R.N.I. No.HIN/2002/8718 www.aksnews.com M.P./BHOPAL/642/2024-26

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

वर्ष : 23 । अंक : 20
16 से 31 जुलाई 2025
पृष्ठ : 48
मूल्य : 25 रु.

विकराल होता जलवायु परिवर्तन का संकट

मैदान से पहाड़ों तक तबाही ही तबाही

मानसून की बारिश में बादल फटने से बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बढ़ा

हर साल हजारों करोड़ रुपए की सरकारी और निजी संपत्ति का नुकसान

M/S NIHAL SUNARE
Consultant

हरियाली बढ़ाएं
आओ... एक पौधा लगाएं

Nariman Point Colony, Indore

इस अंक में

पहल

9 | **पीडब्ल्यूडी इंजीनियरों...**

मप्र में भवन, सड़क, पुल और अन्य परियोजनाओं के निर्माण को बेहतर बनाने पर सरकार का फोकस है। इसके लिए सरकार लोकनिर्माण विभाग के इंजीनियरों की काबिलियत का परीक्षण करवाएगी। जानकारी के...

डायरी

10-11 | **अटकी नहीं...**

मप्र में सरकार का पूरा फोकस सुशासन पर है। सरकार के इस लक्ष्य को मुख्य सचिव अनुराग जैन साकार कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि प्रदेश में केवल सिलेक्टिव पोस्टिंग हो रही है। गौरतलब है कि प्रशासनिक...

मुद्दा

14 | **घुसपैठ बनी नासूर...**

भारत सरकार को साहस जुटाना होगा कि जितने बांग्लादेशी भारत में रह रहे हैं उनके रहने के लिए उसी अनुपात में बांग्लादेश से भूमि मांगे। बांग्लादेश इसके लिए राजी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में हमें सख्ती दिखानी होगी। बात आगे बढ़े तो रंगपुर डिवीजन में...

अपराध

18 | **हथियारों के लाइसेंस...**

मप्र वाकई अजब है, गजब है। यहां कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसा ही एक मामला सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल, प्रदेश में नकली ड्राइविंग लाइसेंस, नकली वोटर कार्ड, नकली आधार कार्ड बनाने के कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन अब हथियारों के...

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

भारत सहित पूरे विश्व में विकास की भूख से जलवायु परिवर्तन का संकट विकराल होता जा रहा है। इस कारण जहां जून-जुलाई में यूरोप में गर्मी का तांडव मचा हुआ है, वहीं भारत में मानसून ने तबाही मचा रखी है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में बादल फटने से बाढ़ और भूस्खलनों में सैकड़ों लोग मारे गए हैं वहीं सरकारी और निजी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा है। दूसरी तरफ मैदानी क्षेत्रों यानि मप्र, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, उप्र, बिहार आदि में बाढ़ से त्राहिमाम की स्थिति बन गई है।

29

35

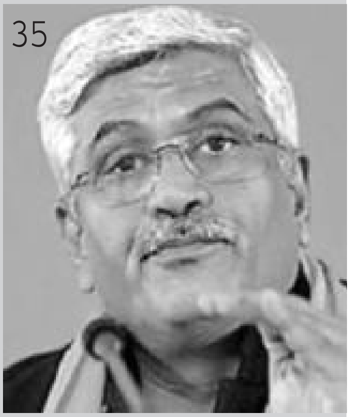

44

45

राजनीति

30-31 | **विपक्ष की भूमिका...**

भारतीय लोकतंत्र को कमजोर करने में उसी कांग्रेस का हाथ नजर आ रहा है जो कभी कांग्रेस का हाथ, आम आदमी के साथ का नारा देती थी और आम आदमी ने तो अपनी नई पार्टी ही बना डाली। किसी लोकतंत्र में जनता के लिए उन्हीं की चुनी सरकार चलाने के बड़े मायने हैं। कभी बहुमत...

महाराष्ट्र

34 | **उद्धव-राज साथ-साथ!**

महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के एक साथ आने से न केवल सत्तारूढ़ महायुति के लिए चुनौती बढ़ी है, बल्कि विपक्षी पार्टियों के गठबंधन महाविकास अघाड़ी के लिए राज-उद्धव का साथ गले की फांस बन सकती है। महाविकास अघाड़ी की सहयोगी पार्टी कांग्रेस और...

बिहार

38 | **बिहार में 20-20 खेल रहे तेजस्वी**

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी तापमान अब पूरी तरह से चढ़ चुका है। भाजपा-जदयू की दोस्ती सत्ता पर अपना वर्चस्व बनाए रखने की कोशिश में है तो राजद-कांग्रेस और वामपंथी दल मिलकर किस्मत आजमा रहे हैं। इंडिया गठबंधन की...

6-7	अंदर की बात
39	पड़ोस
41	विदेश
42	महिला
44	खेल
45	फिल्म
46	व्यंग्य

पाक्षिक अक्स

वर्ष-23, अंक-20, पृष्ठ-48
16 से 31 जुलाई, 2025

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
टेलीफेक्स - 0755-4017788

email : akshmagazine@gmail.com
Website : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2021-23

प्रमुख संवाददाता

भावना सक्सेना-भोपाल, जय मतानी-भोपाल,
हर्ष सक्सेना-भोपाल,
दक्ष दवे-इंदौर, संदीप वर्मा-इंदौर,
विपिन कंधारी-इंदौर, गौरव तिवारी-विदिशा,
ज्योत्सना अनूप यादव-गंजबासौदा, राजेश तिवारी-उज्जैन,
टोनी छाबड़ा-धार, आशीष नेमा-नरसिंहपुर,
अनिल सोडानी-नई दिल्ली, हसमुख जैन-मुंबई,
इंद्र कुमार बिन्नानी-पुणे।

प्रदेश संवाददाता

पारस सरावगी (इंदौर)
09329586555
नवीन रघुवंशी (इंदौर)
09827227000 (इंदौर)
धर्मेन्द्र कथूरिया (जबलपुर)
098276 18400
श्यामसिंह सिकरवार (उज्जैन)
094259 85070
सुभाष सोमानी (रतलाम)
089823 27267
मोहित बंसल (विदिशा)
075666 71111

क्षेत्रीय कार्यालय

नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी, फोन : 9811017939
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान) मोबाइल-09829 010331
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर, भिलाई, मोबाइल 094241 08015
देवास : जय सिंह, देवास मो.-7000526104, 9907353976

स्वात्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

अपनी बात

लचर शिक्षा, अयोग्य बच्चे! जिम्मेदार कौन?

देश के ख्यातनाम शायर गुलजार ने लिखा है...

वो तुम्हें फ्री में बहुत कुछ देंगे, लेकिन शिक्षा नहीं,
क्योंकि उन्हें पता है, शिक्षा ही सवालों को जन्म देती है।

अगर मप्र और देश की वर्तमान सरकारी स्कूली शिक्षा के स्तर को देखें तो शायर की ये पंक्तियां निश्चित रूप से संदेह पैदा करती हैं। क्योंकि देश की सरकारी व्यवस्था पूरी तरह लचर है और उनमें अयोग्य बच्चों की भीड़ है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, यह कोई भी बताने को तैयार नहीं है। हर साल जब भी स्कूली शिक्षा की बदहाली के स्तर को लेकर रिपोर्ट आती है तो सरकारें उसे सुधारने के बड़े-बड़े दावे करती है, लेकिन उन दावों पर कभी अमल नहीं होता है। अगर अमल होता तो यह तस्वीर कभी भी सामने नहीं आती कि कहीं स्कूल नहीं हैं, कहीं शिक्षक नहीं हैं तो कहीं स्कूल का भवन ही नहीं है। ऐसे में भारत का भविष्य कैसे उज्ज्वल होगा। यह बात सभी जानते हैं कि प्राथमिक शिक्षा ही किसी व्यक्ति के जीवन की वह नींव होती है, जिस पर उसके संपूर्णजीवन का भविष्य तय होता है, लेकिन दुख इस बात का है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009, 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी तौर पर लागू है और इस अधिनियम को लागू हुए 15 साल हो गए, लेकिन शिक्षा को लेकर जो हमारा सपना था वो कहीं भी रूप लेता नहीं दिख रहा। हम वहीं खड़े हैं, जहां से चले थे, अगर कुछ बदला है तो वह केवल समय और यही समय आज सवाल पूछ रहा है कि आखिर शिक्षा की दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है? 15 साल होने के बाद भी प्राथमिक शिक्षा अपने हाल पर रो रही है। अगर मप्र की बात करें तो यहां के प्राथमिक और माध्यमिक सरकारी स्कूलों में तकरीबन 1 करोड़ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। इनके लिए सरकार ने तकरीबन 40 हजार करोड़ रुपए का सालाना बजट तय किया है। लेकिन जब बच्चों के ज्ञान का आंकलन किया जाता है तो यह तथ्य सामने आता है कि तीसरी-चौथी के बच्चे को न तो गिनती आती है और न ही पहाड़े। ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार शिक्षकों और अधिकारियों के वेतन पर जो मोटी रकम खर्च करती है उसका फायदा क्यों नहीं पहुंच रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर आंकलन किया जाए तो देश में मप्र की शिक्षा व्यवस्था सबसे बदहाल है। यहां शिक्षकों की कमी सबसे बड़ी समस्या है। यही नहीं जो शिक्षक हैं, वे पढ़ाने की बजाय बाबूगिरी पर अधिक जोर देते हैं। सरकार के तमाम दावों के बावजूद ये व्यवस्था जस की तस है। आखिर प्राथमिक शिक्षा की हालत क्यों खराब है? जब विद्यालयों में शिक्षक ही नहीं होंगे तो बच्चों को पढ़ाएगा कौन और कौन अभिभावक ऐसी स्थिति में अपने बच्चों का यहां दाखिला करवाएगा। गिरते शिक्षा स्तर का प्रमुख कारण शिक्षकों की कमी है। आंकड़े चौंकाने वाले हैं, क्योंकि देश में कहीं-कहीं तो 200 बच्चों पर 1 शिक्षक ही तैनात है और कहीं-कहीं तो पूरा का पूरा विद्यालय अतिथि शिक्षक के सहारे ही चलता है। प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षा की बद से बदतर हालत के लिए कुछ हद तक हमारा समाज भी जिम्मेदार है। इसे दुर्भाग्य ही कहेंगे कि देश के अधिकतर अभिभावक मौजूदा दौर को देखते हुए अपने बच्चों को तो अंग्रेजी माध्यम या फिर मिशनरी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ठीक इसके विपरीत अभिभावक स्वयं प्राथमिक स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। इसके पीछे कारण है, क्योंकि प्राथमिक स्कूल में पढ़ाई के अलावा और सभी कार्य होते हैं और आप दबाव वाले हैं तो घर बैठकर सरकारी पैसों पर मौज कर सकते हैं। बच्चों को वे यहां इसलिए नहीं पढ़ाते क्योंकि यहां पढ़ाई न के बराबर होती है। प्राथमिक शिक्षा की गिरती साख का ही परिणाम है कि शिक्षा का निजीकरण हो रहा है। इसका परिणाम है कि सरकारी स्कूली शिक्षा व्यवस्था दिन पर दिन बदहाल होती जा रही है।

- राजेन्द्र आगाल

भारत की रफ्तार

भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। 2019 में भारत ने ब्रिटेन को पछाड़कर पांचवां स्थान प्राप्त किया और अब जापान को पीछे छोड़ते हुए चौथे स्थान पर पहुंचने को है। आईएमएफ और विश्व बैंक, दोनों ने इसकी पुष्टि की है। इसी गति से भारत अमेरिका और चीन को भी एक दिन पछाड़ देगा।

● **विष्णु वर्मा,** रायसेन (म.प्र.)

सख्ती बरते प्रशासन

राजधानी भोपाल सहित प्रदेशभर में एमआरपी से अधिक कीमत पर शराब बेची जा रही है। प्रदेशभर में एमआरपी से अधिक कीमत पर शराब बेचने वाले लाइसेंसी ठेकेदारों के खिलाफ आबकारी विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। शासन-प्रशासन को इनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए।

● **हरीश कुमार,** गुना (म.प्र.)

नया मॉडल अपनाए कांग्रेस

मप्र में सिर्फ 15 महीनों को छोड़कर पिछले 20 सालों से कांग्रेस सत्ता से बाहर रही है। पार्टी लगातार चुनाव हार रही है। 2020 में हुए दलबदल के बाद कई क्षेत्रों में कांग्रेस का संगठन बेहद नाजुक स्थिति में हैं। अब कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने के नए मॉडल पर काम करना चाहिए।

● **प्रहलाद सिंह,** भिंड (म.प्र.)

परमाणु रक्षक या भक्षक?

आज विश्व उसी दहलीज पर खड़ा है, जहां परमाणु महत्वाकांक्षाएं, हाइब्रिड युद्ध की रणनीतियां और सभ्यताओं का टकराव मानवता के भविष्य को चुनौती दे रहा है। हर राष्ट्र ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए हथियारों का विशाल भंडार एकत्रित कर लिया है, परंतु शक्ति का यह संतुलन अब पूर्णतः बिखर चुका है। विश्व के 9 देशों–रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल व उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार हैं। वहीं ईरान भी इसकी तैयारी कर रहा है। इन सभी से ये सवाल उठ रहा है कि परमाणु बम रक्षक के रूप में काम करेगा या भक्षक के रूप में।

● **नीलम पुरोहित,** बैतूल (म.प्र.)

पाकिस्तान की तस्वीर उजागर

ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान दुनिया से सहानुभूति बटोरने के लिए जहां विश्व समुदाय में अनेक भ्रम, भ्रांतिया एवं भारत की छवि को छिछालेदार करने में जुटा है, वहीं भारत का डर दिखा-दिखा कर ही पाक अनेक देशों से आर्थिक मदद मांग रहा है। इन्हीं स्थितियों को देखते हुए दुनिया के सामने भारत का पक्ष रखने के लिए केंद्र सरकार ने जिस तरह से सात सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों को विदेशों में पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए भेजा था। उन नेताओं ने जिस तरह भारत की बात रखी, उससे देश की राजनीति को नई दिशा मिली है। इससे न सिर्फ पाकिस्तान की काली करतूत दुनिया के सामने उजागर हुई, बल्कि भारत की छवि भी दुनियाभर में चमकी है।

● **अभिषेक सूर्यवंशी,** पन्ना (म.प्र.)

मोदी सरकार का बज रहा डंका

मोदी सरकार का लक्ष्य भारत को दुनिया की एक ताकतवर आर्थिक महाशक्ति बनाने का है, जिसके लिए वह निरंतर कार्य कर रही है और उन कार्यों के दम से ही भारत आज विश्व में चौथे पायदान पर आ चुका है। देश की आंतरिक व बाह्य सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए मोदी सरकार ने बहुत काम किया है, मोदी सरकार ने देश के कुछ हिस्सों में दशकों से बेखौफ होकर के अपना राज चला रहे नक्सलियों की कमर तोड़ने का कार्य किया, जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद पर लगाम लगाने का कार्य किया है। इससे मोदी सरकार का देशभर में डंका बज रहा है।

● **पिंकी यादव,** इंदौर (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल

कोई तो चीन से भिड़ा!

चीन को तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी लाल आंख नहीं दिखा पाते हैं। उन्होंने एक बार लाल आंख दिखाई तो फिर फटाफट उसके साथ समझौता भी कर लिया। केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तब गुजरात का मुख्यमंत्री रहते नरेंद्र मोदी बार-बार केंद्र सरकार को ललकारते थे कि वह चीन को लाल आंख दिखाए। लेकिन खुद प्रधानमंत्री बने तो गलवान घाटी जैसी घटना के बाद भी चीन को लाल आंख नहीं दिखाई। लेकिन अब यह हिम्मत अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने दिखाई है। पेमा खांडू ने चीन को लेकर वह कहा है, जो कहने की हिम्मत भारत का नेता पिछले 60 साल से नहीं कर रहे थे। खांडू ने कहा है कि भारत की सीमा तिब्बत से मिलती है, चीन से नहीं। यह सीधे चीन की अखंडता और उसकी संप्रभुता को चुनौती है। तभी खांडू के साहस को सैल्यूट किया जाना चाहिए। अब सवाल है कि क्या खांडू ने अपनी तरफ से यह बयान दिया कि उनका बयान भारत के विदेश मंत्रालय से मंजूर हुआ है? क्योंकि यह बहुत बड़ा बयान है। पहली बार किसी ने तिब्बत पर चीन के अवैध कब्जे पर खुलकर बयान दिया है। अब तो दलाई लामा भी इस बारे में सोच समझकर बोलते हैं। लेकिन कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे दोरजी खांडू के बेटे, जो अब भाजपा में हैं, ने सीधे चीन को चुनौती दी है।

50 करोड़ बनाम 60 लाख का टेंडर

खबर आई है कि दिल्ली पीडब्ल्यूडी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बंगले की साज-सज्जा के लिए निकाला गया टेंडर रद्द कर दिया है। यह टेंडर उनको आवंटित दो बंगलों के रेनोवेशन के लिए निकाला गया है। गौरतलब है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री को राजनिवास मार्ग पर अगल-बगल के दो बंगले आवंटित हुए हैं, जिनमें पिछले दिनों पूजा हुई। मुख्यमंत्री ने एक बंगले को जनसेवा सदन बनाने का ऐलान किया है, जहां उनका कैम्प ऑफिस होगा और दूसरा उनका निवास होगा। वे अभी शालीमार बाग के अपने घर में रहती हैं। नए बंगले की पूजा के समय उपराज्यपाल वीके सक्सेना भी मौजूद थे। सोचें, इतनी योजना के साथ घर की पूजा हुई, दशहरा तक उसमें शिफ्ट करने की योजना बनी और टेंडर रद्द हो गया। यह हैरान करने वाली बात इसलिए है क्योंकि सोशल मीडिया में भाजपा के अपने लोगों ने ऐसा माहौल बना दिया, जैसे 60 लाख रुपए खर्च करके बंगले का रेनोवेशन कराना कोई अपराध है। कहां अरविंद केजरीवाल ने अपने रहने के लिए बंगले पर 50 करोड़ रुपए खर्च कर दिए और कहां भाजपा की सरकार उसका एक फीसदी भी खर्च करने में डर गई! यह प्रचार शुरू कर दिया कि भाजपा ने केजरीवाल के शीशमहल का प्रचार करके चुनाव लड़ा और खुद मुख्यमंत्री के लिए शीशमहल बना रही है।

बंद से बनी विपक्ष की एकजुटता

बिहार में विपक्षी पार्टियां बिखरी हुई दिख रही थीं। कांग्रेस पार्टी के सारे कार्यक्रम अकेले हो रहे थे। इस साल के पहले छह महीने में राहुल गांधी पांच बार बिहार दौरे पर पहुंचे और हर बार उनका कार्यक्रम अकेले हुआ। उसमें राजद या कम्युनिस्ट पार्टियों को नहीं शामिल किया गया। पहली बार एक साझा कार्यक्रम हुआ। बिहार में चुनाव आयोग की ओर से कराए जा रहे मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के खिलाफ सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर सड़क पर उतरी। अब तक अलग राजनीति कर रहे कम्युनिस्ट पार्टियों के नेता भी राजद और कांग्रेस के साथ मंच पर आए। इतना ही नहीं विकासशील इंसान पार्टी के नेता मुकेश सहनी भी विपक्ष के साथ सड़क पर उतरे, जिनके बारे में कई तरह की चर्चाएं चल रही थीं और कहा जा रहा था कि वे भारतीय जनता पार्टी के भी संपर्क में हैं। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य और मुकेश सहनी के एक साथ खुली जीप में पटना की सड़कों पर निकलने से एक बहुत पावरफुल तस्वीर बनी है। विपक्षी पार्टियां इसके लिए चुनाव आयोग को धन्यवाद दे रही हैं कि उसने सबको एकजुट कर दिया और बिहार की जनता को भी मैसेज पहुंचा दिया कि कुछ गड़बड़ हो रही है, जिसके विरोध में सभी विपक्षी पार्टियां सड़क पर उतरी हैं।

पप्पू-कन्हैया से कौन डरता है?

यह लाख टके का सवाल है कि आखिर बिहार में कांग्रेस और राजद के अंदर कौन लोग हैं, जिनको पप्पू यादव और कन्हैया कुमार से डर लगता है? गत दिनों पटना की सड़कों पर विपक्षी गठबंधन ने प्रदर्शन किया। प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में ट्रेनें रोकी गईं और सड़कों पर परिवहन को रोका गया। पटना में सबसे ज्यादा भीड़ जुटाई पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने। उन्होंने प्रदर्शन के पूरे रास्ते को कांग्रेस के झंडे से पाट दिया। राजद के लोग भी हैरान थे कि इतने कांग्रेसी कहां से आ गए, जो झंडा लेकर पटना की सड़कों पर निकले हैं। यह पप्पू यादव का करिश्मा था। लेकिन उनको न तो खुली जीप में चढ़ने दिया गया और न सभा की जगह पर मंच पर जगह दी गई। उलटे जब वे राहुल गांधी और तेजस्वी के नजदीक जाने की कोशिश कर रहे थे तो उनको धक्के मारकर गिरा दिया गया। कमोबेश ऐसा ही हाल कन्हैया कुमार का भी रहा। पिछले दिनों उन्होंने बिहार में नौकरी दो पलायन रोको यात्रा निकाली थी और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने पहुंचे थे।

थरूर का बड़ा हमला

कांग्रेस के सांसद शशि थरूर की अपनी पार्टी से दूरी बढ़ती जा रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने और केंद्र सरकार के डेलिगेशन की अगुवाई करने के बाद अब अपनी ही पार्टी पर तीखा हमला किया है। उन्होंने इमरजेंसी को भारत के इतिहास का एक काला अध्याय बताया है। इमरजेंसी के समय जबरदस्ती नसबंदी कराए जाने को थरूर ने क्रूरता की मिसाल बताया है। तिरूवनंतपुरम के सांसद शशि थरूर ने एक लेख में लिखा है कि इमरजेंसी को सिर्फ भारतीय इतिहास के काले अध्याय के रूप में याद नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इससे सबक लेना जरूरी है। उन्होंने नसबंदी अभियान को मनमाना और क्रूर फैसला बताया। मलयालम भाषा के अखबार दीपिका में प्रकाशित लेख में थरूर ने लिखा है कि अनुशासन और व्यवस्था के लिए उठाए गए कदम कई बार ऐसी क्रूरता में बदल जाते हैं, जिन्हें किसी तरह उचित नहीं कहा जा सकता। थरूर ने लेख में लिखा कि लोकतंत्र को हल्के में नहीं लेना चाहिए।

इनसे सीखिए संबंध बनाना

प्रदेश में कई नौकरशाह ऐसे होते हैं, जिन्हें मैनेजमेंट का धनी माना जाता है। ये मैनेजमेंट में इतने माहिर होते हैं कि सख्त से सख्त व्यक्ति को भी अपने सांचे में ढाल लेते हैं। ऐसे ही एक आईएएस अधिकारी इन दिनों चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। दरअसल, साहब वरिष्ठता के साथ ही अपने संबंध मजबूत करने में भी माहिर होते जा रहे हैं। इसकी मिसाल यह है कि प्रदेश में 2018 के समय जो प्रशासनिक मुखिया थे, साहब की उनसे भी खूब छनती थी। इन साहब ने उन्हें भी साध रखा था और दोनों के संबंध उनके रिटायर होने तक मधुर रहे। अब इन साहब की वर्तमान प्रशासनिक मुखिया से भी खूब पट रही है। इस कारण प्रशासनिक जमावट में भी उनका हस्तक्षेप बढ़ रहा है। साहब के संबंध बनाने के इस गुर को देखकर उनके साथी यह कहने से नहीं चूकते हैं कि अगर संबंध बनाना है तो इनसे सीखिए। यहां बता दें कि जिन साहब की बात हो रही है, वे 1993 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। ये साहब इस समय बड़े साहब की गुड बुक में सबसे ऊपर हैं। सूत्रों का कहना है कि उनकी और वर्तमान प्रशासनिक मुखिया के घनिष्ठ संबंधों का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि दोनों का ठिकाना एक ही जगह बन रहा है और दोनों के आर्किटेक्ट और इंजीनियर भी एक ही हैं। अभी हाल ही में साहब को एक बड़े विभाग की जिम्मेदारी भी मिली है।

मांगा जाएगा स्पष्टीकरण

प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में अक्सर अफसरों का महिला प्रेम चर्चा का केंद्र बना रहता है। लेकिन कुछ अफसर ऐसे होते हैं, जो महिला प्रेम में आरपार करने की स्थिति में आ जाते हैं। ऐसे ही अफसरों में 2014 बैच के एक आईपीएस अधिकारी का भी नाम शामिल है। साहब जब महाकौशल क्षेत्र के एक जिले में कप्तानी कर रहे थे तो तथाकथित तौर पर एक महिला पुलिस अधिकारी से उनकी नजदीकी बढ़ी और विवादों में फंस गई। खुद उक्त महिला पुलिस अधिकारी के पति ने मोर्चा खोला और साहब के खिलाफ लिखित शिकायतों की भरमार लगा दी। काफी विवाद के बाद सरकार ने इस मामले को संज्ञान में लिया और पहले उक्त महिला पुलिस अधिकारी को जिले से रवाना

किया, फिर साहब को भी वहां से हटा दिया। सूत्र बताते हैं कि उक्त महिला पुलिस अधिकारी का पति अभी भी वॉट्सएप के माध्यम से शिकायतें कर रहा है। जिसको लेकर प्रशासन में हलचल मची रहती है। सूत्रों का कहना है कि सरकार अभी भी इस मामले की गंभीरता को समझ रही है और बताया जा रहा है कि जल्द ही साहब से इस संदर्भ में स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है।

अपने ही जाल में फंस गई मैडम

विंध्य क्षेत्र के एक जिले में पदस्थ एक महिला आईएएस अधिकारी अपने ही बुने जाल में इस कदर फंस गई हैं कि कभी भी उन पर सरकारी गाज गिर सकती है। दरअसल, मैडम जिले में कलेक्टर हैं और उन्होंने नियमों के विपरीत जाकर 20 एकड़ भूमि का नामांतरण करवा दिया है। बताया जाता है कि जैसे ही यह मामला स्थानीय सांसद के पास पहुंचा तो उन्होंने इस संदर्भ में कलेक्टर से बात की, तो उन्होंने आव देखा न ताव सांसद महोदय से कह दिया कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। जो कुछ भी हुआ है, ऊपर से फोन आने के बाद हुआ है। सूत्र बताते हैं कि सांसद महोदय भी कहां रुकने वाले थे। उन्होंने भी इस मसले को लेकर ऊपर बात की तो पता लगा कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। बताया जाता है कि इस नामांतरण के खेल में एक विधायक का भी हस्तक्षेप है। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि जिस 20 एकड़ जमीन का नामांतरण कराया गया है, उसका असली मालिक 2013 में ही दिवंगत हो गया है। अब इस मामले में ईओडब्ल्यू में भी एफआईआर दर्ज हो गई है। सूत्र बताते हैं कि जिस तरह कलेक्टर मैडम ने नियमों के विपरीत जाकर नामांतरण करवाया है, उससे सरकार की छवि पर भी असर पड़ा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि जल्द ही मैडम के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है। यहां बता दें कि मैडम 2012 बैच की आईएएस अधिकारी हैं।

विशेष सहायक ने बना ली सीडी

कभी-कभी अपने प्रिय भी गले ही हड्डी बन जाते हैं, जिसे न निगल सकते हैं न उगल सकते हैं। ऐसे ही एक गले की हड्डी के चक्कर में एक मंत्रीजी इस कदर फंस गए हैं कि वे उसे अपने से दूर नहीं होने देना चाहते हैं। जिन मंत्रीजी की यहां बात हो रही है, वे मालवा-निमाड़ क्षेत्र के एक धार्मिक जिले के प्रभारी मंत्री हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मंत्रीजी ने अपने पास अपनी पसंद के एक अधिकारी को विशेष सहायक के रूप में रखवाया था। उस विशेष सहायक ने मंत्रीजी को अपने चंगुल में फंसाने के लिए उनके लाड़ले की एक सीडी बना ली। इससे मंत्रीजी परेशान हो गए। इस बीच विभागीय सचिव ने उक्त विशेष सहायक की पदस्थापना दूसरी जगह कर दी। जिससे मंत्रीजी इस कदर परेशान हो उठे कि उन्होंने सचिव से मिन्नतें करनी शुरू कर दीं कि मेरा उक्त विशेष सहायक बहुत अच्छा काम कर रहा था, इसलिए उसे दूसरी जगह न भेजा जाए। बताया जाता है कि मंत्रीजी की गुहार पर सचिव ने उनके विशेष सहायक का तबादला निरस्त कर दिया। दरअसल, मंत्री को डर है कि सीडी कहीं लीक न हो जाए।

एसपी के आगे बेबस आईजी

कभी-कभी वरिष्ठ नौकरशाहों की अपने कनिष्ठों के सामने तनिक भी नहीं चलती है। ऐसा ही इन दिनों मप्र की लाइफलाइन कहे जाने वाली नदी वाले संभाग में देखने को मिल रहा है। सूत्रों का कहना है कि संभाग के बड़े पुलिस अधिकारी को यहां पदस्थ हुए करीब 8 महीने हो गए, लेकिन आज भी जिलों के एसपी उनकी तनिक भी नहीं सुनते हैं। जब इसकी पड़ताल की गई तो पता चला कि कई पुलिस अधीक्षक ऐसे हैं जो वर्षों से जिलों में कुंडली मारकर बैठे हैं। इनमें से कुछ को राजनीतिक संरक्षण भी मिला हुआ है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि संभाग की बड़ी कुर्सी पर बैठे आईपीएस अधिकारी जब कभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को कोई निर्देश देते हैं तो उनमें से अधिकांश उसे नजरअंदाज कर देते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि हरदा में करणी सेना ने जो उत्पात मचाया था, उसकी भनक तक इनको नहीं लग पाई। यहां बता दें कि 2006 बैच के उक्त आईपीएस अधिकारी यहां पदस्थापना से पहले गुंडे-बदमाश और डकैतों के लिए कुख्यात रहे संभाग में पदस्थ थे और वहां उनका जमकर सिक्का चलता था। लेकिन यहां आने के बाद से वे बेबस हो गए हैं।

मप्र भाजपा की नई कार्यकारिणी में होंगे नए चेहरे

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के बाद नई प्रदेश कार्यकारिणी के गठन पर मंथन शुरू हो गया है। जिसको लेकर नेताओं ने लॉबिंग शुरू कर दी है। जानकारों का कहना है कि भाजपा की नई कार्यकारिणी में अधिकांश नए चेहरों को जगह दी जाएगी। कार्यकारिणी में सांसदों और विधायकों की संख्या सीमित रखी जाएगी। दरअसल, पार्टी नया नेतृत्व तैयार करना चाहती है। इसके लिए प्रदेश कार्यकारिणी में नए नेताओं को जगह दी जाएगी। कहा जा रहा है कि जल्द ही नई कार्यकारिणी का खाका तैयार किया जाएगा और पार्टी हाईकमान की मंजूरी के बाद अगले माह कार्यकारिणी की घोषणा कर दी जाएगी।

गौरतलब है कि मप्र भाजपा को लंबे इंतजार के बाद नया अध्यक्ष मिल गया है। अब जल्द ही प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी में भी बदलाव होगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल अगले कुछ दिनों में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मिलने दिल्ली जा सकते हैं। इसके बाद प्रदेश भाजपा की नई कार्यकारिणी का गठन होगा। मोर्चा अध्यक्षों को भी बदला जाएगा। प्रदेश भाजपा की नई कार्यकारिणी में इस बार सांसद और विधायकों की संख्या घट सकती है। भाजपा सूत्रों की मानें तो इस बार भाजपा के सदस्यता अभियान में अहम जिम्मेदारी निभाने वाले भाजपा नेता और पुराने कार्यकर्ताओं को कार्यकारिणी में स्थान दिया जाएगा। भाजपा ने सदस्यता अभियान का पूरा डेटा तैयार किया है। इस डेटा के हिसाब से सदस्यता अभियान में जुटे नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।

पार्टी का पूरा फोकस संगठन की मजबूती पर है। इसके लिए कार्यकारिणी में पार्टी के सीनियर और अनुभवी नेताओं को शामिल करके फेरबदल किया जाएगा। इस बार युवा और नए चेहरों को भी कार्यकारिणी में जगह मिलने की संभावना है जिनकी कार्यप्रणाली से पार्टी खुश है। जबकि पहले रहे कुछ पदाधिकारियों की छुट्टी होना भी तय माना जा रहा है। गौरतलब है कि प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति से पहले जिला अध्यक्षों का चुनाव हो चुका है। इस बार पार्टी ने सभी जिला अध्यक्ष के लिए नए चेहरों को मौका दिया है। इसलिए ही कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रदेश कार्यकारिणी में भी ऐसा देखा जा सकता है। जबकि पूर्व जिला अध्यक्षों को भी पार्टी ने अभी नई जिम्मेवारी नहीं दी है। इसके अलावा कई और नेता भी हैं जो कि नए रोल का इंतजार कर रहे हैं। भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी में वर्तमान में प्रदेश उपाध्यक्ष 15, प्रदेश महामंत्री 5, प्रदेश मंत्री 14, प्रदेश प्रवक्ता 19, पैनलिस्ट 5, मोर्चा अध्यक्ष 7, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य 203, स्थाई आमंत्रित सदस्य 22 और विशेष आमंत्रित सदस्य 237 हैं। इस तरह नई कार्यकारिणी का स्वरूप भी ऐसा ही होगा। इस बार कार्यकारिणी में सांसदों और विधायकों की संख्या सीमित रखने की बात हो रही है। अभी भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी में 15 प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। इनमें सांसद संध्या राय, राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मिक, आलोक शर्मा शामिल हैं। इसके अलावा पूर्व विधायक चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी, जीतू जिराती, बहादुर सिंह चौहान, बृजराज सिंह चौहान और वर्तमान विधायक चिंतामणि मालवीय, ललिता यादव शामिल हैं। वहीं कार्यकारिणी में अभी 5 महामंत्री हैं, जिनमें रणवीर सिंह रावत, खरगापुर से विधायक और पूर्व मंत्री हरिशंकर खटीक, पूर्व विधायक सरदेंदु तिवारी, वर्तमान विधायक भगवानदास सबनानी और राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार शामिल हैं। इसके अलावा कार्यकारिणी में 14 प्रदेश मंत्री हैं। इसमें भाजपा के पुराने कार्यकर्ता और पूर्व विधायक शामिल हैं। इनमें से कार्यकारिणी के 60 फीसदी पदाधिकारियों को बदला जा सकता है। इनके स्थान पर नए विधायकों और भाजपा के कार्यकर्ताओं को नई कार्यकारिणी में स्थान मिलेगा।

प्रदेश कार्यकारिणी को संतुलित बनाया जाएगा। इसके लिए हमेशा की तरह इस बार भी प्रदेश कार्यकारिणी में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन का ख्याल रखा जाएगा। इसके अलावा दूसरा मसला उम्र के क्राइटेरिया का है। भाजपा भले ही कहे कि उसने पदाधिकारियों के लिए उम्र का कोई क्राइटेरिया तय नहीं किया है पर जिलाध्यक्षों के चयन में अधिकांश जिलों में 60 साल के कम उम्र के कार्यकर्ताओं को ही वरीयता दी गई है। प्रदेश कार्यकारिणी में प्रमुख पदों पर भी युवाओं का भी प्रतिनिधित्व रहे, इसका ख्याल रखा जाएगा। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस से कई बड़े-छोटे नेताओं ने भाजपा का दामन थामा था। इनमें कुछ तो पार्टी में घुल-मिल गए, तो कुछ अभी भी अलग-थलग हैं। कोई दायित्व नहीं मिलने पर वे उलझन में हैं। पुराने भाजपाई उन्हें आज भी स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। कारण, उनके आने से भाजपा के कई नेता हाशिए पर आ गए। ऐसे में पुराने नेताओं को साधे रखने और कांग्रेस से आने वालों की अपेक्षाओं का भी ध्यान रखा जाएगा। इन्हें प्रदेश कार्यकारिणी से लेकर मोर्चा, प्रकोष्ठों में एडजस्ट किया जा सकता है।

● **प्रवीण सक्सेना**

गाइडलाइन के अनुसार ही बनेगी जिला कार्यकारिणी

नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद अब जिलों की कार्यकारिणी का गठन नई गाइडलाइन के अनुसार ही होगा। जिला स्तर पर कार्यकारिणी में 40 फीसदी पदाधिकारी नए नियुक्त किए जाएंगे। एससी, एसटी महिलाओं को भी टीम में जगह दी जाएगी। मप्र में भाजपा की जिला अध्यक्षों का चयन 5 महीने पहले हो चुका है। इसके बाद से जिलों की कार्यकारिणी का भी गठन अब तक नहीं हो सका है। दरअसल भाजपा के नए अध्यक्ष का चयन न हो पाने से जिलों की कार्यकारिणी का गठन अटका हुआ था। नए प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल मप्र के जिलों की कार्यकारिणी का भी गठन करेंगे। इससे पहले जिलों की कार्यकारिणी की गाइडलाइन तय की जाएगी। अब तक जिलों की कार्यकारिणी की गाइडलाइन तय नहीं हो पाई है। जिलों की कार्यकारिणी में मंडल स्तर तक काम करने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं को स्थान दिया जाएगा।

पीडब्ल्यूडी इंजीनियरों की होगी परीक्षा

मप्र में भवन, सड़क, पुल और अन्य परियोजनाओं के निर्माण को बेहतर बनाने पर सरकार का फोकस है। इसके लिए सरकार लोकनिर्माण विभाग के इंजीनियरों की काबिलियत का परीक्षण करवाएगी।

जानकारी के अनुसार सरकार के पैमाने पर खरा उतरने के लिए पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों को मूल्याकंन परीक्षा देनी होगी। यह परीक्षा उनके ज्ञान और कौशल का मूल्यांकन करने के लिए आयोजित की जाती है, और यह सुनिश्चित करती है कि वे अपने काम के लिए योग्य हैं।

गौरतलब है कि प्रदेश में लोक निर्माण विभाग द्वारा बनवाई गई सड़कों की गुणवत्ता को लेकर बराबर सवाल उठते रहते हैं। ऐसे में पीडब्ल्यूडी ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए अपने अधीनस्थ इंजीनियरों के लिए निर्माण संबंधी कोड और मानकों को याद करना अनिवार्य कर दिया है। विभाग ने निर्देश जारी कर स्पष्ट किया कि विभाग के सभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और उनसे नीचे के इंजीनियरों को निर्माण कोड्स का पूरा ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए जल्द ही मूल्यांकन परीक्षा भी होगी। इस परीक्षा में उन कोड्स और मानकों को शामिल किया जाएगा जो भवन, सड़क, पुल व अन्य परियोजनाओं में लागू होते हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में पीडब्ल्यूडी सबसे बड़ी सरकारी निर्माण एजेंसी है। पीडब्ल्यूडी के अधीन कुल 80,775 किमी सड़क नेटवर्क है। जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग 9,315 किमी, मुख्य जिला मार्ग 25,639 किमी, राज्य राजमार्ग 11,389 किमी और अन्य जिला मार्ग 34,432 किमी है।

दरअसल, वरिष्ठ आईएएस सुखवीर सिंह को हाल में लोक निर्माण विभाग का प्रमुख सचिव पदस्थ किया गया है। उन्होंने पदभार ग्रहण करते ही विभागीय अमले की कसावट शुरू कर दी है। उन्होंने विभाग के अंतर्गत चल रहे सभी भवन, सड़क और ब्रिज निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, टिकाऊपन एवं सुरक्षा मानकों को और अधिक सुदृढ़ एवं पारदर्शी बनाने के लिए विभाग में कार्यरत सभी इंजीनियरों को भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी), नेशनल बिल्डिंग कोड (एनबीसी) और संबंधित भारतीय मानक (आईएस) कोड्स के अनुसार कार्यों का क्रियान्वयन करने को कहा है। जारी निर्देशों में परीक्षा लेने संबंधी बिंदु से विभाग के प्रदेशभर के इंजीनियरों में हड़कंप मच गया है। प्रमुख सचिव सिंह ने प्रमुख अभियंता लोक निर्माण, प्रमुख अभियंता (भवन), प्रबंध संचालक मप्र सड़क विकास निगम और प्रबंध संचालक मप्र भवन विकास निगम को पत्र लिखकर जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। पत्र में अधोसंरचना निर्माण कार्यों में उपयोग होने वाले आईआरसी, एनबीसी और आईएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कोड्स की सूची भी संलग्न की गई है। इन कोड्स के अनुसार निर्माण कार्य करने को कहा गया है।

रिटायर्ड अफसरों को संविदा पर रखेगा एनएचएआई

मप्र में राजमार्ग परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने रिटायर्ड अफसरों को संविदा पर रखकर उनकी सेवाएं लेने जा रहा है। संविदा पर रखे गए अधिकारी सड़कों के लिए भूमि अधिग्रहण और कब्जा दिलाएंगे। जानकारी के अनुसार केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने मप्र में राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़कों के निर्माण में तेजी लाने और भूमि अधिग्रहण में होने वाली देरी को गंभीरता से लिया है। इसके लिए राजस्व विभाग के रिटायर्ड राजस्व अधिकारियों की सेवा लेने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद अब प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़कों के लिए निजी भूमि अधिग्रहण को लेकर सरकार रिटायर्ड अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, पटवारी की नियुक्ति करेगी। बताया जा रहा है कि राजस्व विभाग के कामकाज में राष्ट्रीय राजमार्ग के इंजीनियरों को भूमि अर्जन संबंधी कामों में होने वाली दिक्कतों के मद्देनजर त्वरित कार्रवाई के लिए यह नियुक्तियां की जा रही हैं। आवेदनकर्ता रिटायर्ड अफसर की उम्र एक जुलाई को 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। रिटायर्ड रेवेन्यू अफसर को चयनित किए जाने पर पदस्थापना उसी शहर में दिए जाने को प्राथमिकता दी जाएगी। जिस शहर में वे रह रहे हैं। रिटायर्ड रेवेन्यू ऑफिसर्स को भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के 2016 के सर्कुलर के आधार पर वेतन भत्तों का लाभ दिया जाएगा। अधिकारियों को अंतिम वेतन एवं पेंशन भुगतान के अंतर की राशि का भुगतान वेतन के रूप में किया जाएगा। उन्हें किसी प्रकार के भत्तों की पात्रता नहीं होगी।

वर्तमान में पीडब्ल्यूडी के 22,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसमें 10,000 किमी सड़कों एवं 10,463 करोड़ रुपए से 474 पुलों और फ्लाई ओवरों पर कार्य प्रगति पर है। साथ ही नर्मदा प्रगतिपथ, विंध्य एक्सप्रेस-वे, मालवा-निमाड़ कॉरिडोर, अटल प्रगतिपथ, बुंदेलखंड और मध्य भारत विकास पथ जैसी 6 प्रमुख परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जो प्रदेश के पिछड़े अंचलों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ेंगी।

प्रमुख सचिव सिंह ने अपने पत्र में कहा है कि विभाग में कार्यरत सभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एवं उनसे नीचे के स्तर के इंजीनियरों को निर्देशित किया जाता है कि वे 15 अगस्त तक संबंधित कोड्स का अध्ययन सुनिश्चित कर भविष्य में निर्माण कार्य में उपयोग करें। इसके बाद एक मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन मोड में आयोजित की जा सकती है। परीक्षा का उद्देश्य अभियंताओं की तकनीकी ज्ञान क्षमता, व्यावहारिक क्रियान्वयन योग्यता एवं गुणवत्ता नियंत्रण में सुधार की क्षमता का समुचित मूल्यांकन करना है। परीक्षा के प्राप्तांक विभागीय डेटाबेस में संधारित किए जाएंगे और उनका उपयोग वार्षिक मूल्यांकन, प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान, जिम्मेदारी वितरण एवं विशेष परियोजनाओं के आवंटन जैसे महत्वपूर्ण संदभों में किया जाएगा। इस उद्देश्य हेतु विभागीय पोर्टल पर अध्ययन के लिए जरूरी दिशा-निर्देश एवं संदर्भ कोड सूची जल्द उपलब्ध कराई जाएगी। चूंकि यह प्रक्रिया विभागीय नीति का अभिन्न अंग है, अत: सभी विभागीय मुख्य अभियंता, अधीक्षण यंत्री भी अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित सभी महत्वपूर्ण कोड्स का अध्ययन करेंगे एवं इस परिपत्र का परिपालन सुनिश्चित करने हेतु अपने अधीनस्थ अभियंताओं को जरूरी जानकारी प्रदान करेंगे एवं कार्यों को गुणवत्तापूर्वक करने के लिए प्रेरित करेंगे।

● विकास दुबे

...अटकी नहीं सिलेक्टिव पोस्टिंग

मप्र में सरकार का पूरा फोकस सुशासन पर है। सरकार के इस लक्ष्य को मुख्य सचिव अनुराग जैन साकार कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि प्रदेश में केवल सिलेक्टिव पोस्टिंग हो रही है। गौरतलब है कि प्रशासनिक व्यवस्था में काम करने वाले अधिकारी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार आज नहीं तो कल तबादले की बड़ी सूची जारी करेगी। लेकिन पिछले 6 महीने से बड़ी सूची तो जारी नहीं हुई है, लेकिन अफसरों के तबादले निरंतर हो रहे हैं। जहां जरूरत है, वहां सरकार अफसरों की नई पदस्थापना कर रही है। इसकी वजह यह है कि तबादले करने से सरकार की साख पर दाग लगते हैं। इसलिए शासन और प्रशासन के मुखिया की अभी तक यही कोशिश रही है कि केवल जरूरत के हिसाब से ही तबादले किए जाएं।

सूत्रों का कहना है कि मुख्य सचिव अनुराग जैन दिल्ली दरबार से मप्र भेजे गए हैं। इसलिए उन्हें यह समझाइश देकर भेजा गया है कि प्रदेश में अंधाधुंध तबादलों से बचकर काम करें। अगर सरकार थोकबंद तबादले करेगी तो विपक्ष भी हमलावर हो जाएगा और इसमें भ्रष्टाचार का आरोप लगने लगेगा। इसलिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और मुख्य सचिव अनुराग जैन तबादलों के पक्ष में नहीं हैं। जबसे अनुराग जैन मुख्य सचिव बनकर आए हैं, तब से यह देखने को मिला है कि केवल जरूरत के हिसाब से तबादले किए जा रहे हैं। दरअसल, तबादले होने से काम भी प्रभावित होता है। लेकिन अफसर इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं और थोकबंद तबादलों के इंतजार में हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं।

संजय दुबे को बड़ी जिम्मेदारी

अभी हाल ही में राज्य सरकार ने प्रशासनिक सर्जरी करते हुए वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के बड़े स्तर पर तबादले किए। संजय दुबे को नगरीय प्रशासन विभाग की कमान सौंपी गई है। यह विभाग इस समय बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शहरी विकास, मेट्रो परियोजनाएं, स्मार्ट सिटी जैसे बड़े प्रोजेक्ट प्रदेश में चल रहे हैं। वहीं राजेश राजौरा को एसीएस, नर्मदा घाटी विकास विभाग, निशांत वरवड़े को सचिव, कृषि विभाग मिला है। वहीं, लंबे समय से लूपलाइन में माने जा रहे डीपी आहूजा को अब महत्वपूर्ण सहकारिता विभाग का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है। प्रबल सिपाहा, जो करीब साढ़े तीन साल से लोक सेवा आयोग के सचिव के रूप में कार्यरत थे, अब आयुक्त, उच्च शिक्षा बनाए गए हैं। वहीं, एम सेलवेंद्रन, जो अब तक प्रभारी सचिव (कार्मिक) थे, को उनके प्रदर्शन को देखते हुए सचिव किसान कल्याण के पद से हटाकर कार्मिक सचिव सामान्य प्रशासन विभाग बनाया गया है। 2015 बैच की आईएएस अधिकारी राखी सहाय को मप्र लोक सेवा आयोग का सचिव बनाया गया है। वे पिछले कई वर्षों से इंदौर में ही विभिन्न पदों पर रही हैं। अब वे आयोग की सचिव बतौर इंदौर में ही काबिज रहेंगी।

सीएम सचिवालय में बार-बार बदलाव क्यों...?

किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री कार्यालय शासन-प्रशासन की रीढ़ माना जाता है। इसलिए सरकार की सबसे पहली कोशिश यह रहती है कि सीएम सचिवालय में लंबे समय तक काम करने वाले अफसरों को पदस्थ किया जाए। लेकिन मप्र में यह देखने को आ रहा है कि सीएम सचिवालय में बार-बार बदलाव हो रहा है। अभी हाल ही में राज्य सरकार ने प्रशासनिक सर्जरी करते हुए वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के बड़े स्तर पर तबादले किए। इसमें सीएम सचिवालय भी शामिल था। मुख्यमंत्री सचिवालय में अपर मुख्य सचिव रहे डॉ. राजेश राजौरा को हटाकर उनकी जगह नीरज मंडलोई को मुख्यमंत्री कार्यालय का नया अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। मंडलोई मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की गुड बुक में लंबे समय से माने जाते रहे हैं। **मंडलोई के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी सीएम सचिवालय और सीएस के बीच की दूरी को कम करना।** अब कहा जा रहा है कि तकरीबन 6 महीने से जो सूची बैकलॉग पड़ी है, उसे हरी झंडी दे दी जाएगी। पिछले साल जून में राजेश राजौरा को मुख्यमंत्री कार्यालय में अपर मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त किया गया था। उस समय उनके साथ सीएमओ में दो और प्रमुख सचिव की भी तैनाती हुई थी। मुख्यमंत्री कार्यालय में कुल 9 आईएएस अधिकारियों की टीम बनाई गई थी, जिसकी कमान राजौरा के हाथ में थी। कुछ समय पहले वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राघवेंद्र सिंह, संजय शुक्ल और भरत यादव को भी सीएमओ से हटा दिया गया था। वहीं हाल ही में योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में उप सचिव आईएएस विकास मिश्रा को मुख्यमंत्री कार्यालय में उप सचिव बनाया गया है। वहीं, आलोक कुमार सिंह को अपने वर्तमान दायित्व के साथ-साथ मुख्यमंत्री कार्यालय में उप सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

अपनों के शिकार हो गए शुक्ल

तबादले में सबसे चौंकाने वाला नाम नगरीय विकास एवं आवास विभाग के एसीएस संजय कुमार शुक्ल का था। उन्हें अब सामान्य प्रशासन विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। बताया जाता है कि विभागीय मंत्री से नजदीकी के कारण शुक्ल को हटाया गया। वहीं उनके समकक्ष कुछ अधिकारियों और एक रिटायर आईएएस अधिकारी की भूमिका भी शुक्ल को नगरीय विकास एवं आवास विभाग से हटाने में रही।

आईएएस-आईपीएस की सूची जल्द

वरिष्ठ अधिकारियों के तबादलों के बाद अब जल्द ही आईएएस-आईपीएस अधिकारियों की एक और सूची आएगी। इसमें प्रदेश के कमिश्नरों, कलेक्टरों, आईजी, डीआईजी और एसपी के बड़े पैमाने पर तबादले हो सकते हैं। गौरतलब है कि सरकार फील्ड में नई जमावट करने वाली है। इसके साथ ही 1 अगस्त को **उज्जैन संभागायुक्त संजय गुप्ता रिटायर** होने वाले हैं। बताया जा रहा है कि उनकी जगह इंदौर कलेक्टर **आशीष सिंह कमिश्नर** बनाए जाएंगे। हालांकि आशीष सिंह को 2026 में कमिश्नर की रैंक मिलेगी। वहीं इंदौर कलेक्टर बनने के लिए **धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा** सबसे बड़े दावेदार बनकर उभरे हैं। हालांकि बताया जाता है कि भोपाल कलेक्टर **कौशलेंद्र विक्रम सिंह** भी इंदौर कलेक्टर बनने की तैयारी में हैं। अब देखना यह है कि 1 अगस्त के बाद किसकी-किसकी लॉटरी लगती है।

आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक बनीं सोनाली

अभी हाल ही में मप्र को एक उपलब्धि मिली है, वह यह है कि वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सोनाली मिश्रा को रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वह 1993 बैच की मप्र कैडर की भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी हैं। कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मिश्रा की 31 अक्टूबर, 2026 को उनकी सेवानिवृत्ति तक इस पद पर नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। वह वर्तमान महानिदेशक मनोज यादव से पदभार ग्रहण करेंगी, जो 31 जुलाई को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। मिश्रा आरपीएफ का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी होंगी, जिसे अन्य कर्तव्यों के अलावा रेलवे संपत्ति और यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वह वर्तमान में मप्र पुलिस में अतिरिक्त महानिदेशक (चयन) के पद पर तैनात हैं। ध्यान देने वाली बात है कि इसी साल मई के महीने में राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन भोपाल में आयोजित किया गया था। इस खास मौके पर सुरक्षा की जिम्मेदारी महिला अफसरों के हाथ में सौंपी गई थी। कार्यक्रम में आईपीएस सोनाली मिश्रा को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा का जिम्मा दिया गया था। जिसको उन्होंने बखूबी निभाया था। सोनाली मिश्रा के नेतृत्व में 6 से अधिक महिला आईपीएस अधिकारियों ने भोपाल में मुस्तैदी के साथ अपनी सेवाएं दी थीं।

रवि गुप्ता की लगी लॉटरी

सोनाली मिश्रा को रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किए जाने से आईपीएस अधिकारी रवि गुप्ता की लॉटरी लग गई है। अब वे 1 अगस्त को जीपी सिंह के रिटायर होने के बाद स्पेशल डीजी बन जाएंगे। पहले वे 1 सितंबर को लोकेश मुद्गल के रिटायरमेंट के बाद स्पेशल डीजी बनते।

मप्र में आईजी का टोटा

प्रदेश में पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारियों की कमी है। जानकारी के अनुसार प्रदेश में आईजी के 31 पद स्वीकृत हैं, लेकिन इसके मुकाबले करीब 15-16 आईजी ही कार्यरत हैं। इससे प्रशासनिक जमावट सही ढंग से नहीं हो पा रही है। वहीं डीआईजी के स्वीकृत सभी 26 पदों पर उप महानिरीक्षक कार्यरत हैं। यही नहीं राज्य प्रशासनिक सेवा से पदोन्नत होकर अखिल भारतीय पुलिस सेवा में चयनित 2010 बैच के बने 3 साल हो गए हैं, लेकिन 5 अधिकारी डीआईजी नहीं बन पाए हैं। उधर, 2011 और 2012 बैच वाले आईपीएस अधिकारी डीआईजी बनने की कतार में हैं।

नए मुख्य सचिव की सुगबुगाहट

मप्र में नए मुख्य सचिव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। मौजूदा मुख्य सचिव अनुराग जैन और अपर मुख्य सचिव जेएन कंसोटिया अगस्त में रिटायर होने वाले हैं। ऐसे में अगर मुख्य सचिव जैन को एक्सटेंशन नहीं मिलता है तो सीएम सचिवालय में अपर मुख्य सचिव रहे डॉ. राजेश राजौरा सबसे सीनियर आईएएस अफसर होंगे। दूसरी ओर, राजौरा के बैच की दिल्ली में पदस्थ महिला आईएएस अलका उपाध्याय ने भी भोपाल में अपनी दिलचस्पी बढ़ा दी है।

1989 बैच के आईएएस अधिकारी अनुराग जैन 11 अगस्त को 60 साल के हो रहे हैं। वहीं उन्हीं के बैच के एक अन्य आईएएस जेएन कंसोटिया 12 अगस्त को 60 साल की उम्र पूरी करेंगे। दोनों ही अधिकारियों ने 21 अगस्त 1989 को एक साथ आईएएस की नौकरी जॉइन की थी। इसलिए दोनों ही अधिकारी सर्विस रूल के हिसाब से 31 अगस्त को रिटायर होंगे। ऐसे में मप्र के नए मुख्य सचिव के पद को लेकर भी प्रशासनिक गलियारे में चर्चा शुरू हो गई है। इसे हवा तब मिली जब 6 जुलाई को सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश द्वारा अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री डॉ. राजेश राजौरा को सीएम सचिवालय से बाहर किया गया और उन्हें नर्मदा घाटी विकास विभाग का एसीएस और प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बना दिया गया। यह विभाग पहले से राजौरा के पास है। 1 अक्टूबर 2024 को मप्र के मुख्य सचिव बने अनुराग जैन के कार्यकाल में एक्सटेंशन की चर्चा अभी सर्वाधिक है लेकिन मंत्रालय सूत्रों का कहना है कि अगर जैन को एक्सटेंशन नहीं मिलता तो राजौरा की दावेदारी सबसे अधिक होगी। जैन के सीएस बनने से पहले राजौरा का नाम फाइनल माना जा रहा था। सीएस के एक्सटेंशन का मामला केंद्र की अनुमति से ही होगा और अगर जैन को एक्सटेंशन नहीं दिया जाता है तो नए मुख्य सचिव के पद के लिए नाम भी केंद्र की सहमति से फाइनल होगा।

● राजेन्द्र आगाल

सिया की जंग धरातल पर उतरी

राजधानी भोपाल में सिया (स्टेट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी) में खदानों की अनुमति को लेकर जो विवाद शुरू हुआ है, वह अब धरातल पर आ गया है। दरअसल, सिया के चेयरमैन शिवनारायण सिंह चौहान अपनी मंशा पूरी होते न देख आर-पार की लड़ाई में उतर गए हैं। सूत्रों का कहना है कि चौहान कुछ खदानों को अपने हिसाब से अनुमति देना चाहते थे, लेकिन जब उनकी बात नहीं बनी तो उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। गौरतलब है कि चौहान की मनमानी से विभाग के अधिकारी-कर्मचारी पहले से ही परेशान चल रहे थे। ऐसे में पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. नवनीत मोहन कोठारी ने सिया के माध्यम से सरकार पर लग रहे दाग को धोने की कवायद शुरू की है और उन्होंने लंबित पड़े मामलों का निपटारा तेजी से शुरू कर दिया है। वहीं गत दिनों उन्होंने चौहान को सबक सिखाने के लिए सुबह-सुबह उनका दफ्तर सील करवा दिया। हालांकि दोपहर में उसे फिर से खोल दिया गया। दरअसल, सिया चेयरमैन सरकार की मंशा और गाइडलाइन के विपरीत जाकर काम करना चाहते हैं। इस पर विभाग ने लगाम कसनी शुरू कर दी है।

पत्थरों के टुकड़ों से बनेगी रेत

रेत के लिए नदियों पर निर्भरता खत्म करने के मकसद से मप्र की पहली मैकेनिकल सैंड (एम-सैंड) पॉलिसी बनाई जाएगी। नई पॉलिसी में प्रस्तावित किया गया है कि मप्र में एम-सैंड का 10 करोड़ रुपए का प्लांट लगाने पर 40 प्रतिशत तक की सब्सिडी सरकार देगी। पॉलिसी में ओवर बर्डन निष्पादन कराने वाला मप्र पहला ऐसा राज्य होगा। ओवर बर्डन निष्पादन यानी किसी भी खनन के दौरान मिट्टी के साथ निकलने वाले पत्थरों के टुकड़े। नई पॉलिसी में इन पत्थरों को भी तोड़कर रेत बनाने की मंजूरी दी जा रही है। अब तक खनन के बाद निकले पत्थर काम के नहीं होते थे। पत्थरों को तोड़कर उसी तकनीकी दक्षता की रेत बनाने को एम-सैंड कहते हैं, जैसी नदियों से निकलती है।

फिलहाल तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, राजस्थान और केरल जैसे देश के 8 राज्यों में एम-सैंड पॉलिसी लागू है। कर्नाटक में सबसे ज्यादा 2 करोड़ टन, तेलंगाना में 70 लाख टन और तमिलनाडु में 30 लाख टन, राजस्थान में 1.20 करोड़ टन एम-सैंड का सालाना उत्पादन हो रहा है। राजस्थान ने इसके लिए वर्ष 2024 में एम-सैंड पॉलिसी बनाई थी। इसके तहत रियायत देते हुए 3 साल के अनुभव व 3 करोड़ के टर्न ऑवर की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। सरकारी व वित पोषित निर्माण कार्यों में बजरी की मांग की आपूर्ति में 50 प्रतिशत एम-सैंड के उपयोग की अनिवार्यता तय है। केरल की पॉलिसी से सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि वहां नदियों से रेत का उत्खनन ना के बराबर बचा है। सभी स्टेक होल्डर्स से बैठकों की प्रक्रिया पूरी करने के बाद बनी मप्र एम-सैंड पॉलिसी अब आखिरी चरण में है। सूत्रों का कहना है कि शासन स्तर पर इस पॉलिसी को जल्द ही प्रदेश में लागू किया जा सकता है।

प्रदेश में अब मेजर मिनरल की खदानों से बड़ी मात्रा में निकलने वाले पत्थरों से भी रेत बनाई जाएगी। इसके लिए लायसेंस जारी कर एम-सैंड यूनिट लगाई जाएंगी। इसके साथ अलग-अलग पत्थरों से बनने वाली एम-सैंड के लिए अलग-अलग रॉयल्टी की दरें और उसके रेट तय किए जाएंगे। जिन जिलों में रेत उत्खनन नहीं होता है वहां पर एम-सैंड प्लांट लगाए जाएंगे। इसके प्रावधान शामिल किए गए हैं। इस पॉलिसी को इसी महीने लागू करने की तैयारी की जा रही है। सरकार द्वारा नदियों से निकाली जाने वाली रेत की बजाय एम-सैंड (मैन्युफेक्चर्ड सैंड यानी पत्थर से कृत्रिम तरीके से बनने वाली रेत) को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने पिछले साल समीक्षा बैठक में इस संबंध में निर्देश दिए थे। हाल ही में खनिज विभाग ने यह प्रक्रिया पूरी कर ली है। अब एम-सैंड पॉलिसी को जल्द कैबिनेट में पेश किया जाएगा। कैबिनेट से एप्रूवल के बाद इसी माह इसे लागू करने की तैयारी की जा रही है। इससे नदियों को नवजीवन मिल सकेगा। अभी हर साल प्रदेश में 125 लाख घन मीटर से अधिक रेत की जरूरत होती है। इस रेत की पूर्ति नदियों से ही होती है।

प्रदेश में 14 जिले ऐसे चिन्हित किए गए हैं जहां पर रेत उत्खनन नहीं होता है। इनमें भोपाल और इंदौर जैसे बड़े जिले भी शामिल हैं। पॉलिसी के तहत इन जिलों में प्राथमिकता से एम-सैंड प्लांट लगाए जाएंगे। इससे रेत की आपूर्ति होने के साथ रोजगार भी बढ़ेगा। प्रमुख सचिव खनिज संसाधन विभाग उमाकांत उमराव का कहना है कि एम-सैंड पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार है। विभिन्न संबंधित विभागों से भी डिस्कशन लगभग पूरा हो गया है। इसमें एम-सैंड को बढ़ावा देने के लिए कई प्रावधान शामिल किए गए हैं। इसी माह पॉलिसी लागू करने की तैयारी की जा रही है। पॉलिसी में प्रावधान है कि एम-सैंड प्लांट लगाने वालों को सरकार 40 फीसदी तक छूट दे सकती है। गिट्टी, पत्थर की खदान और क्रेशर संचालन करने वालों को एक आवेदन पर एम-सैंड प्लांट के लिए लायसेंस मिलेगा। एम-सैंड को बढ़ावा देने के लिए इसकी रॉयल्टी भी कम रहेगी। इसकी कीमत 50 रुपए प्रति घन मीटर के करीब रहने की संभावना है। जबकि नदियों की रेत के लिए 250 रुपए प्रति घन मीटर तय है। मेजर मिनरल जैसे कोयला, बॉक्साइट, मैंगनीज सहित हीरे की खदानों की खुदाई में बड़ी मात्रा में ग्रेनाइट, बेसाल्ट, लाइम स्टोन जैसे पत्थर बड़ी मात्रा में निकले हैं लेकिन यह वेस्ट मटेरियल की तरह पड़े रहते हैं। पॉलिसी में इन पत्थरों से एम-सैंड बनाने के लिए लायसेंस देने के प्रावधान किए गए हैं। साथ ही ग्रेनाइट, बेसाल्ट, लाइमस्टोन जैसे पत्थरों से बनने वाली रेत के लिए रॉयल्टी भी अलग-अलग तय की जाएगी।

● सुनील सिंह

नदियों से 2.5 करोड़ घनमीटर उत्खनन

मप्र में फिलहाल करीब 50 से ज्यादा नदियों से वैध रेत उत्खनन किया जाता है। इनमें 10 बड़ी नदियां ऐसी हैं, जहां बहुतायत में उत्खनन होता है। मप्र में सालभर में नदियों से करीब 2.5 करोड़ घन मीटर रेत निकाली जाती है। हालांकि, प्रदेश की सालाना जरूरत करीब 4 करोड़ घनमीटर रेत की है। यानी उत्खनन के बाद भी करीब डेढ़ करोड़ घनमीटर रेत की और जरूरत पड़ती है। नदियों से निकलने वाली रेत के मुकाबले एम-सैंड आम लोगों को भी ज्यादा सस्ती मिलेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके लिए रॉयल्टी की दरें केवल 50 रुपए प्रति घन मीटर रखी जा रही है। इसके अलावा प्लांट लगाने के लिए तीन अलग-अलग श्रेणियों में सब्सिडी देने का प्रावधान भी किया जा रहा है। नई पॉलिसी के तहत 10 करोड़ रुपए तक का प्लांट लगाने पर 40 प्रतिशत, 10-50 करोड़ रुपए तक के प्लांट पर 35 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जा सकती है। 50 करोड़ से ज्यादा बड़े प्लांट पर जल्द आने वाली मप्र उद्योग पॉलिसी में उद्योग विकास अनुदान देने का प्रस्ताव बनाया गया है। मप्र में ग्रेनाइट पत्थर काफी मात्रा में हैं, जो एम-सैंड बनाने के लिए सबसे उपयोगी माने जाते हैं। इसके अलावा सैंड स्टोन, बिसाल्ट और क्वार्डजाइट पत्थर भी इसके लिए उपयोगी हैं। नई पॉलिसी में प्रस्ताव दिया जा रहा है कि खनिज विभाग निजी जमीन पर परिवहन या उत्खनन अनुज्ञा देकर एम-सैंड तैयार करवाएगा। वहीं, सरकारी जमीन के लिए उद्योगपति को टेंडर प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

आदिवासियों को मिल रहे पट्टे

मप्र में जंगल बचाने शुरू होंगे वन विज्ञान केंद्र

मप्र के नक्सल प्रभावित बालाघाट जिले में पुलिस ने 46 थानों और कैंपों में एकल सुविधा केंद्र शुरू किए गए हैं। इन केंद्रों के जरिए ऑपरेशन पहचान के तहत आधार कार्ड, आयुष्मान योजना, वृद्धावस्था पेंशन और आपकी भूमि आपके द्वार अभियान के तहत वनाधिकार पट्टा जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। हालांकि शुरुआत में नक्सलियों ने ग्रामीणों को इन केंद्रों से दूर रहने के लिए उकसाया। लेकिन जब इन केंद्रों से सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को सीधे मिलने लगा, तो नजरिया बदला। धीरे-धीरे लोगों का इन केंद्रों पर भरोसा बढ़ा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तब देखने को मिला, जब इलाके के कुख्यात नक्सली कमांडर संपत की पत्नी हिरोड़ा बाई खुद पुलिस कैंप पहुंची और वनाधिकार पट्टे का फॉर्म भरकर जमा किया। अब इस मॉडल को प्रदेश के 89 आदिवासी ब्लॉक में लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गत दिनों सीएम हाउस में एक बैठक ली, जिसमें उन्होंने ये निर्देश दिए। यह बैठक वन अधिकार अधिनियम और पेसा एक्ट के क्रियान्वयन को लेकर गठित राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की शीर्ष कार्यकारी समिति के साथ हुई।

बालाघाट एसपी आदित्य मिश्रा साल 2022 में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पदस्थ थे। उसी दौरान उन्होंने बालाघाट के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस चौकियों को एकल सुविधा केंद्रों में बदलने की शुरुआत की थी। इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू करते हुए ग्रामीणों, खासकर आदिवासी वर्ग को वनाधिकार पट्टों के आवेदन, जाति प्रमाण पत्र बनवाने और अलग-अलग सरकारी योजनाओं का फायदा दिलाने का जरिया बनाया गया। हालांकि, बीच में आदित्य मिश्रा का तबादला हो गया। लेकिन इस साल, जब वे फिर बालाघाट एसपी बनकर पहुंचे, तो उन्होंने पिछले महीने (जून) से इस काम को फिर से शुरू किया। बालाघाट एसपी आदित्य मिश्रा ने बताया कि हमने इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए हर पुलिस चौकी और कैंप में 4-5 पुलिसकर्मियों को आदिवासी वर्ग को सरकारी योजनाओं का फायदा दिलाने के लिए प्रशिक्षित किया। दूसरे विभागों के अधिकारी-कर्मचारियों के नंबर पुलिस चौकी को मुहैया कराए। जहां जिस आवेदक को दिक्कत आती, पुलिस चौकी से संबंधित विभाग में बातचीत कर समाधान कराया जाता है। वहीं, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि जनजातीय वर्ग के अध्ययनरत और युवाओं का सामाजिक सम्मेलन बुलाएं। इस सम्मेलन के जरिए सरकार इन बच्चों को उन तक पहुंचने वाले लाभ का फीडबैक भी लेगी और जिन्हें जरूरत है, उन तक सरकारी योजनाएं और सुविधाएं भी पहुंचाई जाएंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में पेसा एक्ट यानि पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 लागू है। इसमें पेसा मोबिलाइजर्स के जरिए जनजातियों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देकर योजनाओं से लाभान्वित भी कराया जाता है। इन सभी पेसा मोबिलाइजर्स का अपने काम में मौजूदगी और हाई क्वालिटी का काम फील्ड में दिखाई भी देना चाहिए।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि पेसा मोबिलाइजर्स को नियुक्त करने और संतोषजनक प्रदर्शन न करने पर इन्हें हटाने के अधिकार सरकार अब ग्राम सभाओं को देने जा रही है। इस फैसले से एकरूपता आएगी और ग्राम सभाएं पेसा मोबिलाइजर्स से अपने मुताबिक काम भी ले सकेंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों के विकास के लिए विधायकों द्वारा विजन डॉक्यूमेंट बनाया गया है। वनाधिकार अधिनियम और पेसा कानून के अमल के लिए समुचित प्रावधान भी इसी विजन डॉक्यूमेंट में शामिल कर लिए जाएं। उन्होंने कहा कि सरकार क्रमबद्ध रूप से विशेष रूप से पिछड़े जनजातीय समूहों और अन्य जनजातीय बहुल गांव, मजरों-टोलों तक सड़कों का निर्माण कर रही है। ग्राम पंचायत विकास कार्ययोजना में पेसा कोष की राशि खर्च करने का अधिकार भी संबंधित पेसा ग्राम सभा को दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि वन क्षेत्र के सभी गांवों के विकास के लिए प्रस्ताव दिए जाएं। उन्होंने कहा कि यह काम एक्शन प्लान बनाकर किया जाए। उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर 2025 तक सभी गांवों के दावे प्राप्त कर लें और इसी दौरान इनका निराकरण भी कर लें। वन अधिकारियों की ट्रेनिंग का काम 15 अगस्त तक पूरा कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि अगर कोई तकनीकी परेशानी आ रही है तो इसके लिए वन और जनजातीय कार्य विभाग मिलकर एक नया पोर्टल भी बना लें।

● नवीन रघुवंशी

मप्र सरकार जंगलों की कटाई रोकने और जंगल पर आश्रित आदिवासी वर्ग की आजीविका बढ़ाने के लिए वन विज्ञान केंद्र शुरू करने जा रही है। वन विकास केंद्र स्थानीय स्तर पर रिसर्च करके ये तय करेंगे कि किस क्षेत्र में किस प्रजाति के पौधे लगाकर जंगल बढ़ाना चाहिए। फिलहाल तीन क्षेत्रों विंध्य, महाकौशल और मध्य क्षेत्र में ये वन विकास केंद्र पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किए जाएंगे। वन विज्ञान केंद्र को कृषि विज्ञान केंद्रों की तर्ज पर स्थापित किया जाएगा। आमतौर पर मप्र में वन विभाग सागौन के पौधे लगाने पर जोर देता है। उसकी वजह ये है कि जानवर सागौन को नुकसान नहीं पहुंचाते और इमारती लकड़ी होने के कारण इससे सरकार को आमदनी अच्छी होती है। अब वन विज्ञान केंद्र के जरिए स्थानीय जलवायु और वातावरण में आदिवासी वर्ग की आजीविका को बढ़ाने में मददगार पेड़ लगाने के लिए शोध करेगा। इसके बाद हरड़, बहेड़ा, आंवला, महुआ जैसे पेड़ लगाए जाएंगे। इससे जंगल भी बचेंगे और आदिवासी वर्ग की आजीविका भी बढ़ेगी। वन विकास केंद्रों का संचालन करने के लिए तीन एनजीओ चयनित किए जाएंगे। इस काम में आईआईएफएम यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट टेक्निकल सपोर्ट देगा। वन विभाग इस पूरे प्रोजेक्ट की निगरानी करेगा। इस पायलट में तीन प्रमुख आधार होंगे। पहला वन विभाग, दूसरा संबंधित ग्राम सभा (स्थानीय जनसमुदाय का प्रतिनिधित्व करेगी) और तीसरा निजी निवेशक। महाराष्ट्र में वाटरशेड मैनेजमेंट के लिए सरकार ने एनजीओ, ग्रामीण विकास विभाग, स्व सहायता समूहों की मदद से सूखाग्रस्त गांवों को पानीदार बनाने पर काम किया। इसमें तालाबों, नदी, नालों का चौड़ीकरण, गहरीकरण पर काम शामिल है। करीब 25 हजार गांवों का चयन कर सरकार ने वर्षा जल को रोककर सिंचाई क्षमता को दो फसलें पैदा करने पर काम किया है।

घुसपैठ बनी नासूर

बांग्लादेशियों को वापस भेजना बड़ी चुनौती

घुसपैठ के खिलाफ फिलहाल विभिन्न राज्यों में जो कार्रवाई हो रही है, उससे लगता है कि हम शायद कुछ हजार बांग्लादेशियों को ही वापस भेज पाएंगे। बड़ी संख्या में बांग्लादेशियों के भारत में रहने की स्थिति से हमें समझौता करना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो हमें तीन बातें सुनिश्चित करनी होंगी। पहली, अवैध रूप से आए बांग्लादेशियों को अलग पहचान पत्र दिए जाएं, जिसके अंतर्गत उन्हें देश में रहने और काम करने की अनुमति हो। दूसरी, वे भारत में अचल संपत्ति न खरीद सकें और तीसरी उन्हें किसी भी चुनाव में वोट देने का अधिकार न हो। भारत सरकार को यह भी साहस जुटाना होगा कि जितने बांग्लादेशी भारत में रह रहे हैं, उनके रहने के लिए उसी अनुपात में बांग्लादेश से भूमि मांगे। बांग्लादेश इसके लिए राजी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में हमें सख्ती दिखानी होगी। बात आगे बढ़े तो रंगपुर डिवीजन में भूमि लेने से सिलीगुड़ी कॉरिडोर की समस्या बहुत हद तक सुलझ जाएगी। गृहमंत्री बार-बार कहते हैं कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है कि यहां कोई भी घुसा चला आए और यहीं बसेरा बना ले। धर्मशाला तो हमारा देश बन चुका है। देखना यह है कि इस धर्मशाला की सरकार कितनी सफाई कर पाती है।

भारत सरकार को साहस जुटाना होगा कि जितने बांग्लादेशी भारत में रह रहे हैं उनके रहने के लिए उसी अनुपात में बांग्लादेश से भूमि मांगे। बांग्लादेश इसके लिए राजी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में हमें सख्ती दिखानी होगी। बात आगे बढ़े तो रंगपुर डिवीजन में भूमि लेने से सिलीगुड़ी कॉरिडोर की समस्या बहुत हद तक सुलझ जाएगी।

बांग्लादेशियों की भारत में बड़ी संख्या में घुसपैठ से पैदा समस्याओं के प्रति भारत में दशकों तक सुस्ती दिखाए जाने के बाद अब कुछ जागृति दिखाई दे रही है। कई राज्यों में उनकी धरपकड़ हो रही है और उन्हें वापस बांग्लादेश भेजे जाने के प्रयास हो रहे हैं। दिल्ली में ही पिछले छह महीनों के दौरान करीब 800 बांग्लादेशी पकड़े गए और उन्हें बांग्लादेश वापस भेजा गया। असम में विशेष तौर से बांग्लादेशियों के विरूद्ध अभियान चल रहा है। असम ने एक आदेश जारी किया है कि जब तक जिला मजिस्ट्रेट सत्यापित नहीं कर देंगे, तब तक किसी को आधार पहचान पत्र नहीं मिलेगा।

महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा से भी अवैध बांग्लादेशियों की धरपकड़ के समाचार आए हैं, फिर भी हमें यह समझना होगा कि जो कार्रवाई हो रही है, वह बांग्लादेशियों की बहुत अधिक संख्या को देखते हुए शून्य है। वैसे तो तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान से कुछ लोग बराबर भारत में घुसपैठ करते रहे। 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद सोचा गया कि अब घुसपैठ कम हो जाएगी, पर दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। नया देश बनने के बाद भी वहां अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न होता रहा और उनकी स्थिति खस्ताहाल बनी रही। फलस्वरूप हिंदू और मुसलमान, दोनों ही अलग-अलग कारणों से भारत आते रहे। बांग्लादेश के इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज के अनुसार 1951 और 1961 के बीच पूर्वी पाकिस्तान से 35 लाख व्यक्ति गायब हो गए। इसी प्रकार 1961 से 1974 के बीच 15 लाख व्यक्तियों का भी कुछ पता नहीं चला। ये व्यक्ति हवा में नहीं उड़ गए। ये सब भारत चले आए। बांग्लादेश के बुद्धिजीवियों ने लेबेंस्राम की भी एक थ्योरी चलाई। इसके अनुसार अधिक जनसंख्या के क्षेत्र से कम जनसंख्या के क्षेत्र में लोगों का प्रवाह एक सामान्य प्रक्रिया है और बांग्लादेशियों का भारत जाना स्वाभाविक है। दुर्भाग्य से भारत की किसी भी सरकार ने इस समस्या को गंभीरता से नहीं लिया।

कारगिल युद्ध के बाद भारत सरकार ने चार टास्क फोर्स बनाई थीं। इनमें से एक टास्क फोर्स बॉर्डर मैनेजमेंट यानी सीमा प्रबंधन से संबंधित थी। इसके अध्यक्ष माधव गोडबोले थे, जो बाद में केंद्रीय गृह सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने अगस्त 2000 में भारत सरकार को सौंपी रिपोर्ट में खेद प्रकट किया कि देश में हर पार्टी में इस समस्या के प्रति उदासीनता थी और किसी भी राज्य या केंद्र सरकार ने इसके दुष्परिणामों के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने साफ लिखा कि इस समस्या को लेकर सारी जानकारी और उससे निपटने के पर्याप्त संसाधन थे, पर राजनीतिक वर्ग में समस्या से निपटने के तरीकों में कोई सहमति न होने के कारण निष्क्रियता रही। टास्क फोर्स के आंकलन के अनुसार हर महीने करीब 25 हजार यानी प्रतिवर्ष 3 लाख बांग्लादेशी अवैध तरीके से भारत आते रहे और भारत में उनकी कुल संख्या उस समय तक करीब 1.5 करोड़ थी। बांग्लादेश-भारत सीमा पर जैसे-जैसे फेंसिंग लगती गई, घुसपैठियों की संख्या में कमी होती गई। फिर भी बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या भारत में इस समय कम से कम 2 करोड़ होगी। 2001 में मंत्रियों के एक समूह ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक रिपोर्ट में स्पष्ट शब्दों में उल्लेख किया कि बांग्लादेश से जो घुसपैठ हो रही है वह देश की सुरक्षा, सामाजिक सौहार्द और आर्थिक प्रगति के लिए एक गंभीर खतरा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2005 में एक फैसले में कहा कि असम में बांग्लादेशियों की घुसपैठ के कारण आंतरिक उथल-पुथल और विदेशी आक्रमण जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है और इस परिस्थिति में भारत सरकार का कर्तव्य बनता है कि असम की सुरक्षा के लिए संविधान के अनुच्छेद 355 के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई करे।

यह देश का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि टास्क फोर्स की रिपोर्ट, मंत्रियों के समूह की चेतावनी और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी भारत सरकार की नींद नहीं खुली और स्थिति जस की तस बनी रही। क्या यूपीए सरकार, क्या एनडीए सरकार, किसी ने कुछ नहीं किया। अब जब बांग्लादेश में तख्तापलट हो गया है और शेख हसीना वहां से बचकर भारत में निर्वासित रूप में रह रही हैं और मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार का गठन हो गया है, जो भारत विरोधी है, तब सबको लग रहा है कि कुछ करना चाहिए। समकालीन वैश्विक परिदृश्य को देखें तो तमाम देश अवैध रूप से रह रहे लोगों के खिलाफ अभियान छेड़े हुए हैं। अमेरिका में विभिन्न देशों से घुसपैठ कर आए हुए सभी व्यक्तियों को जबरन उनके देश वापस भेजा जा रहा है। पाकिस्तान ने भी करीब 13 लाख अफगानों को वापस अफगानिस्तान भेज दिया है। मलेशिया से भी बांग्लादेशियों के विरूद्ध कार्रवाई की खबर आ रही है। ऐसे माहौल में भारत में अवैध तरीके से घुसे बांग्लादेशियों और म्यांमार से रोहिंग्या घुसपैठियों के विरूद्ध व्यापक स्तर पर कार्रवाई में कोई संकोच नहीं होना चाहिए।

● **डॉ. जय सिंह सेंधव**

2047 तक बुजुर्गों का प्रदेश हो जाएगा मप्र

दुनियाभर में जिस तरह भारत की पहचान युवाओं के देश के रूप में हो रही है, उसी तरह भारत में मप्र में यूथ अधिक हैं। लेकिन इस बीच एनएफएचएस (राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण) की रिपोर्ट ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार मप्र में प्रजनन दर तेजी से कम हो रही है। अगर यही स्थिति रही तो मप्र में 2047 तक यूथ से ज्यादा बुजुर्ग दिखेंगे। यानी मप्र बुजुर्गों का प्रदेश हो जाएगा।

गौरतलब है कि राजधानी भोपाल को देश की सबसे स्वच्छ राजधानी का खिताब मिला है, कई मामलों में शहर देश में टॉप पर है, लेकिन प्रजनन दर के मामले में भोपाल देश ही नहीं बल्कि मप्र में भी सबसे पिछड़ा है। एक ओर जहां मप्र की प्रजनन दर 2.8 है, जो देश के औसत प्रजनन दर 2.3 से 0.5 अधिक है। वहीं भोपाल की प्रजनन दर 2.0 है, यानि यहां प्रति महिला दो बच्चे पैदा होते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-2021 की रिपोर्ट के अनुसार भोपाल में तेजी से प्रजनन दर घट रही है। प्रदेश में भोपाल इस मामले में सबसे निचले पायदान पर है। जबकि सबसे अधिक प्रजनन दर वाले जिलों में पन्ना है। वहां टीएफआर 4.1 है। इसी तरह शिवपुरी का 4.0, बड़वानी में 3.9, विदिशा में 3.9 और छतरपुर का टीएफआर 3.8 है। इसी तरह यदि प्रदेश में टाप 5 सबसे कम प्रजनन दर वाले जिलों की बात करें तो इनमें भोपाल टीएफआर 2.0, ग्वालियर का 2.1, मंदसौर का 2.2, इंदौर 2.2 और दतिया जिले में प्रजनन दर 2.3 है। बता दें कि प्रजनन दर यानि टोटल फर्टिलिटी रेट का आशय किसी क्षेत्र में प्रति एक हजार महिलाओं पर पैदा होने वाले बच्चों से है। इसका सीधा मतलब ये है कि संबंधित क्षेत्र की महिलाएं अपने प्रजनन काल में कितने बच्चों को जन्म देती हैं। इसी के आधार पर भविष्य की जनसंख्या का अनुमान लगाया जाता है। भारत में टीआरएफ 2.1 एक आइडियल प्रजनन दर है, लेकिन भोपाल इससे भी पीछे है। हालांकि ये पहली बार नहीं है, इसके पहले किए गए फैमिली हेल्थ सर्वे में भी भोपाल का टीएफआर 2.1 था।

मप्र में फर्टिलिटी रेट कम होने से बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ेगी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के ताजा आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में 20 से 29 साल के युवाओं की आबादी 1 करोड़ 54 लाख है, लेकिन आने वाले साल यानि वर्ष 2047 तक युवा आबादी बढ़ने की बजाय कम होने लगेगी। इसके उलट वर्तमान में जहां 60 साल से अधिक आयु वर्ग के बुजुर्गों की संख्या 57 लाख के करीब है, वो साल 2045 तक बढ़कर 1 करोड़ 80 लाख से अधिक होगी। यानि 23 साल बाद मप्र की अधिकतर आबादी बुजुर्ग होगी। यदि फैमिली हेल्थ सर्वे 2011-12 और 2019-21 की रिपोर्ट का विश्लेषण करें, तो भोपाल के साथ ही मप्र में कई अन्य जिले भी हैं, जहां तेजी से फर्टिलिटी रेट घट रहा है, लेकिन यह आइडियल फर्टिलिटी रेट से अधिक है। इनमें पन्ना, शिवपुरी, बड़वानी, विदिशा और छतरपुर जिलों में टीएफआर तेजी से घट रहा है। जबकि अन्य जिलों में आंशिक गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि इन 10 सालों में रीवा, सीधी, शाजापुर, सिवनी, धार और श्योपुर ऐसे जिले हैं, जहां टीएफआर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। नोडल अधिकारी डॉ. रचना दुबे का कहना है कि मप्र में शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रजनन दर अधिक है। इसका कारण लोगों में जागरूकता और परिवार नियोजन जैसे प्रबंधों का अभाव है। डॉ. रचना दुबे कहती हैं कि भोपाल जैसे शहर में परिवार नियोजन को लेकर बड़े स्तर पर काम होता है। नसबंदी को लेकर यहां लोग ज्यादा जागरूक हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में नसबंदी को लेकर भी भ्रांतियां हैं, जिससे कई बार लोग परिवार नियोजन का सहारा नहीं लेते।

● जितेंद्र तिवारी

10 सालों में प्रजनन दर में आई कमी (आंकड़े प्रतिशत मे)

जिला	2011-12	2019-21	जिला	2011-12	2019-21
पन्ना	4.3	4.1	मुरैना	3.2	3.0
शिवपुरी	4.4	4.0	सिवनी	3.0	3.0
बड़वानी	4.4	3.9	भिंड	3.1	2.9
विदिशा	4.0	3.9	धार	2.9	2.9
छतरपुर	4.1	3.8	हरदा	3.0	2.9
सतना	3.7	3.6	झाबुआ	3.0	2.9
दमोह	3.6	3.5	मंडला	3.0	2.9
सीहोर	3.6	3.5	बैतूल	2.9	2.8
डिंडोरी	3.5	3.4	उज्जैन	2.9	2.8
गुना	3.5	3.4	शहडोल	2.8	2.7
रायसेन	3.6	3.4	श्योपुर	2.7	2.7
रीवा	3.4	3.4	बालाघाट	2.7	2.6
सीधी	3.4	3.4	छिंदवाड़ा	2.7	2.6
उमरिया	3.6	3.4	देवास	2.6	2.5
सागर	3.5	3.3	नर्मदापुरम	2.6	2.5
कटनी	3.3	3.2	नीमच	2.6	2.5
शाजापुर	3.2	3.2	जबलपुर	2.5	2.4
टीकमगढ़	3.3	3.2	दतिया	2.5	2.3
नरसिंहपुर	3.2	3.1	इंदौर	0.3	2.2
राजगढ़	3.2	3.1	मंदसौर	2.2	2.2
रतलाम	3.2	3.1	ग्वालियर	2.2	2.1
वेस्ट निमाड़	3.3	3.1	भोपाल	2.1	2.0
ईस्ट निमाड़	3.1	3.0			

रोजगार नहीं... निराशा की गारंटी

> केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली छमाही के लिए मनरेगा के तहत खर्च को अपने वार्षिक आवंटन के 60 प्रतिशत पर सीमित कर दिया है। सरकार का यह निर्णय मनरेगा की मूल अवधारणा के खिलाफ है। मनरेगा की मजदूरी में वृद्धि केवल आर्थिक आवश्यकता का विषय नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय और ग्रामीण सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मनरेगा मांग पर आधारित योजना है जिसमे कोई भी बेरोजगार काम मांग सकता है। जितने मजदूर काम मांगेंगे उतना काम देना होगा। इसमें कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए जब तक कि एक परिवार 100 दिन का रोज़गार पूरा नहीं कर लेता है। मांग के आधार पर काम मनरेगा की मूल भावना है। यह काम मजदूर वित्तीय वर्ष में किसी भी महीने में मांग सकता है। मनरेगा कानून के अनुसार इसमें कोई भी रुकावट मजदूरों के काम के कानूनी हक के खिलाफ है। इसी अवधारणा के चलते मनरेगा को वित्त मंत्रालय के सरकारी खर्च को नियंत्रण करने के नियमों से बाहर रखा गया था।

गौरतलब है कि वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2017 में मासिक/त्रैमासिक व्यय योजना (एमईपी/क्यूईपी) को लागू किया था जिसका तथाकथित मकसद मंत्रालयों को नकदी प्रवाह प्रबंधन और अनावश्यक उधारी से बचने में मदद करना था। अब तक ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत आने वाले महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को इसके दायरे से बाहर रखा गया क्योंकि ग्रामीण विकास मंत्रालय का तर्क था कि यह एक मांग आधारित योजना है, जिस पर खर्च की एक निश्चित सीमा तय करना व्यवहारिक नहीं है। लेकिन वित्त वर्ष 2025-26 की शुरुआत में, वित्त मंत्रालय ने ग्रामीण विकास मंत्रालय को निर्देश दिया है कि मनरेगा को भी एमईपी/क्यूईपी ढांचे के अंतर्गत रखा जाएगा। हालांकि भाजपानीत केंद्र सरकार के इस फैसले से किसी को हैरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह कोई इकलौता ऐसा फैसला नहीं है जो न केवल ग्रामीण भारत में रोजगार मुहैया करवाने वाले मनरेगा को कमजोर करेगा बल्कि इसके तहत रोजगार के अधिकार के भी खिलाफ है।

बजट में लगातार कटौती से लेकर भ्रष्टाचार से लड़ने के नाम पर नित नई जटिलताएं पैदा करने वाली तकनीक का बड़े पैमाने पर उपयोग किए जाने वाले सभी कदम मनरेगा के मौलिक सिद्धांत को कमजोर करना ही है। मोदी सरकार अपने इन कदमों से न केवल विभिन्न अध्ययनों द्वारा मनरेगा की साबित की जा चुकी उपयोगिता को अनदेखा करती है बल्कि इससे ग्रामीण आर्थिक संकट और बेरोजगारी की गंभीर समस्या से निपटने की सरकार की बेरुखी का भी पता चलता है। अगर उपरोक्त निर्णय लागू होता है तो इसका मतलब है कि इस वर्ष सितंबर के अंत तक इस योजना के लिए बजट के आवंटन 86,000 करोड़ का 60 प्रतिशत, केवल 51,600 करोड़ रुपए ही उपलब्ध होंगे। यह मनरेगा के अंतर्गत रोजगार सृजन को गंभीर तौर पर प्रभावित करेगा क्योंकि इसका एक बड़ा हिस्सा, 21,000 करोड़ रुपए पिछले वित्तीय वर्ष की लंबित देनदारियों के भुगतान में खर्च हुआ है। इस तरह के फैसले से जमीनी स्तर पर मांग के बावजूद मजदूरों को मनरेगा में काम के लिए बेहिसाब तरीकों

पश्चिम बंगाल में मनरेगा का संकट

उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल में मनरेगा के अंतर्गत पंजीकृत 2.56 करोड़ मजदूर, जिनके पास जॉब कार्ड हैं और जो अकुशल मजदूरी के लिए पूर्णतः पात्र भी हैं, पिछले तीन वर्षों से काम से महरूम हैं। इन मजदूरों को काम के कानूनी अधिकार (मनरेगा के अंतर्गत काम पाने के अधिकार) से भ्रष्टाचार के आरोपों से कारण वंचित रखा जा रहा है। हालांकि यह सत्य है कि देश के अधिकांश राज्यों में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में, मनरेगा के क्रियान्वयन में भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। इसके पीछे ठेकेदारों, स्थानीय नेताओं, जिनमें अधिकांश सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) से जुड़े हैं और विभिन्न स्तरों की नौकरशाही के बीच की सांठगांठ जिम्मेदार है। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन मजदूरों का इस भ्रष्टाचार से कोई लेना-देना नहीं है, उन्हें केंद्र सरकार द्वारा बीते तीन वर्षों से दंडित किया जा रहा है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई में सबसे पहली आवश्यकता होती है मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति, जो न तो केंद्र सरकार में दिखाई देती है और न ही पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार में। केंद्र सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से हल करने के बजाय राजनीतिक लाभ के लिए भ्रष्टाचार के नाम पर टीएमसी सरकार को निशाना बना रही है। वहीं टीएमसी सरकार खुद को पीड़ित बताकर ग्रामीण गरीबों की सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रही है। इन दोनों ही सरकारों की प्राथमिकता भ्रष्टाचार से लड़ना नहीं है। परिणामस्वरूप, सबसे अधिक पीड़ित वे मेहनतकश मजदूर हो रहे हैं जो न तो भ्रष्टाचार के जिम्मेदार हैं और न ही इसके पक्षधर, लेकिन उन्हें अपने ही कानूनी अधिकार से वंचित कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने मनरेगा, 2005 की धारा-27 का हवाला देते हुए पश्चिम बंगाल में योजना के लिए वित्तीय सहायता को रोक दिया। यह धारा योजना के क्रियान्वयन में नियमों के उल्लंघन की स्थिति में धनराशि रोकने का अधिकार देती है।

से हतोत्साहित किया जाएगा।

दरअसल मनरेगा को कमजोर करने में सबसे बड़ा कारण लगातार बजट में कमी और समय पर आवंटन राज्यों तक न पहुंचना ही है। इससे ही सभी तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। हालांकि हमारी वित्त मंत्री समय-समय पर मीडिया में कहती रहती हैं कि मनरेगा के लिए फंड की कोई कमी नहीं है और काम की मांग के अनुसार इसमें कोई कमी नहीं आने दी जाएगी लेकिन यह दावा सच्चाई से कोसों दूर है। फंड की कमी के चलते ही अघोषित तरीके से काम की मांग को नियंत्रित किया जाता है। अलग-अलग तरीकों से मजदूरों को भी हतोत्साहित किया जाता है। यह बात सरकार की संसदीय समिति की 2024 की एक रिपोर्ट में भी एक बड़ी कमजोरी के तौर पर चिन्हित की गई है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि आवश्यकता के आधार पर संसाधनों की पूर्ति की जा सकती है लेकिन वर्ष के शुरुआत में अनुमानित बजट में ही फंड में कटौती करने से मनरेगा कार्यान्वयन के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलू पर व्यापक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए कमेटी ने जमीनी स्तर पर इस योजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए फंड की कमी को एक बहुत बड़ी बाधा माना है। मनरेगा के लिए शुरू में ही उपयुक्त बजट का प्रावधान किया जाना चाहिए जिसका आधार पिछले वर्ष के खर्च का चलन हो सकता है। गौरतलब है कि पीपुल्स एक्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट गारंटी सहित देश के कई अर्थशास्त्रियों ने मनरेगा के लिए प्रतिवर्ष कम से कम 2.64 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटन सुझाया है। यहां तक कि अपनी एक रिपोर्ट में विश्व बैंक ने सिफारिश की है कि इस कार्यक्रम के लिए देश की जीडीपी का कम से कम 1.7 प्रतिशत आवंटित किया जाना चाहिए। इसके विपरीत, वर्ष 2024-25 में मनरेगा के लिए किया गया आवंटन जीडीपी का मात्र 0.26 प्रतिशत ही है। इस वर्ष के बजट (2025-26) में भी केवल 86000 करोड़ रुपए ही मनरेगा के लिए रखे गए हैं। यह योजना की व्यापक जरूरतों और ग्रामीण भारत की बढ़ती आर्थिक असुरक्षा के संदर्भ में बेहद अपर्याप्त है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार की प्राथमिकताओं में ग्रामीण गरीबों की आजीविका सुरक्षा को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जा रहा है।

इसी तरह ग्रामीण विकास और पंचायती राज पर संसद की स्थायी समिति ने 22 मई को संसद में प्रस्तुत अपनी आठवीं रिपोर्ट में यह उजागर किया कि मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी भुगतान में देरी अब भी एक गंभीर समस्या बनी हुई है। यह देरी उन ग्रामीण मजदूरों को प्रभावित कर रही है जो अपनी आजीविका के लिए इस योजना पर निर्भर हैं। देश की सरकार संसद की ग्रामीण विकास और पंचायती राज पर संसद की स्थायी समिति द्वारा लगातार दिए गए सुझावों को अनदेखा करती आ रही है लेकिन मनरेगा को कमजोर करने का कोई भी सुझाव तत्परता से लागू करती है।

इसी तरह संसद की ग्रामीण विकास पर गठित एक समिति ने मनरेगा के तहत मजदूरी को कम से कम 400 रुपए प्रतिदिन करने की सिफारिश की है। इस समिति का मानना है कि वर्तमान दरें दैनिक बुनियादी खर्चों को पूरा करने के लिए भी अपर्याप्त हैं और एक न्यायसंगत मजदूरी के बिना यह योजना ग्रामीण मजदूरों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के अपने उद्देश्य में विफल हो रही है। इसी वर्ष मार्च महीने में संसद में पेश की गई रिपोर्ट में भी समिति ने यह सिफारिश की कि ग्रामीण मजदूरी पर महंगाई के वास्तविक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए मजदूरी दरों में संशोधन किया जाए। एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो काफी समय से यह समिति उठाती आ रही है वह है मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी दरों की गणना के विसंगतिपूर्ण तरीके के बारे में।

दरअसल मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी दरों की गणना खेत मजदूरों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-एएल) के आधार पर की जाती है। अभी तक इसके लिए 1 अप्रैल 2009 की मूल दरों को आधार बनाकर संशोधन किया जाता है। संसद की स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में इस पद्धति की तीव्र आलोचना करते हुए कहा है कि 2009-2010 को आधार वर्ष मानकर की जा रही गणना अब अप्रासंगिक और निष्प्रभावी हो चुकी है, जो मौजूदा महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत के अनुरूप कोई उचित आंकड़ा देने में असमर्थ है। इससे पहले यही तर्क महेंद्र देव समिति ने भी दिया था और सुझाव दिया गया था कि मनरेगा मजदूरी सूचकांक का आधार वर्ष 2014 होना चाहिए।

● श्याम सिंह सिकरवार

गुजरात में मनरेगा घोटाले, भाजपा के दोहरे मापदंड

पिछले कुछ दिनों में भाजपा की भ्रष्टाचार की लड़ाई के मॉडल की पोल देश की जनता के सामने खुल गई है। लड़ाई तो दूर की बात है लेकिन भाजपा के नेता भ्रष्टाचार के नित नए कीर्तिमान बना रहे हैं। वैसे देश में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो नवउदारवादी नीतियों का चर्म है जिसके चलते देश की जनता के संसाधन शासक वर्ग के कुछ कॉर्पोरेट घरानों और विदेशी पूंजी को सौंपे जा रहे हैं लेकिन पिछले कुछ महीनो में पूरे देश में भाजपा के विकास मॉडल के रूप में प्रचारित राज्य गुजरात में मनरेगा में हो रहे कई सौ करोड़ रुपए के घोटाले उजागर हुए हैं। ऐसे ही एक मामले में गुजरात के दाहोद जिले में राज्य के पंचायत और कृषि मंत्री बचू खाबड़ के बेटे बलवंत खाबड़ को दाहोद पुलिस ने मनरेगा में 70 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक खुलासों में यह सामने आया है कि यह घोटाला पूरी तरह एक फर्जी नेटवर्क पर आधारित था, जिसमें सड़कों, बंधों और अन्य सार्वजनिक निर्माण कार्यों जैसे अधोसंरचना परियोजनाओं को केवल कागजों पर दिखाया गया था। मनरेगा के अंतर्गत आदिवासी समुदायों के लिए नियोजित रोजगार से जुड़ी धनराशि को कथित रूप से जाली दस्तावेजों के माध्यम से चुराया गया और इसे उन एजेंसियों को भेजा गया जिनका संबंध मंत्री के बेटों से था। इस घोटाले में मंत्री बचू खाबड़ के दोनों बेटे, बलवंत और किरण शामिल पाए गए हैं। पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार से निपटने के लिए सरकारों की वास्तविक मंशा को समझने के लिए यह जरूरी है कि सोशल ऑडिट की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की जाए।

हथियारों के लाइसेंस भी नकली

मप्र वाकई अजब है, गजब है। यहां कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसा ही एक मामला सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल, प्रदेश में नकली ड्राइविंग लाइसेंस, नकली वोटर कार्ड, नकली आधार कार्ड बनाने के कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन अब हथियारों के लाइसेंस भी नकली मिलने का मामला सामने आया है। यह मामला ग्वालियर-चंबल अंचल में सामने आया है।

ग्वालियर-चंबल अंचल में बंदूकों का शौक किसी से भी छिपा नहीं है। शायद यही वजह है कि अब दूध, पनीर और मावा की तरह चंबल में हथियार के लाइसेंस भी नकली बनने लगे हैं। देश में संभवत: ये पहली बार होगा जब नकली हथियार लाइसेंस पकड़ में आए हैं। वह भी तीन-तीन। इन दिनों ग्वालियर में प्रशासन का आर्म्स डिपार्टमेंट सकते में है। क्योंकि ग्वालियर में कोई असली जैसे हुबहू नकली लाइसेंस तैयार कर रहा है। कई लोग ठगों के झांसे में आकर नकली लाइसेंस थामे बंदूकों के साथ घूम रहे हैं। ऐसे कुछ मामले ग्वालियर कलेक्ट्रेट में भी पहुचे हैं। जिसकी एक बड़ी वजह सामने आई है। आपको बता दें कि, शस्त्र लाइसेंस का पूरा सिस्टम ऑनलाइन हो चुका है और इसमें दर्ज होने वाली जानकारी भी सॉफ्टवेयर के जरिए पहले तय फॉर्मेट में दर्ज की जाती हैं। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर अभी जांच की जा रही है। इन लाइसेंस धारियों को बयान लेने के लिए बुलाया गया है। उन्होंने यह लाइसेंस कहां से और किसके द्वारा बनवाए हैं इसकी जानकारी भी जुटाई जा रही है। असल में पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब नकली लाइसेंस को असली समझकर अपने लाइसेंस की डायरी लेने के लिए एक आवेदक ने कलेक्ट्रेट में फोन किया। जब उसे बताया गया कि इस तरह का कोई भी लाइसेंस कलेक्ट्रेट में नहीं है, तब वह कलेक्ट्रेट की आम शाखा में पहुंचा और पूरा माजरा समझ में आ गया।

पिछले एक साल से ग्वालियर-चंबल अंचल में शस्त्र लाइसेंस बनाने पर रोक लगी हुई है। क्योंकि काफी समय से अंचल में आत्मरक्षा के लिए जारी होने वाले लाइसेंसी हथियारों से कुछ जगहों पर आपराधिक गतिविधियां पाई गई हैं। जिसके बाद से ही बंदूक-पिस्टल जैसे हथियार के लाइसेंस नहीं बनाए जा रहे हैं। इसी बात का फायदा अब हथियार माफिया उठा रहे हैं और लोगों को नकली लाइसेंस बनाकर दे रहे हैं। ऐसे ही तीन लाइसेंस के आधार पर प्रशासन जांच में जुटा हुआ है। जांच में पता चला है कि, ऐसी तीन डायरी अब तक सामने आ चुकी हैं जो इस फर्जीवाड़े का प्रमाण हैं। इन लाइसेंस डायरियों को हाथ से लिखा गया है, इन लाइसेंस पर अपर कलेक्टर और कलेक्टर के सिग्नेचर और सील भी लगाई गई है। तीनों ही लाइसेंस आवेदक ग्वालियर के रहने वाले हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि इन तीनों ही लोगों से लाइसेंस बनवाने के नाम पर ठगी की गई होगी। इस मामले की जांच कर रहे एडीएम टीएन सिंह ने बताया कि इस फर्जीवाड़े के बारे में सोशल मीडिया के जरिए पता चला। कुछ स्क्रीन शॉट्स भी उनके पास आए हैं जो इन नकली लाइसेंसों के थे। जिनमें दो 315 बोर की बंदूक के लाइसेंस और एक पिस्टल का लाइसेंस था। बताया गया कि यह बाह्य कलेक्ट्रेट से जारी हुए हैं। लेकिन इस तरह के कोई भी लाइसेंस यहां से जारी नहीं हुए। इस जानकारी के आधार पर हमने जांच शुरू की है और इन लाइसेंस धारकों से संपर्क कर उन्हें बुलाया है कि जिससे इस फर्जीवाड़े की तह तक जाया जा सके।

ग्वालियर के तीन लोगों के पास अब तक लाइसेंस और डायरी मिली हैं। पहला गिरगांव के रहने वाले ऐंदल सिंह के नाम से पिस्टल लाइसेंस बनाया गया। इस लाइसेंस की मियाद 27 मार्च 2027 तक है। डायरी को हाथ से भरा गया, कारतूसों की संख्या भी हाथ से दर्ज की गई है और इस पर एडीएम की सील और हस्ताक्षर भी किए गए हैं। इसमें बीच-बीच में डीएम के भी सिग्नेचर ट्राई किए हैं। दूसरा पिंटो पार्क के न्यू राम विहार कॉलोनी के रहने वाले अमित सिंह राजावत के नाम पर भी एक लाइसेंस बनाया गया है। इसकी यूनिक आईडी में तारीख 2027 की गई है। कारतूस लेकर सभी जरूरी जानकारियां भी हाथ से दर्ज की गई हैं और ठीक पहले लाइसेंस की तरह इसमें भी सील और सिग्नेचर लगाए गए हैं। तीसरा लाइसेंस ग्वालियर के डीडी नगर में रहने वाले रामनिवास सिंह नाम के व्यक्ति का बनाया गया है। इस पर लाइसेंस धारक की फोटो लगाई गई है और जिसमें यूनिक आईडी की तारीख 2026 की गई है। ये सभी लाइसेंस इस तरह तैयार किए गए हैं कि, असली और नकली का फर्क करना बहुत मुश्किल है।

● **लोकेश शर्मा**

सब्जियों की तरह बिक रही है लाइसेंस डायरी

ग्वालियर में पिस्टल रिवाल्वर के तीन नकली लाइसेंस मिले हैं। लाइसेंस सामने आने के बाद से हथियार लाइसेंस की प्रणाली कटघरे में आई है। पुलिस ने दो ठगों पर केस भले ही दर्ज कर लिया है, लेकिन इस सिस्टम में लीकेज है। बता दें कि हथियार लाइसेंस जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज जो डायरी के रूप में बनते हैं, वहीं डायरी लाइसेंसी हथियार विक्रेताओं के यहां सब्जी जैसी मिलती हैं। 150, 200 रुपए में इसे कोई भी खरीद सकता है, कोई पूछने वाला नहीं है। बता दें कि ग्वालियर में तीन फर्जी लाइसेंस के मामले में यही हुआ है, ठगों ने ऑनलाइन फार्म व मैन्युअल फार्म के जरिए झांसा देना शुरू किया। बाजार से डायरी खरीदकर हाथों से भर ली। जानकारी इस तरह भरी गई कि वह असली जैसी दिखे। अब लाइसेंस डायरी में सॉफ्टवेयर जनरेटेड स्लिप चिपकाई जाती है, लेकिन अभी भी यह स्लिप कोई और तैयार करके चिपका दे तो इसका कोई खास सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है। बता दें कि ग्वालियर में तीन नकली लाइसेंस के मामले सामने आने के बाद प्रशासन व पुलिस में हड़कंप मच गया। इस मामले में एफआइआर दर्ज की गई है। पुलिस ने पड़ताल शुरू कर दी है। तीन लोगों से एक से डेढ़-डेढ़ लाख रुपए ऐंठ लिए गए।

मप्र के शिक्षा के स्तर में सुधार नहीं

मप्र की जिलेवार स्थिति

2023-24 की रिपोर्ट में प्रचेस्टा ग्रेड-1 में 6 जिले, प्रचेस्टा-2 में 44 जिले और 5 जिले प्रचेस्टा-3 में शामिल हैं। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पीजीआई-डी 2023-24 की बात की जाए तो प्रचेस्टा-1 में 6 जिले शामिल हैं। इनमें भिंड, दमोह, नरसिंहपुर, पन्ना, सीधी, रायसेन हैं। वहीं प्रचेस्टा-2 में 44 जिलों में सागर, भोपाल, छतरपुर, शहडोल, सीहोर, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, छिंदवाड़ा, बैतूल, नीमच, विदिशा, निवाड़ी, होशंगाबाद, उज्जैन, मुरैना, बालाघाट, टीकमगढ़, गुना, राजगढ़, डिंडोरी, देवास, खंडवा, मंदसौर, शाजापुर, सतना, आगर मालवा, धार, सिवनी, दतिया, श्योपुर, मंडला, कटनी, हरदा, अशोकनगर, रीवा, बुरहानपुर, उमरिया, अनूपपुर, रतलाम और सिंगरौली शामिल है। प्रचेस्टा-3 में 5 जिले खरगोन, शिवपुरी, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ शामिल हैं। पीजीआई-डी में, पीजीआई स्कोर के लिए नामकरण को विभिन्न ग्रेड में बांटा गया है। पीजीआई-डी में उच्चतम प्राप्त करने का ग्रेड उत्कर्ष है, जो उस श्रेणी में कुल अंकों के 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले जिलों के लिए है। उत्तम-1 उन जिलों के लिए है जिनका पीजीआई स्कोर 81 प्रतिशत से 90 प्रतिशत है। उत्तम-2 में 71 प्रतिशत से 80 प्रतिशत और उत्तम-3 में 61 प्रतिशत से 70 प्रतिशत है। प्रचेस्टा-1 के लिए 51 प्रतिशत से 60 प्रतिशत, प्रचेस्टा -2 के लिए 41 प्रतिशत से 50 प्रतिशत, प्रचेस्टा-3 के लिए 31 प्रतिशत से 40 प्रतिशत, आकांक्षी-1 के लिए 21 प्रतिशत से 30 प्रतिशत, आकांक्षी-2 के लिए 11 प्रतिशत से 20 प्रतिशत और आकांक्षी-3 10 प्रतिशत तक के स्कोर के लिए है। इस प्रकार यह ग्रेडिंग दर्शाती है कि किस जिले में स्कूली शिक्षा का शैक्षणिक स्तर कैसा है और हर साल यह उसके प्रदर्शन के आधार पर बदलता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 लागू होने के बाद देशभर में स्कूली शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की दिशा में प्रयास तेज हुए हैं। इस दिशा में मप्र ने स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और व्यवस्था में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है। केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 रिपोर्ट 2023-24 में दिल्ली का औसत समग्र स्कोर 532.8 अंक रहा, जो पिछले वर्ष (2022-23) में 508.9 था। यानी इस वर्ष मप्र ने 23.9 अंकों की छलांग लगाई गई है। इसके चलते मप्र का ग्रेड आकांक्षी-2 (11 से 20 प्रतिशत) से बढ़कर आकांक्षी-2 (21 से 31 प्रतिशत) में पहुंच गया है।

भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा की परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पीजीआई 2.0 रिपोर्ट जारी की है। इसमें मप्र को आकांक्षी-1 ग्रेड मिला है। इस ग्रेड के अनुसार अन्य राज्यों की तुलना में मप्र का शैक्षणिक स्तर अच्छा नहीं है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट में पिछड़े सभी राज्यों की शैक्षिक नीतियों पर सवाल उठाए गए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट जारी की है। 2023-24 के लिए तैयार की गई इस रिपोर्ट में स्कूली शिक्षा में मप्र सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शुमार है। मप्र उन 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल है जो 2023-2024 पीजीआई रिपोर्ट में आकांक्षी-1 ग्रेड में शामिल है। पीजीआई रिपोर्ट के अनुसार मप्र ने पिछले 2 सालों में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं की है। यह रिपोर्ट 2022 से 2024 में मप्र की डाउनग्रेड रैंकिंग को दर्शाती है। इन 2 सालों में मामूली अंतर देख सकते हैं। यह केवल आकांक्षी-2 से आकांक्षी-1 तक आगे बढ़ा है। 2022-2023 की रिपोर्ट के अनुसार, नरसिंहपुर, सीधी और पन्ना जैसे जिलों ने बेहतर प्रदर्शन किया है और 2023-2024 की रिपोर्ट में इन्हें प्रचेस्टा-1 में रखा गया है। इसके अलावा आगर मालवा, रतलाम, बुरहानपुर, उमरिया, शिवपुरी और रीवा जैसे जिलों ने 2022-2023 से बेहतर प्रदर्शन किया है और उन्हें 2023-2024 में प्रचेस्टा-2 में रखा गया है। इनमें अलग-अलग 6 कैटेगिरी में दमोह जिले ने अधोसरंचना और डिजिटल लर्निंग की कैटेगिरी में 600 में से 303 अंक हासिल कर प्रचेस्टा सूची में स्थान हासिल किया है।

भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा की परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पीजीआई जारी कर जिलेवार स्थिति को बताया है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट में राज्यवार सभी स्कूलों की परफॉर्मेंस को 6 कैटेगिरी में बांटा है। इन कैटेगिरी में परिणाम, प्रभावी कक्षा लेनदेन, बुनियादी ढांचा सुविधाएं और छात्र अधिकार, स्कूल सुरक्षा और बाल संरक्षण, डिजिटल लर्निंग और शासन प्रक्रिया शामिल है। इन कैटेगिरी को आगे 11 डोमेन में बांटा गया है। इसमें सीखने के परिणाम और गुणवत्ता, पहुंच परिणाम, शिक्षक उपलब्धता और व्यावसायिक विकास परिणाम, सीखने का प्रबंधन, सीखने की गतिविधियां, बुनियादी ढांचा सुविधाएं, छात्र अधिकार, स्कूल सुरक्षा और बाल संरक्षण, डिजिटल लर्निंग, फंड कन्वर्जेंस और उपयोग, उपस्थिति निगरानी प्रणाली और स्कूल नेतृत्व विकास शामिल है।

मप्र का 2022-23 में स्कोर 508.9 रहा और उसका ग्रेड आकांक्षी-2 था। वहीं 2023-2024 में स्कोर 532.8 रहा और ग्रेड आकांक्षी-1 हो गया। यानी प्रदेश में शिक्षा के स्तर में मामूली सुधार हुआ है। इस प्रकार परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में 2022-23 में 3 जिले प्रचेस्टा-1 ग्रेड में, 39 जिले प्रचेस्टा-2 में और 13 जिले प्रचेस्टा-3 ग्रेड में थे। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पीजीआई-डी 2022-23 के लिए सभी 6 श्रेणियों के मप्र की जिलेवार स्थिति बताई गई है। इसमें प्रचेस्टा-1 में 3 जिले दमोह, भिंड, रायसेन शामिल हैं। वहीं प्रचेस्टा-2 में 39 जिले शामिल हैं। इनमें नरसिंहपुर, पन्ना, सागर, भोपाल, छतरपुर, सीधी, छिंदवाड़ा, इंदौर, शहडोल, बैतूल, ग्वालियर, विदिशा, सीहोर, होशंगाबाद, दतिया, जबलपुर, राजगढ़, बालाघाट, टीकमगढ़, नीमच, अशोकनगर, गुना, सतना, देवास, उज्जैन, खंडवा, शाजापुर, सिवनी, निवाड़ी, मुरैना, मंदसौर, धार, डिंडोरी, श्योपुर, हरदा, कटनी और मंडला शामिल हैं। वहीं प्रचेस्टा-3 में 13 जिलों में आगर-मालवा, रतलाम, बुरहानपुर, उमरिया, शिवपुरी, रीवा, खरगोन, सिंगरौली, अनूपपुर, बड़वानी, अलीराजपुर और झाबुआ शामिल हैं।

● **अरविंद नारद**

मप्र में जिस उत्साह के साथ सरकारी कार्यालयों में ई-ऑफिस सिस्टम लागू कराया गया है, उसके परिणाम उसके अनुसार नहीं मिल रहे हैं। आलम यह है कि न तो मंत्रियों और न ही अधिकारियों की इसमें रुचि है। इसका परिणाम यह देखने को मिल रहा है कि ई-ऑफिस सिस्टम में बड़े जिले और संभाग पिछड़े हुए हैं, वहीं छोटे जिले आगे हैं।

पटरी पर नहीं आया ई-ऑफिस सिस्टम

मप्र में 1 जनवरी से लागू ई-ऑफिस सिस्टम में बड़े जिले और संभागों के अधिकारियों की ज्यादा रुचि दिखाई नहीं दे रही है। मंत्रालय की बात करें तो केवल मुख्य सचिव का दफ्तर ही 100 फीसदी ई-ऑफिस में तब्दील हुआ है, जबकि मुख्यमंत्री सचिवालय में भी 30 फीसदी फाइलों का मूवमेंट मैन्युअली हो रहा है। बात करें, मंत्रियों के दफ्तरों की तो 30 में से केवल 5 मंत्रियों का दफ्तर ही ई-ऑफिस में तब्दील हुआ है। नेशनल इनफोर्मेटिक्स सेंटर ने मंत्रालय समेत विभागाध्यक्ष कार्यालय, संभागीय कार्यालय और जिलों में ई-ऑफिस सिस्टम का एनालिसिस किया है। ये रिपोर्ट सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपी है। 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक किए गए एनालिसिस में सामने आया कि 55 जिलों में से केवल 15 जिलों में ही 500 से ज्यादा ई-फाइलें क्रिएट हुई हैं, बाकी जिलों में ये आंकड़ा 500 से नीचे है। इसी तरह विभागों की बात करें तो सामान्य प्रशासन विभाग ई-ऑफिस सिस्टम में अव्वल है, जबकि प्रवासी भारतीय विभाग में सिस्टम चालू ही नहीं हुआ है।

ई-ऑफिस एक ऑनलाइन सिस्टम है। इसमें फाइलों के मूवमेंट के साथ अधिकारी-कर्मचारियों का पूरा डेटाबेस, उनकी छुट्टी, दौरे, गोपनीय चरित्रावली और संपत्ति के विवरण को डिजिटलाइज करने के निर्देश हैं। इसके लिए नेशनल इनफोर्मेटिक्स सेंटर ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जिसमें ये सारी सुविधाएं मौजूद हैं। इसका सबसे अहम हिस्सा फाइलों का मूवमेंट है, क्योंकि ये सीधे आम लोगों से जुड़ा मामला है। सरकारी दफ्तरों में फाइलों के मूवमेंट में ही सबसे ज्यादा देरी होती है। कई-कई सालों तक फाइलें धूल खाती हैं, आगे नहीं बढ़तीं। ई-ऑफिस सिस्टम में अधिकारी से लेकर कर्मचारियों को अपने कम्प्यूटर पर बैठकर ही फाइलें निपटानी हैं। इससे ये भी पता चलता है कि कौनसी फाइल किस अफसर के पास कब से लंबित है, उसकी क्या वजह है? यानी फाइल के मूवमेंट को रियल टाइम ट्रैक किया जा सकता है। मंत्रालय, विभागों और जिला एवं संभाग स्तर के कार्यालयों को ई-फाइलिंग सिस्टम को लागू करने के लिए दो काम करने थे। पहला नई ई-फाइलें क्रिएट करना और दूसरा पी-फाइलें क्रिएट करना, यानी जो पुरानी फाइलें हैं, उन्हें स्कैन कर डिजिटल फॉर्मेट तैयार करना। इसके बाद इसी डिजिटल फॉर्मेट को आगे बढ़ाना। हर फाइल की लोकेशन अपडेट रहेगी, जिससे फाइलों का तेजी से मूवमेंट होगा। ई-ऑफिस सिस्टम में लिपिक से लेकर मुख्य सचिव तक फाइल निपटाने की समय सीमा तय की गई है। तय समय पर फाइल आगे नहीं बढ़ाई गई, तो संबंधित अफसर को इसकी वजह भी बतानी पड़ेगी। बिना किसी कारण के फाइल को नहीं रोका जा सकेगा। इसके बाद भी फाइलें लंबित रहती हैं, तो संबंधितों पर कार्रवाई की जा सकेगी। इमरजेंसी में एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में अधिकारियों को फाइल लेकर आना-जाना नहीं पड़ेगा। एक क्लिक पर फाइल सामने स्क्रीन पर मिल जाएगी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव गृह, सामान्य प्रशासन समेत 10 अहम विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। उनके भी कई विभागों में ई-ऑफिस सिस्टम पूरी तरह से लागू नहीं हो सका है। मुख्यमंत्री सचिवालय में 70 फीसदी काम पेपरलैस है। सूत्र कहते हैं कि मुख्यमंत्री के लिए मैन्युअल फाइल व्यवस्था को पूरी तरह से बंद भी नहीं किया है। मंत्रालय सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री के साइन की कॉपी कर कोई इसका दुरुपयोग न कर सके, इसका भी ख्याल रखा गया है। इसलिए कुछ अहम फाइलों को मैन्युअली ही तैयार किया जाता है। ऑनलाइन सुरक्षा को और ज्यादा पुख्ता कर धीरे-धीरे फाइलों का मैन्युअल मूवमेंट भी ऑनलाइन

पीएचक्यू बना ई-ऑफिस

मप्र पुलिस मुख्यालय अब मंत्रालय की तर्ज पर पूरी तरह ई-ऑफिस में तब्दील हो चुका है। यह कदम पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना की पहल पर उठाया गया है। मकवाना का अगला लक्ष्य है- इस व्यवस्था को जिलों तक पहुंचाना, ताकि मैन्युअल फाइल भेजने की प्रक्रिया को पूरी तरह खत्म किया जा सके। मूल रूप से डीजीपी ने सभी शाखाओं को निर्देश दिया था कि 31 मार्च तक ई-ऑफिस प्रणाली पूरी तरह लागू कर ली जाए, लेकिन कई शाखाएं समयसीमा में यह कार्य पूरा नहीं कर सकीं। इसके बाद उन्होंने अंतिम रूप से 15 अप्रैल तक इसकी क्रियान्वयन की समयसीमा तय की। सख्त निर्देशों के बाद अब पुलिस मुख्यालय में ई-ऑफिस प्रणाली लागू हो चुकी है। अब मकवाना की योजना है कि पीएचक्यू को राज्य के सभी जिलों की पुलिस शाखाओं से ई-ऑफिस के जरिए जोड़ा जाए। इसके लिए दिसंबर 2025 तक का लक्ष्य रखा गया है। तैयारी है कि इस संबंध में विभागीय आदेश जल्द ही जारी किया जाएगा। ई-ऑफिस प्रणाली के तहत पुलिस मुख्यालय को मंत्रालय से जोड़ने की योजना भी बनाई जा रही है। गौरतलब है कि मुख्य सचिव अनुराग जैन ने पहले ही 1 जनवरी 2025 से मंत्रालय को पूरी तरह ई-ऑफिस बना दिया है।

किया जाएगा। मंत्रालय सूत्रों का कहना है कि मंत्रालय में मुख्य सचिव के दफ्तर से लेकर निचले स्तर का कामकाज ऑनलाइन हो चुका है। फाइलों का मूवमेंट ई-फाइलिंग सिस्टम के जरिए ही हो रहा है। मगर, जो फाइलें स्वीकृति के लिए मंत्री को भेजी जाती हैं, उन्हें मैन्युअली तैयार करना पड़ता है। मंत्रियों के पास फाइल पहुंचती हैं, वे इन फाइलों पर टीप लिखकर वापस विभागों को लौटा देते हैं। इसके बाद उसे फिर से ई-फाइलिंग सिस्टम में अपलोड करना पड़ता है। इसके लिए फाइल के मुख्य पृष्ठ को स्कैन करना पड़ता है। इससे एक फाइल की कई सारी डिजिटल कॉपियां बन रही हैं। सूत्रों का कहना है कि मंत्रियों के घर और दफ्तरों पर जो स्टाफ तैनात है, उन सभी को ई-ऑफिस सिस्टम की ट्रेनिंग दी जा चुकी है।

विभागों की बात करें तो 56 विभागों में सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त, वन, स्कूल शिक्षा और कृषि ये वो टॉप 5 विभाग हैं, जहां तेजी से ई-ऑफिस सिस्टम को अपनाया जा रहा है। एनआईसी की 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक की रिपोर्ट के मुताबिक सामान्य प्रशासन विभाग में 58 हजार से ज्यादा ई-फाइलों का मूवमेंट हुआ है जबकि 4320 पी-फाइल (पेपर) का मूवमेंट हुआ है। दूसरे नंबर पर वित्त विभाग है, जहां 25 हजार ई-फाइलों का मूवमेंट हुआ है। हालांकि, बाकी विभागों में ई-फाइल मूवमेंट की रफ्तार धीमी है। 56 में से 6 विभागों में ही 10 हजार से ज्यादा ई-फाइलों का मूवमेंट हुआ है। 5 हजार से ज्यादा ई-फाइलों का मूवमेंट करने वाले 10 विभाग हैं। 25 मंत्रियों के दफ्तरों में पेपरलैस काम हो रहा है, मगर उसकी रफ्तार बेहद धीमी है। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का दफ्तर पूरी तरह से ई-ऑफिस हो चुका है। वे कहते हैं कि इस सिस्टम से सरकारी दफ्तरों में पारदर्शिता आई है। काम तेजी और सुरक्षित तरीके से हो रहा है। कागजों को न संभालने का झंझट है और न ही उनके फटने या नष्ट होने का डर है। दस्तावेजों को लंबे समय तक सुरक्षित रखना है तो डिजिटल फॉर्मेट ही एकमात्र विकल्प है। वे बताते हैं कि जब मैं राजस्व मंत्री था, तब जिलों के कलेक्टर कार्यालय में नकल के दस्तावेज

पीले कपड़ों में रखे हुए थे। राजस्व मंत्री रहते हुए मैंने सारे रिकॉर्ड को डिजिटल करवा दिया था। अब एक क्लिक पर आप राजस्व का बरसों पुराना रिकॉर्ड निकाल सकते हैं।

मंत्रालय के बाद 30 दिनों के भीतर विभाग प्रमुख (संचालनालय) में भी ई-ऑफिस सिस्टम लागू किया गया था। जमीनी स्तर पर सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग का काम इन्हीं के जरिए होता है। ई-फाइल मूवमेंट में पीएचई विभाग का जल निगम टॉप पर है। चार महीने में यहां 1 लाख से ज्यादा ई-फाइलों का मूवमेंट हुआ है। दूसरे नंबर पर कोष एवं लेखा संचालनालय है, यहां 50 हजार से ज्यादा ई-फाइलों का मूवमेंट हुआ है। इसके बाद मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, नेशनल हेल्थ मिशन, मप्र स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और फिर भोपाल पुलिस कमिश्नर कार्यालय आता है। कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड और एक्साइज, टेक्निकल और हायर एजुकेशन डायरेक्टोरेट में भी फाइलों का ज्यादातर मूवमेंट ई-फाइलिंग के तौर पर हो रहा है। वहीं, पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ, जल संसाधन विभाग के चीफ इंजीनियर का ऑफिस, एडवोकेट जनरल और चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर के दफ्तर में चार महीनों में केवल 1-1 ई-फाइल का मूवमेंट हुआ है। हैरानी की बात ये है कि 68 विभाग प्रमुखों के दफ्तरों में ई-फाइल मूवमेंट शून्य है। इनमें सभी रेंज के आईजी और डीआईजी दफ्तर, एमपी पुलिस एकेडमी, गौ संवर्धन बोर्ड, पिछड़ा वर्ग आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, वक्फ ट्रिब्यूनल, विद्युत नियामक आयोग, लोकायुक्त, एमपी भवन, राज्य सूचना आयोग, आनंद संस्थान, सेंट्रल और जिला जेल, एमपी बोर्ड और मप्र लोकसेवा आयोग जैसे अहम विभाग शामिल हैं। जिले और संभागों की बात करें तो छोटे जिले ई-ऑफिस सिस्टम लागू करने में अव्वल हैं। बैतूल में सबसे ज्यादा ई-फाइलें क्रिएट हुई हैं और यहां फाइलों का मूवमेंट भी ई-फाइल के तौर पर हुआ है। इसके बाद नर्मदापुरम, बालाघाट, अनूपपुर और हरदा है। जहां तक बड़े जिलों की बात करें तो ग्वालियर 9वें, इंदौर 26वें, भोपाल 27वें, उज्जैन 38वें और जबलपुर 42वें नंबर पर है। अलीराजपुर, पन्ना, मैहर, छतरपुर और पांढुर्ना जिलों में ई-फाइल सिस्टम की हालत बेहद खराब है। यहां न तो ई-फाइल उतनी संख्या में क्रिएट की गईं और न ही इनका मूवमेंट हैं।

● **धर्मेंद्र कथूरिया**

मप्र की डिजिटल विधानसभा

मप्र की 16वीं विधानसभा के छठवें सत्र यानि मानसून सत्र की आहट आ रही है। मार्च के बाद अब जुलाई के आखिरी दिनों में शुरू होने के आसार नजर आ रहे हैं। इस बार विधानसभा में ई-विधान के जरिये पूरी कार्रवाई की जानी है, इसके लिए भी तैयारियां तेजी से चल रही हैं। विधानसभा सचिवालय ने इस सत्र के लिए पूरी तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर तथा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के बीच चर्चा के बाद सत्र की अवधि और सत्र शुरू करने की तारीख पर निर्णय हो जाएगा। ई-विधान को लेकर विधानसभा सचिवालय विभागीय तौर पर तेजी से काम कर रहा है। ई-विधान की तैयारियों के बीच विधानसभा सचिवालय द्वारा 35 ऑल इन वन कम्प्यूटर खरीदे जाने हैं। इस कम्प्यूटर की खास बात यह होती है कि इसमें सीपीयू, मॉनीटर, बैटरी बैकअप, स्पीकर सभी एक साथ होते हैं। इसके लिए अलग से पार्ट्स नहीं खरीदने पड़ते। भारत सरकार डिजिटल इंडिया की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसलिए ई-विधान को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसे एनईवीए (नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन) कहा जाता है। भारत सरकार मिशन मोड में इस परियोजना पर काम कर रही है। सभी राज्य विधान मंडलों को डिजिटल और कागज रहित बनाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। इसका टारगेट सभी राज्य विधान मंडलों को पेपरलेस करना, विधायी प्रक्रिया को ऑनलाइन करना है। जिसमें प्रश्न पूछना, विधेयक पेश करना और चर्चा करना शामिल है।

खेला लकड़ी का

बड़े काम की सागौन, लेकिन...

जहां भी मजबूत और टिकाऊ लकड़ी की बात होती है, सागौन उस सूची में सबसे ऊपर रहता है। इमारती लकड़ी का राजा कहा जाने वाला सागौन (टेक्टोना ग्रैंडिस) दुनिया के सबसे मूल्यवान उष्णकटिबंधीय हार्डवुड में से एक है और इसका उपयोग जहाज निर्माण से लेकर भवन निर्माण और महंगे फर्नीचर इत्यादि के लिए होता है। दुनिया भर के 95 प्रतिशत से अधिक सागौन संसाधन एशिया में हैं और उनमें से 35 प्रतिशत सागौन के बाग (प्लांटेड फॉरेस्ट) केवल भारत में हैं। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) द्वारा प्रकाशित ग्लोबल टीक रिसोर्सेज एंड मार्केट असेसमेंट 2022 के अनुसार प्राकृतिक देसी सागौन के जंगलों का सबसे बड़ा हिस्सा मप्र एवं महाराष्ट्र में है।

अधिकांश क्षेत्रों में औसत वार्षिक वृद्धि (मीन एनुअल इंक्रीमेंट यानी पेड़ों के स्टैंड की औसत वार्षिक वृद्धि) 12 घन मीटर प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष (मी3/हेक्टेयर/वर्ष) से कम है। वृद्धि के लिए अनुकूल परिस्थितियों में 10-12 मी3/हेक्टेयर/वर्ष की उपज आदर्श मानी जाती है। लेकिन चूंकि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 और राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के तहत सरकारी स्वामित्व वाले वनों से लकड़ी की कटाई प्रतिबंधित है इसलिए इस बेशकीमती लकड़ी की बढ़ती घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मांग को पूरा करने के लिए निजी बागानों का सहारा लिया जाता है। हालांकि प्लांटेड सागौन की कम उत्पादकता इस बेशकीमती कृषि वानिकी सेक्टर को पंगु बना देती है। एफएओ द्वारा 2024 में प्रकाशित पुस्तक के एक अध्याय में भारत में सागौन की कम उत्पादकता जैसे मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है। कोयंबटूर स्थित वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान (आईएफजीटीबी) के शोधकर्ता इस अध्याय में कहते हैं, सागौन का प्राकृतिक पुनर्जनन काफी हद तक बीजों पर निर्भर करता है लेकिन ऐसे कई कारक हैं जो इस तरीके से वृक्षों के व्यापक प्रसार को प्रभावित करते हैं। कम फल उत्पादन, खराब बीज व्यवहार्यता और निम्न अंकुरण दर ऐसे कुछ कारक हैं। इसी अध्याय में आगे कहा गया है, पारंपरिक वानस्पतिक प्रसार विधियों जैसे कटिंग रोपना, ग्राफ्टिंग और बडिंग इत्यादि की भी अपनी सीमाएं हैं। जैसे निम्न सफलता दर और पुराने पेड़ों में जड़ें कमजोर होना इत्यादि। इन मुद्दों को ध्यान में रखकर शोधकर्ता और निजी व्यवसायी सागौन के ऊतक संवर्धन (टिशू कल्चर) प्रसार को बढ़ावा देते हैं और दावा करते हैं कि इससे 8 से 12 वर्षों में अधिक लाभ और रिटर्न मिल सकता है। इसके अलावा आईएफजीटीबी के शोधपत्र के अनुसार ऊतक संवर्धन आनुवंशिक रूप से बेहतर एवं रोग मुक्त पौधे तैयार करता है।

भारत में सागौन के ऊतक संवर्धन अनुसंधान की शुरुआत 1970 के दशक में हुई जिसके बाद 1980-90 के दशक में राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला (एनसीएल), पुणे द्वारा इस दिशा में व्यापक प्रयास किए गए। इस दिशा में कई प्रोटोकॉल मौजूद हैं। उदाहरण के लिए 2005 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद ने परिपक्व पेड़ों की नई टहनियों से नोडल एक्सप्लांट्स (ऊतकों) को विकसित करने की एक विधि स्थापित की। इस प्रोटोकॉल के चार चरण हैं, प्राथमिक एक्सप्लांट्स की स्थापना, इन विट्रो मल्टीप्लिकेशन (गुणन), जड़ें बनना और पौधों में मजबूती आना (अनुकूलन)।

वर्तमान में भारत में 200 से अधिक ऊतक संवर्धन प्रयोगशालाएं सागौन के पौधे तैयार करती हैं। लेकिन क्या ऊतक संवर्धन वास्तव में त्वरित विकास और उच्च उत्पादकता की गारंटी देता है? दीर्घकालिक क्षेत्रीय अध्ययनों का अभाव होने के कारण इस प्रश्न का उत्तर देना संभव नहीं है। व्यापक वानिकी अनुसंधान के बावजूद ऊतक-संवर्धित सागौन की वृद्धि, गुणवत्ता और आर्थिक लाभ पर 25 वर्ष से अधिक समय तक का कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं हुआ है। परीक्षणों से निकले निष्कर्षों और उनके विश्लेषण से हमें कुछ अंतर्दृष्टि मिलती है। सर्वप्रथम, सफलता की ऐसी कहानियां व्यक्तिपरक होती हैं और उन्हें सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता है। एनसीएल के एक शोधकर्ता द्वारा 2011 में लिखे गए एक पेपर में महाराष्ट्र के सांगली के पास एक किसान के खेत में ऊतक-संवर्धित सागौन की उत्कृष्ट वृद्धि रिपोर्ट की गई है। 8 वर्षों में इन पेड़ों में एक समान वृद्धि हुई और ये वृक्ष 8-10 मीटर ऊंचाई और 60-70 सेमी परिधि तक पहुंच गए। हालांकि पेपर में कहा गया है कि दक्षिण भारत में एक निजी कंपनी से प्राप्त ऊतक-संवर्धित सागौन में अल्प वृद्धि, उच्च परिवर्तनशीलता और उच्च मृत्यु दर दिखाई दी। दूसरा, वृक्षारोपण का प्रकार आर्थिक क्षमता निर्धारित कर सकता है। इंडियन जर्नल ऑफ एग्रोफॉरेस्ट्री में 2021 के एक अध्ययन में कर्नाटक में तीन अलग-अलग सागौन रोपण प्रणालियों का विश्लेषण किया गया है। गहन रूप से प्रबंधित 4×4 मीटर की दूरी पर रोपे गए, लाइन या रेखा 4 मीटर की दूरी और अप्रबंधित 2×2 मीटर की दूरी पर रोपे गए। गहन रूप से प्रबंधित पेड़ों को उचित सिंचाई, उर्वरक और अच्छी कृषि पद्धतियां मिलीं जबकि वहीं लाइन पौधारोपण में न्यूनतम रखरखाव किया गया।

● रजनीकांत पारे

अध्ययन से यह भी पता चलता है कि 20 वर्षों के बाद गहन प्रबंधन के साथ भी सागौन की उपज 5-10 मी3 प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष थी। यह ऊतक-संवर्धित सागौन द्वारा छोटे चक्रों में अधिक उपज देने के दावों पर सवाल उठाता है। उदाहरण के लिए कर्नाटक के चिक्काबल्लापुर की एक कंपनी मदर एग्री बायोटेक प्रति हेक्टेयर 440 पेड़ लगाने की सलाह देती है। कंपनी का कहना है कि सागौन 8, 12 और 18 साल में उपज देना शुरू कर देता है और एक वृक्ष क्रमशः 0.7 मी3, 2.12 मी3 और 4.24 मी3 लकड़ी प्रति पेड़ पैदा करता है। एक अन्य कंपनी नेशनल ग्रीन बायोटेक का दावा है कि प्रति एकड़ (0.4 हेक्टेयर) 600 पेड़ लगाने के 8 साल के भीतर प्रत्येक पेड़ 0.76 मी3 लकड़ी का उत्पादन कर सकता है। इन दावों को सत्यापन और प्रमाणन की आवश्यकता है क्योंकि भारत में कोई भी वानिकी अनुसंधान संस्थान सागौन के लिए 10 या 15 वर्ष की रोटेशन अवधि की सिफारिश नहीं करता है। हालांकि ऊतक संवर्धन निश्चित रूप से आशाजनक है लेकिन विभिन्न परिस्थितियों के तहत इसकी दीर्घकालिक प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए आगे अनुसंधान की आवश्यकता है।

दबंगों के सामने प्रशासन नतमस्तक

देश-दुनिया हर क्षेत्र में इतना आगे बढ़ गई है। दुनिया चांद पर पहुंच गई है, लेकिन आज भी 21वीं सदी में कुछ लोगों रुढ़िवादी सोच से बाहर नहीं निकल पाए हैं। आज भी लोगों के मन से जातिवाद और छुआछूत निकल नहीं पाया है। तभी तो बुंदेलखंड में आज भी दलितों को पानी के लिए संघर्ष के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। गांव के दबंग दलितों को सरकारी कुआं से पानी नहीं भरने दिया जा रहा है। बदलते समय के साथ अब छुआछूत, गरीबों-दलितों पर दबंगों का अत्याचार जैसी घटनाएं काफी कम हो गई हैं। क्योंकि लोग अब जागरूक हो गए हैं। साथ ही कानूनी कार्रवाई भी सख्त होने लगी है। लेकिन अभी भी दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्ग के लोगों पर दबंग अन्याय कर रहे हैं। ऐसा ही मामला सामने आया है पन्ना जिले की ग्राम पंचायत सिरस्वाहा से। हालत ये है कि 200 ग्रामीण पानी के लिए मोहताज हो गए हैं। ग्राम पंचायत सिरस्वाहा के ग्राम सिंधुपुर में ग्रामीणों के लिए पेयजल का एक ही साधन है सार्वजनिक कुआं। गांव के दबंगों ने यहां अवैध कब्जा करते हुए रास्ता बंद कर दिया। सारे नियमों को धता बताकर अवैध निर्माण किया जा रहा है। कुएं का रास्ता बंद होने से ग्रामीण पेयजल के लिए भटकने लगे। कमजोर वर्ग के लोगों को गांव के बाहर जाकर यहां-वहां से पीने के पानी का जुगाड़ करना पड़ रहा है। महिलाएं सुबह से पानी की तलाश में सिर पर बर्तन लेकर निकल जाती हैं। पानी कहां मिलेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं रहता।

ग्रामीणों ने अवैध निर्माण करने वालों से काफी निवेदन किया कि उन्हें कुएं तक पहुंचने का रास्ता खोल दें। लेकिन दबंग लोगों ने इन कमजोर वर्ग के लोगों को धमकाकर भगा दिया और कहा कि जाओ जहां शिकायत करना हो कर देना लेकिन दोबारा इस तरफ आने की कोशिश नहीं करना। इसके बाद परेशान ग्रामीणों ने पन्ना कलेक्टर के पास पहुंचकर अपनी व्यथा सुनाई। ग्रामीणों का कहना है पन्ना कलेक्टर से इससे पहले भी लिखित शिकायत की थी लेकिन अभी तक कुएं का रास्ता नहीं खोला गया। वे लोग पेयजल के लिए दर-दर भटक रहे हैं। दबंगों के अत्याचार से पीड़ित ग्रामीण किशोरा का कहना है गांव में सिर्फ 200 परिवारों को पानी पीने के लिए एक सार्वजनिक कुआं है। इस कुएं को बहुत पहले ग्रामीणों द्वारा खोदा गया था। बाद में प्रशासन द्वारा उसे पक्का करवाया गया। इसी कुएं से सभी ग्रामीण पीने का पानी एवं निस्तार का पानी भरते हैं। कुएं के दो तरफ मकान बने हुए हैं। कुएं के दक्षिण एवं उत्तर में जगह खाली है, जिस पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है। रास्ता रोककर बीम डालकर मकान बनाया जा रहा है।

पीड़ित महिला रामदुलारी बताती हैं सार्वजनिक कुएं पर अतिक्रमण की शिकायत हम लोगों द्वारा ग्राम पंचायत की सचिव एवं पटवारी से भी की गई। उनके द्वारा भी कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गया और दबंग नहीं माने। रास्ता बंद कर दिया है। अब गांव के 200 ग्रामीणों पर पानी का संकट गहरा गया है। क्योंकि गांव में पीने के पानी के लिए कोई दूसरा साधन नहीं है। सिर्फ एक कुआं ही साधन है। प्रशासन द्वारा बोर कराया गया था, वह खराब हो गया है। पानी के लिए दिनभर गांव के बाहर भटकना पड़ता है। इस मामले में नायब तहसीलदार शशिकांत दुबे का कहना है कि ग्राम पंचायत सिरस्वाहा के माजरा सिंधुपुर में सार्वजनिक कुएं पर विवाद है, इसकी जानकारी मिली है। मैं मौके पर पहुंचकर वस्तुस्थिति समझूंगा। इसके बाद ही कुछ कह सकता हूं। यह सार्वजनिक कुआं है। निश्चित ही लोगों को पानी भरने से कोई नहीं रोक सकता।

बुंदेलखंड के छतरपुर जिले में जातिवाद और छुआछुत का दंश जाने का नाम नहीं ले रहा है। आजादी के सालों बाद भी जातिवाद से लोग आजाद नहीं हो पा रहे हैं। तभी तो एक दलित को कुएं पर दबंगों द्वारा कब्जा कर पानी नहीं भरने दिया जा रहा है। दलित पिछले 8 दिनों से पानी दूर से लाने को मजबूर है। दरअसल, छतरपुर जिले के घुवारा चौकी थाना इलाके के कुटोरा गांव में दलित समाज के लोगों ने गत दिनों एसपी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती आवेदन दिया। जिसमें कुआं मुक्त करवाने की मांग की है। उनके कुएं के पास भगोनी, पटेल बगैरा ने झोपड़ी बनाकर कब्जा कर लिया है। जब गांव के शासकीय कुएं से गांव के अहिरवार समाज के लोग पानी भरने के लिए जाते हैं, तो उन्हें छुआछूत का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं दलितों को उस कुएं से पानी भी नहीं भरने दिया जाता है। कुटोरा गांव के करीब 12 ग्रामीणों ने जनसुनवाई में वरिष्ठ अधिकारियों के सामने बेबस होकर न्याय की गुहार लगाई है। गांव के पीड़ित दलित ने बताया कि गांव के रनमत हार में एक शासकीय कुआं स्थित है। गांव के सभी वर्गों के लोग पिछले कई वर्षों से उसी कुएं से पानी भरते हैं, लेकिन करीब 8 दिनों से शासकीय कुएं पर गांव के कुछ दबंगों का कब्जा है।

● सिद्धार्थ पांडे

जातियों के अलग-अलग कुएं

बुंदेलखंड के टीकमगढ़ जिले का गांव है सुजानपुरा। यहां जातियों के नाम पर भेदभाव किया जा रहा है। यहां जाति के आधार पर पानी का बंटवारा कर दिया गया है। तीन जातियों के तीन अलग-अलग कुएं हैं। यहां एक जाति वालों के कुएं से दूसरी जाति का व्यक्ति पानी भर ले तो उसके साथ मारपीट की जाती है। गांव का अहिरवार समाज वंशकार जाति को अछूत मानता है। ऐसे में वह अपने कुएं से उन्हें पानी नहीं भरने देता। गांववालों का कहना है कि यहां सालों से यही व्यवस्था चली आ रही है। दबंगों का आतंक ऐसा है कि सूखा पड़े या कोई और विपत्ति आए यह परंपरा कोई नहीं तोड़ सकता। इनके अलावा अन्य जातियों का एक अलग कुआं है जो अहिरवार और वंशकार समाज को अपने कुएं से पानी नहीं भरने देता। वंशकार समाज अगर अहिरवार समाज के कुएं से पानी भर ले तो कुएं में गंगाजल डालकर उसे शुद्ध किया जाता है। दोषी को पंचायत दंडित भी करती है। आदिम जाति कल्याण विभाग की संयोजक सरिता नायक का कहना है कि इस तरह का मामला पहली बार सुनने में आया है। इसे निपटाने के लिए अगर गांव में कैंपेन चलाने की जरूरत पड़ी तो करेंगे ताकि लोगों के दिलों से छुआछूत का भाव खत्म किया जा सके।

विकराल होता जलवायु परिवर्तन का संकट

मैदान से पहाड़ों तक तबाही ही तबाही

भारत सहित पूरे विश्व में विकास की भूख से जलवायु परिवर्तन का संकट विकराल होता जा रहा है। इस कारण जहां जून-जुलाई में यूरोप में गर्मी का तांडव मचा हुआ है, वहीं भारत में मानसून ने तबाही मचा रखी है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में बादल फटने से बाढ़ और भूस्खलनों में सैकड़ों लोग मारे गए हैं वहीं सरकारी और निजी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा है। दूसरी तरफ मैदानी क्षेत्रों यानि मप्र, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, उप्र, बिहार आदि में बाढ़ से त्राहिमाम की स्थिति बन गई है। बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के कारण देश में हजारों करोड़ के पुल, पुलिया, सड़क, मकान, दुकान बह गए हैं।

● राजेंद्र आगाल

भारत इस धरती पर ऐसा देश है, जहां प्रभु और प्रकृति की सबसे अधिक कृपा है। लेकिन विकास की दौड़ में पश्चिमी देशों की बराबरी करने की होड़ में प्रकृति को जिस तरह नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उसका असर मानसून में सबसे अधिक झेलना पड़ता है। जलवायु परिवर्तन के विकराल संकट के कारण बाढ़ अब देशवासियों की नियति बन चुकी है। सरकारें बाढ़ आने पर हर साल राहत का ढिंढोरा पीटकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर चैन की नींद सो जाती हैं। नदी प्रबंधन अब भी दूर की कौड़ी है। इस कारण हर साल हजारों लोग बाढ़ के प्रकोप से प्रभावित होते हैं। भारत में हर साल बाढ़ और बारिश के कारण जान-माल का भारी नुकसान होता है। हर साल औसतन 75 लाख हेक्टेयर भूमि बाढ़ से प्रभावित होती है, 1600 लोगों की जान जाती है और 1805 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। इसके अलावा, बाढ़ से भारतीय अर्थव्यवस्था को हर साल 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान होता है।

विगत एक दशक की तरह इस बार भी मानसून के दौरान बारिश, बाढ़ और भूस्खलन का दौर जारी है। इस साल देश में मानसून ने समय से पहले दस्तक दे दी है। इस कारण आपदा और विपदा भी पहले ही आ गई है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु हो या पहाड़ी राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर या पूर्वोत्तर के राज्य असम, नागालैंड, आंध्रप्रदेश, मिजोरम, मणिपुर या फिर मैदानी राज्य मप्र, उप्र, बिहार, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़ हर तरफ बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात हैं। पहले खेत-खलिहान, नदी-तालाब में भरने वाला पानी अब शहर-गांव में भरा हुआ है। महानगरों में बारिश की वजह से सड़कें लबालब हो चुकी हैं और जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। लेकिन देश के कुछ शहर हर साल ही ऐसी तबाही झेलते हैं, जहां बारिश और फिर बाढ़ से होने वाली बर्बादी समय का चक्र बन चुका है।

कितनी आबादी होती है प्रभावित

थोड़ी तेज बारिश हुई, शहर डूबने लगे। ग्लेशियल लेक टूटा। पहाड़ों से आपदा बहकर नीचे चली आई। चक्रवाती तूफान आया। समंदर की लहरों ने तटीय इलाकों को डुबा दिया। हर जगह कहर बरपा रहा है जीवन देने वाला पानी। बाढ़ बनकर मौत का तांडव करता है पानी। इसलिए दुनियाभर में बाढ़ को लोग गंभीरता से लेते हैं, इससे बचते हैं। दुनिया में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कई दर्जनों ऐसे देश हैं, जहां पर बाढ़ एक बड़ी प्राकृतिक आपदा है। अक्सर आती है। हर साल आती है। अब तो बिना मौसम के भी आ जाती है। हाल ही का मामला गुजरात, आंध्रप्रदेश और तेलंगाना का है। उससे पहले मुंबई और दिल्ली डूबे। बाढ़ का रिस्क सिर्फ भारत में ही नहीं है, बल्कि आसपास के देशों से लेकर अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण एशिया, नॉर्डिक देश हर जगह है।

चीन- कुल आबादी 140 करोड़ के पार है। यहां पर बाढ़ आने पर 39.5 करोड़ लोग प्रभावित होते हैं।

भारत- कुल आबादी 140 करोड़ के पार। यहां बाढ़ आने पर 39 करोड़ लोग प्रभावित होते हैं।

बांग्लादेश- 16.4 करोड़ से ज्यादा आबादी। बाढ़ आने पर 9.4 करोड़ लोग प्रभावित होते हैं। यानी आधी आबादी।

इंडोनेशिया- 28 करोड़ से ज्यादा की आबादी। बाढ़ आने पर 7.6 करोड़ लोग प्रभावित होते हैं।

पाकिस्तान- 23.1 करोड़ से ज्यादा की आबादी। बाढ़ में 7.2 करोड़ लोग परेशान होते हैं।

बाढ़ सबसे ज्यादा कहां आती है? जहां बड़े तट होंगे, नदियों का सिस्टम होगा, मैदानी इलाका होगा। ऐसी जगहों पर आबादी का ज्यादातर हिस्सा बाढ़ की समस्या से जूझेगा। पूरी दुनिया में सिर्फ नीदरलैंड्स और बांग्लादेश ही दो ऐसे देश हैं, जिनकी पूरी आबादी का आधे से ज्यादा हिस्सा बाढ़ से प्रभावित होता है। भारत की कुल आबादी का करीब 28 फीसदी हिस्सा यानी 38.98 करोड़ लोग बाढ़ की समस्या का सामना करते हैं।

हिमाचल में मौसम का तांडव अब तक 98 लोगों की मौत

हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन ने कहर बरपाया हुआ है। राज्य में अब तक 23 बाढ़, 19 बादल फटने की घटनाएं और 16 भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, 20 जून को मानसून की शुरुआत के बाद से हिमाचल प्रदेश में कम से कम 98 लोगों की जान जा चुकी है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) के अनुसार, इनमें 50 मौतें भूस्खलन, अचानक बाढ़ और बादल फटने जैसी घटनाओं के कारण हुईं, जबकि 28 मौतें सड़क दुर्घटनाओं में हुईं हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में मानसून से संबंधित विभिन्न आपदाओं के कारण 14 जुलाई तक कुल 98 लोगों की मौत हो चुकी है। बारिश से होने वाली त्रासदियों में अचानक बाढ़ से 14 मौतें, डूबने से 8, बिजली के झटके, दुर्घटनावश गिरने से 8 मौतें हुईं हैं। जिलों के अनुसार, जानें तो मंडी जिले में सबसे अधिक 17 लोगों की बारिश से संबंधित मौतें हुईं, उसके बाद कांगड़ा में 11 मौतें हुईं। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि अन्य गंभीर रूप से प्रभावित जिलों में कुल्लू (3 मौतें), चंबा (3) और शिमला (3) शामिल हैं। हिमाचल के जिलों में 28 लोगों की जान सड़क दुर्घटनाओं में हुई हैं, इनमें चंबा में सबसे अधिक 6 मौतें हुईं, उसके बाद बिलासपुर, कुल्लू और कांगड़ा का स्थान रहा। हताहतों के अलावा, राज्य को आर्थिक नुकसान हुआ है। एसडीएमए के आंकड़ों के अनुसार, बारिश और भूस्खलन से 269 सड़कें बंद हैं, 285 बिजली ट्रांसफार्मर और 278 जलापूर्ति योजनाएं प्रभावित हुई हैं। वहीं सार्वजनिक और निजी संपत्ति को कुल 57 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान होने का अनुमान है।

नीदरलैंड्स- कुल आबादी का 58.7 फीसदी हिस्सा बाढ़ से परेशान होता है। यानी करीब 1.01 करोड़।

बांग्लादेश- कुल आबादी का 57.5 फीसदी हिस्सा बाढ़ से जूझता है। यानी 9.44 करोड़ से ज्यादा।

वियतनाम- कुल आबादी का 46 फीसदी डूबता है। यानी 4.55 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित होते हैं।

मिस्र- कुल आबादी का 40.5 फीसदी हिस्सा। यानी 3.88 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित होते हैं।

म्यांमार- कुल आबादी का 39.9 फीसदी हिस्सा। यानी 1.91 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित होते हैं।

देश में पहले 110 जिले थे, जो सूखे से बाढ़ की तरफ गए थे। लेकिन अब सूखे से ज्यादा बाढ़ झेलने वाले 149 जिले हैं। बिहार, आंध्रप्रदेश, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उप्र, और असम के 60 फीसदी जिले साल में एक बार जरूर चरम मौसमी आपदा का सामना करते हैं। 2036 तक ऐसी आपदाओं से देश के 147 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित होंगे। 1973 से 2023 तक होने वाली सभी चरम आपदाओं की स्टडी इस नई रिपोर्ट में की गई है। हैरानी इस बात की है दिल्ली, गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान की बाढ़ हो, वायनाड में भूस्खलन हो या फिर इस बार पड़ी चमड़ी गलाने वाली गर्मी हो, वैज्ञानिक और एक्सपर्ट इनके होने का अंदाजा नहीं लगा सकते। क्योंकि इनकी तीव्रता, मात्रा अचानक बढ़ जाती है। असम के 90 फीसदी जिले, बिहार के 87

आसमानी कहर या मानवजनित संकट

बरसात के मौसम में हर साल जैसे ही आसमान में काले बादल मंडराने लगते हैं, भारत के पहाड़ी राज्यों में एक खौफ साथ चलने लगता है, बादल फटने का। यह एक ऐसी विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है, जो कुछ ही पलों में जनजीवन को तहस-नहस कर देती है और मानव जीवन के साथ वन संपदा और बुनियादी ढांचे को भी तबाह कर देती है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और मंडी में इस समय बादल फटने की घटनाएं हुई हैं। हाल में मंडी के करसोग और धर्मपुर में और पिछले माह कुल्लू के सैंज घाटी में बादल फटने की घटना ने न केवल कई घरों को उजाड़ दिया बल्कि पूरे वन क्षेत्र और जनसंपत्ति को भी व्यापक नुकसान पहुंचाया। आसमान से बरसे पानी ने नालों को उफनती नदियों में बदल दिया। सड़कों को मलबे से ढक दिया, कुछ लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लापता हो गए। शिलागढ़ की चोटियों पर अचानक बादल फटा, जिससे मूसलाधार बारिश और पहाड़ी ढलानों से बाढ़ जैसा बहाव नीचे की ओर बढ़ने लगा। सड़कें, पुल, बिजली और जल आपूर्ति जैसी आधारभूत संरचनाएं बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुईं।

फीसदी जिले, ओडिशा के 75 फीसदी जिले और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 93 फीसदी जिले चरम बाढ़ की स्थिति से कभी भी परेशान हो सकते हैं।

हर साल बारिश से हाल बेहाल

दिल्ली का मिंटो ब्रिज राजधानी में बारिश की पहचान बन चुका है। यहां ब्रिज के नीचे हर साल बारिश में डूबी हुई बस या फिर कार की तस्वीर अखबारों की सुर्खियां बनती हैं, फिर भी यह बदस्तूर जारी है। राजधानी में सड़कों और नालों के निर्माण पर करोड़ों रुपए हर साल खर्च किए जाते हैं। इसे चमकाने के लिए बड़े-बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लाए जाते हैं, फिर भी दिल्ली का हाल हर बारिश में एक जैसा ही रहता है। दिल्ली-मुंबई और चेन्नई ऐसे शहर हैं जो बारिश में हर साल डूबते हैं। यहां सरकारों की तैयारियां थोड़ी सी बारिश में भी नाकाफी नजर आती हैं और इसका भुगतान आम जनता को करना पड़ता है, जिनके लिए रोजमर्रा के कामों की वजह से घर से निकलना मजबूरी है। इन महानगरों में सड़कों पर सैलाब, मकान ढहने के हादसे, बिजली के तारों का टूटना और बाढ़ जैसे हालात हर साल की बारिश की कहानी बयां करते हैं। इसके लिए हर साल प्लानिंग होती है और पैसा भी खर्च किया जाता है, लेकिन आखिर में सारे इंतजाम धरे के धरे रह जाते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है?

दिल्ली में बारिश हर साल पुराने रिकॉर्ड तोड़ती है और हर साल एक जैसे हालात पैदा होते हैं। कहीं फ्लाईओवर से वॉटरफॉल जैसा नजारा दिखता तो कहीं अंडरपास में गाड़ियां पानी में डूब जाती हैं। कई-कई घंटे तक लोग सड़कों पर ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। इसी तरह यमुना किनारे बसे इलाकों में नदी में उफान के बाद कहर शुरू हो जाता है। लोगों का अस्थाई विस्थापन, फसलों और घरों की बर्बादी हर साल का रुटीन बन चुका है। राजधानी दिल्ली के अलावा मुंबई और चेन्नई का हाल भी ऐसा ही है, जहां बारिश लोगों के लिए गर्मी से राहत कम और आफत ज्यादा लेकर आती है। मुंबई को हर साल बारिश की वजह से जान-माल की हानि के साथ करोड़ों रुपए का आर्थिक नुकसान भी होता है। इसी तरह चेन्नई में भी लाखों लोग बारिश की वजह से प्रभावित होते हैं और हजारों लोगों के सामने रोजी-रोटी का संकट पैदा हो जाता है।

बढ़ती आबादी का दबाव

सबसे पहले इन शहरों की आबादी बेहिसाब तरीके से बढ़ रही है। पहले से ही इन महानगरों पर जनसंख्या का भारी दबाव है, जिससे बुनियादी ढांचा तैयार करने की हर कोशिश नाकाफी नजर आती है। यही वजह है कि सामान्य बारिश भी इन शहरों पर भारी पड़ जाती है और आबादी के हिसाब से जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी साफ नजर आती है। सड़कों के किनारे बने फुटपाथ और फ्लाईओवर लोगों को सुविधाएं तो देते हैं, लेकिन बारिश में जल निकासी और जल रिसाव ठीक ढंग से न हो पाने की वजह से सड़कों पर पानी जमा हो जाता है। ऐसे में वाहन डूबने और सड़क हादसों की घटनाएं हर साल होती हैं।

हमने अंधाधुंध विकास की आड़ में उद्योग और इनसे जुड़े उत्पादों को जिस तरह से प्राथमिकता दी है, उससे पृथ्वी का सारा संतुलन चरमरा गया है। जानकारों का कहना है कि पृथ्वी आवश्यकताओं तक तो साथ दे सकती है पर इसका सुविधाओं के लिए अत्यधिक शोषण शायद ही इसे भाए। प्रकृति अब तेजी से हमारा साथ छोड़ रही है और कई रूपों में हमें डरा रही है। हमारे देश में इसका एक रूप वर्षा के असंतुलन के रूप में देखने को मिल रहा है। भारतीय मौसम विभाग के आंकड़ों पर गहराई से चिंतन करें, तो स्थिति बेहद चिंताजनक है। देश के कुछ हिस्सों में पूर्वानुमान से कहीं अधिक वर्षा ने आफत मचाई, तो कुछ हिस्सों में किसान पानी के लिए तरस गए। सामान्य से अधिक या सामान्य से कम, दोनों ही स्थितियां चिंता पैदा करने वाली हैं। मौसम विभाग सहित विभिन्न वैज्ञानिक संस्थानों के अध्ययनों के अनुसार, जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा का पैटर्न निरंतर बदल रहा है, जिससे न केवल खेतीबाड़ी पर, बल्कि देश की आर्थिक, स्वास्थ्य और बढ़ती आपदाओं के कारण जनधन की सुरक्षा पर भी असर पड़ रहा है।

स्पंज सिटीज की जरूरत

देश में स्मार्ट सिटीज का निर्माण किया जा रहा है, जहां मॉल, मेट्रो और अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की आधुनिक सुविधाएं दी जा रही हैं। लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि हमें ऐसे शहरों की जरूरत है जो पानी के मामले में स्मार्ट हों, हमें स्पंज सिटीज की जरूरत है, ऐसे शहर जो बारिश के पानी को सोखने और जमा करने के लिए बनाए गए हों और बाढ़ को कम करने के लिए उनका इस्तेमाल किया जा सके। बर्लिन और चीन समेत कई देश बाढ़ को प्रभावी ढंग से मैनेज करने के लिए इस प्लान के तहत आगे बढ़ रहे हैं। शहरों में सीमेंट-कांक्रीट से बनी सड़कों से पानी निकासी का सही इंतजाम कर पाना मुश्किल है, क्योंकि इससे न तो सड़कें बारिश के पानी को सोख पाती हैं और न ही उनकी सही निकासी हो पाती है। ऐसे में सड़क किनारे प्राकृतिक इंतजाम करके पानी को सोखने के

उपाय समय की मांग हो चुके हैं। वर्षा के पैटर्न में बदलाव से पानी की कमी की समस्याएं बढ़ सकती हैं। भारी वर्षा से ऊपरी उपजाऊ मिट्टी के क्षरण के कारण उर्वरता कम होती है। यह परिवर्तन विभिन्न तरीकों से सार्वजनिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। भारत के वर्षा पैटर्न में परिवर्तनों की भविष्यवाणी और प्रबंधन के लिए परिवर्तन के कारणों को समझना और उनकी निगरानी करना महत्वपूर्ण है। इस बदलते पैटर्न के प्रतिकूल प्रभावों के समाधान के लिए एकीकृत दृष्टिकोणों की आवश्यकता है, जिसमें जलवायु-लचीली कृषि, टिकाऊ जल प्रबंधन प्रथाएं, बाढ़ के जोखिमों को कम करने के लिए बुनियादी ढांचा विकास और बदलती जलवायु परिस्थितियों को नियंत्रित करने वाली नीतियों को लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रकृति का सिद्धांत भी यही कहता है कि जो लेना है, उसे लौटाना भी है।

आज सुविधा जुटाने की होड़ व पागलपन इस हद तक जा पहुंचा है कि हम जीवन के मूल्यों और आधारों से भी कहीं आगे आ चुके हैं। हम गलतियों को न तो सुधारने के पक्ष में हैं और न ही यह समझने के लिए तैयार हैं कि अत्यधिक सुविधाएं संकट का ही पर्याय होती हैं। भोगवादी जीवनशैली हमेशा पृथ्वी को नुकसान ही पहुंचाएगी, यह हम सबकी समझ में आ जाना चाहिए। मनुष्य ये भूल गया कि प्रकृति पर उसका नियंत्रण नहीं है। यदि अपने देश की बात करें, तो एक ओर बारिश का बढ़ता असंतुलन और दूसरी ओर धुंध व प्राण वायु की दुश्वारी हमें क्या समझाने की कोशिश कर रही है। शायद यह कि प्रकृति जब भी बिगड़ेगी तो सबको ले डूबेगी। अब भी बहुत कुछ बचाया जा सकता है बशर्ते हम अपने विकास के वर्तमान मॉडल में मूलभूत परिवर्तन करें। बाढ़ एक ऐसी आपदा है जिसमें हर साल करोड़ों रुपयों का नुकसान ही नहीं होता बल्कि हजारों-लाखों घर तबाह हो जाते हैं, लहलहाती खेती बर्बाद हो जाती है और अनगिनत मवेशियों के साथ इंसानी जिंदगियां सालभर में अनचाहे मौत के मुंह में चली जाती हैं। एक शोध से साबित हो चुका है कि पिछले तीन दशक में देश में चार-सवा चार अरब से भी ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। अक्सर देखने में आता है कि मानसून के आते ही नदियां उफान पर आने लगती हैं और देश के अधिकांश भू-भागों में तबाही का तांडव मचाने लगती हैं। वैसे तो आपदा, वह चाहे बाढ़ हो, भूकंप हो या कोई अन्य, का मानव सभ्यता से आदिकाल से रिश्ता रहा है। इसमें भी दोराय नहीं कि सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे ही हुआ और जब-जब बाढ़ ने विकराल रूप धारण किया, नदियों के किनारे बसी बस्तियां बाढ़ के प्रकोप का शिकार हुईं और नेस्तानाबूद हो गईं। यही नहीं नदियों के प्रभाव क्षेत्र में हरे-भरे खेत भी उसकी चपेट में आकर तबाह हो गए। नतीजतन मानव जीवन हर साल कमोबेश बाढ़ की विभीषिका सहने को बाध्य हो गया।

बादल फटने के पीछे का विज्ञान

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) बादल फटने को भारी वर्षा की स्थिति के रूप में परिभाषित करता है, जब बहुत छोटे क्षेत्रों (20-30 वर्ग किमी) में एक घंटे में 10 सेमी या 100 मिमी से अधिक वर्षा होती है। पर्वतीय क्षेत्र पर्वतीय उत्थान के कारण बादल फटने के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। जब नमी से भरपूर हवा किसी पहाड़ी क्षेत्र में ऊपर की ओर बहती है, तो यह बादलों का एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ बनाती है जिसे क्यूम्यलोनिम्बस बादल कहते हैं। ये बादल आमतौर पर बारिश, गरज और बिजली का कारण बनते हैं। बादलों की यह ऊपर की ओर गति, जिसे ऑरोग्राफिक लिफ्ट भी कहा जाता है, एक छोटे से क्षेत्र में अस्थिर बादलों और भारी वर्षा का कारण बनती है। हिमालयी क्षेत्रों में बादल फटना एक आम घटना है और चरम मौसम की घटनाएं और भी विनाश का कारण बनती हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, कुलगाम में बादल फटने के बाद अचानक आई बाढ़ ने लगभग एक दर्जन गांवों को डुबो दिया, घरों में कीचड़ भर गया और मवेशी बह गए। 2022 में, दक्षिणी कश्मीर में एक हिमालय पर्वत गुफा की वार्षिक हिंदू तीर्थयात्रा के दौरान बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई, जिससे 16 लोगों की मौत हो गई। 2010 में, लद्दाख के दर्जनों गांव और लेह का मुख्य शहर हाल के इतिहास की सबसे भीषण बाढ़ की चपेट में आ गया था। एक रिपोर्ट के अनुसार, इस आपदा ने क्षेत्र के घरों और खेतों को तबाह कर दिया था।

जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

जलवायु परिवर्तन की वजह से बेमौसम बारिश और असामान्य गर्मी पड़ रही है और यह ऐसी समस्या है जो सामने से सीधे तौर पर न दिखे लेकिन मौजूद जरूर है। समुद्र का जल स्तर बढ़ने से देश के कई तटीय इलाके आज डूब रहे हैं। मुंबई इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां हर साल की बारिश में शहर डूब जाता है और लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज की वजह से सूखाग्रस्त इलाकों में बेशुमार बारिश कहर मचाती है। मौसम विभाग ने सन् 1989 से लेकर 2018 तक दक्षिण पश्चिम मानसून के जून से लेकर सितंबर तक के आंकड़ों के आधार पर 29 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में दर्ज मानसूनी वर्षा की परिवर्तनशीलता का जो विश्लेषण किया है, उसमें गत् 30 वर्षों की अवधि में देश के विभिन्न हिस्सों में वर्षा के वितरण में भारी असमानता उजागर हो रही है। इस विश्लेषण में उप्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, मेघालय और

नागालैंड में 1989-2018 के दौरान दक्षिण-पश्चिम मानसून की वर्षा में काफी कमी का रुझान दिखाया गया है। अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के साथ-साथ इन पांच राज्यों में वार्षिक वर्षा में भी काफी कमी का रुझान दिखाई देता है। विश्लेषण में भारी वर्षा वाले दिनों की आवृत्ति के संबंध में, सौराष्ट्र और कच्छ, राजस्थान के दक्षिण-पूर्वी भागों, तमिलनाडु के उत्तरी भागों, आंध्रप्रदेश के उत्तरी भागों और दक्षिण-पश्चिम ओडिशा के आसपास के क्षेत्रों, छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों, दक्षिण-पश्चिम मप्र, पश्चिम बंगाल, मणिपुर और मिजोरम, कोंकण और गोवा और उत्तराखंड में उल्लेखनीय वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन का आंकलन शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जो देश में जलवायु चरम सीमाओं सहित क्षेत्रीय जलवायु परिवर्तन पर प्रकाश डालती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में सतही वायु तापमान 1901-2018 के दौरान लगभग 0.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, जिसके साथ ही वायुमंडलीय नमी की मात्रा में भी वृद्धि हुई है। हिंद महासागर की सतह के तापमान में भी 1951-2015 के दौरान लगभग 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। जलवायु परिवर्तनों के स्पष्ट संकेत भारतीय क्षेत्र में मानवजनित ग्रीनहाउस गैसों और एरोसोल फोर्सिंग के कारण उभरे हैं, और भूमि उपयोग और भूमि आवरण में परिवर्तन ने जलवायु चरम सीमाओं में वृद्धि में योगदान दिया है। इसलिए गर्म होते पर्यावरण और क्षेत्रीय मानवजनित प्रभावों के बीच पृथ्वी प्रणाली घटकों के बीच जटिल अंत: क्रियाओं ने पिछले कुछ दशकों में स्थानीय भारी वर्षा, सूखे और बाढ़ की घटनाओं आदि की तीव्रता में वृद्धि की है। वर्षा के बदलते पैटर्न के कई नकारात्मक प्रभाव सामने आ रहे हैं। इस बदलाव का सीधा असर कृषि पर हो रहा है।

ड्रेनेज मैनेजमेंट बड़ी समस्या

आम घरों से निकलने वाले पानी को किसी नाले तक ले जाने की पर्याप्त सुविधाओं की कमी है। जब भी बारिश होती है तो गलियों में बनी नालियां ओवरफ्लो करती हैं। क्योंकि इस पानी की निकासी के सही इंतजाम नहीं हैं, ऐसे में यह नाली के पानी के साथ बारिश का पानी भी सड़कों पर आ जाता है। इसी वजह से महानगरों के कुछ इलाके पूरी तरह तालाब बन जाते हैं क्योंकि वहां का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह चरमराया हुआ है और पानी की निकासी के पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं। महानगरों में बसने का सपना देखने वाले लोगों की बढ़ती संख्या के लिए पेड़ों की कटाई हो रही है, जमीनों, पहाड़ों और जंगलों पर अतिक्रमण किया जा रहा है। लेकिन इन सबके बीच बेहतर जल निकासी व्यवस्था के महत्व को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिससे शहरों में बारिश के अनियमित पैटर्न का खतरा भी बढ़ रहा है। देखा गया है कि पिछले कुछ वर्षों से बाढ़ ने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है। भले ही बीते दशकों की तुलना में पिछले कुछ वर्षों में बारिश की मात्रा में कमी आई है लेकिन बाढ़ से होने वाली तबाही लगातार तेजी से बढ़ती ही जा रही है। जबकि नदी विशेषज्ञ नदियों में जल की मात्रा घटते जाने से चिंतित हैं। एक समय सूखे की मार झेलता राजस्थान का मरू इलाका भी अब नदियों के कोप का शिकार हो रहा है। बीते बरस इसकी गवाही देते हैं। कहने का तात्पर्य यह कि जो इलाके कुछ समय पहले तक बाढ़ के प्रकोप से अछूते थे, आज वे भी वहां की नदियों में आ रहे उफान से तबाह हो रहे हैं।

असल में बाढ़ की समस्या वैसे तो सभी क्षेत्रों में है लेकिन मुख्य समस्या गंगा के उत्तरी किनारे वाले क्षेत्र में है। गंगा बेसिन के इलाके में गंगा के अलावा यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन और महानंदा आदि प्रमुख नदियां हैं जो मुख्यत: उत्तराखंड, उप्र, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, मप्र, राजस्थान, बिहार सहित मध्य एवं दक्षिणी बंगाल में फैली हैं। इनके किनारे घनी आबादी वाले शहर बसे हैं। इस सारे इलाके की आबादी अब 40 करोड़ से भी ऊपर पहुंच गई है और यहां की आबादी का घनत्व 500 व्यक्ति प्रति किमी का आंकड़ा पार कर चुका है। उसका परिणाम है कि आज नदियों के प्रवाह क्षेत्र पर दबाव बेतहाशा बढ़ रहा है, उसके बाढ़ पथ पर रिहायशी कॉलोनियों का जाल बिछता जा रहा है, नदी किनारे एक्सप्रेस-वे व दिल्ली में यमुना किनारे खेलगांव का निर्माण इसका सबूत है कि सरकारें भी इस दिशा में कितनी संवेदनशील हैं। इसमें दोराय नहीं कि हिमालय से निकलने वाली वह चाहे गंगा हो, सिंध हो, ब्रह्मपुत्र हो या उसकी सहायक नदी, उनके उद्गम क्षेत्रों की पहाड़ी ढलानों की मिट्टी को बांधकर रखने वाले जंगल विकास के नाम पर जिस तेजी से काटे गए, वहां बहुमंजिली इमारतें रूपी कांक्रीट के जंगल, कारखाने और सड़कों के जाल बिछा दिए गए, विकास का यह रथ वहां आज भी निर्बाध गति से जारी है।

स्वार्थ के कारण जंगलों की कटाई से बिगड़े हालात

इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता कि स्वार्थ की खातिर पहले अंग्रेजी हुकूमत के दौरान, फिर आजादी के बाद देश में विकास के नाम पर जिस तेजी से जंगलों का कटान किया गया, उसी के कारण नदी घाटी क्षेत्र की ढलानों की बरसात को झेलने की क्षमता अब खत्म हो चुकी है। यह भी सच है कि नदियों के जलागम क्षेत्रों के जंगलों से ढके होने से बाढ़ का प्रकोप किसी हद तक कम जरूर हो जाता है। सच यह भी है कि नदियों के जलागम क्षेत्र की जमीन जंगलों के कटान के चलते जब नंगी हो जाती है, तो उस हालत में मिट्टी साद के रूप में नदी की धारा में जमने लगती है। मैदानी इलाकों में यह साद नदियों की गहराई को पाट कर उनको उथला बना देती है। नतीजतन बरसात के पानी का प्रवाह नदी की धारा में समा नहीं पाता और वह आसपास के इलाकों में फैलकर बाढ़ का रूप अख्तियार कर लेता है। जहां तक गंगा, यमुना और अन्य नदियों का प्रश्न है, अधिकांश का पानी मैदानी क्षेत्रों में खेती आदि के लिए सिंचाई की खातिर नहरों के जरिए निकाला जाता रहा है। इसके कारण नदियों में पानी न के बराबर रहता है जिसकी वजह से नदियां साद को समुद्र तक बहा ले जाने में नाकाम रहती है। नदी की धाराओं में मिट्टी के जमने और उनमें गहराई के अभाव में पानी कम रहने से वे सपाट हो जाती हैं। नदियों के किनारे अब न तो हरियाली बची है, न पेड़-पौधे। जब पेड़-पौधे रहेंगे ही नहीं तो उनकी जड़ें मिट्टी कहां से बांधेंगी।

अब विकास की बात...

पिछले चार दशक में छत्तीसगढ़ बस्तर ने केवल रक्त, अवरोध, हिंसा, रुदन और क्रंदन देखा था। लेकिन अब बस्तर की तस्वीर और तकदीर दोनों ही बदल रही हैं। केंद्र व राज्य की डबल इंजन सरकार ने वे सारे मिथक तोड़ दिए हैं, जो बस्तर के विकास में बाधक बने हुए थे। नक्सलियों के सफाए के साथ ही लोगों को अब यह बात समझ में आने लगेगी कि देश के विकास का एक रास्ता बस्तर से होते हुए भी जाता है।

बस्तर का मतलब अब तक केवल नक्सली हिंसा था, लेकिन अब बस्तर से मिलने वाला लौह अयस्क, इस्पात, धातु प्रसंस्करण, कृषि, वनोपज, बॉक्साइट और मैंगनीज आधारित उद्योग और हर्बल-औषधीय उत्पाद इस क्षेत्र की महत्ता को रेखांकित करेंगे। बस्तर के औद्योगिक परिदृश्य को देखें तो वर्तमान में बस्तर संभाग में 690 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) इकाइयां संचालित हैं। बस्तर संभाग के 3 प्रमुख हिस्सों में चावल मिल, ईंट निर्माण और धातु निर्माण उद्योग शामिल हैं। एनएमडीसी माइनिंग, एनएमडीसी स्टील, एस्सार, ब्रज इस्पात और एएमएनएस इंडिया जैसी प्रमुख कंपनियां यहां स्थापित हैं। इस संभाग से लगभग 102 करोड़ रुपए का निर्यात होता है, जिसमें लौह अयस्क की हिस्सेदारी सर्वाधिक है। राज्य सरकार ने बस्तर संभाग में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में विशेष प्रावधान किए हैं।

विकासात्मक पहलों के साथ-साथ सरकार ने सुरक्षा के मोर्चे पर भी बहुत योजनाबद्ध, समन्वित और दृढ़ता के साथ कार्रवाई की है। जिन कारकों ने बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति का प्रदर्शन भी शामिल है। पहली बार केंद्रीय गृहमंत्री ने स्वयं नेतृत्व करते हुए बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया। केंद्रीय और राज्य बलों के बीच एकीकृत कमान संरचना के माध्यम से बेहतर समन्वय। जिला रिजर्व ग्रुप ने गेम चेंजर की भूमिका निभाई। इसमें अधिकतर आत्मसमर्पण करने वाले पूर्व नक्सली होते हैं, जिन्हें इलाके की गहरी जानकारी होती है और जिनके स्थानीय लोगों से संबंध होते हैं। इससे खुफिया जानकारी जुटाने और बेहतर रणनीति बनाने में बड़ी मदद मिली। दूरदराज के इलाकों में सुरक्षा शिविरों की स्थापना और थानों का सुदृढ़ीकरण। तकनीकी सहायता, विशेषकर ड्रोन और सैटेलाइट इमेजिंग द्वारा निगरानी, जिससे घात लगाकर हमलों की घटनाएं काफी कम हो गईं।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहते हैं कि नई औद्योगिक नीति के तहत बस्तर संभाग में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ खनिज आधारित, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और पर्यटन उद्योग की असीमित संभावनाओं को साकार करने का रोडमैप तैयार किया गया है। विकसित बस्तर की ओर बढ़ने के लिए औद्योगिक नीति 2024-30 के अनुसार बस्तर संभाग के विकास के लिए 32 में से 28 विकासखंडों को समूह-3 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, ताकि उद्योगों को अधिकतम प्रोत्साहन मिले। इस्पात उद्योग के लिए 15 वर्ष तक रॉयल्टी प्रतिपूर्ति का प्रबंध है। इतना ही नहीं, विकास की मुख्यधारा में बस्तर को जोड़ने के लिए नई औद्योगिक नीति में आत्मसमर्पित नक्सलियों को रोजगार देने के लिए रोजगार सब्सिडी का प्रावधान है। अनुसूचित जाति-जनजाति और नक्सलवाद प्रभावित लोगों के लिए 10 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी का प्रावधान है। युवाओं के लिए प्रशिक्षण व्यय प्रतिपूर्ति तथा मार्जिन मनी सब्सिडी का प्रावधान है जिसमें अनुसूचित जाति-जनजाति और नक्सलवाद प्रभावित व्यक्तियों द्वारा स्थापित नए एमएसएमई के लिए 25 प्रतिशत तक की सब्सिडी है।

दक्षिण बस्तर की बैलाडिला पहाड़ियों में विश्व के सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के लौह अयस्क हेमेटाइट आयरन की खदानें हैं। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बैलाडिला में वर्ष 1968 से माइनिंग कर रहा है। यहां इतना लौह अयस्क मौजूद है कि अभी कई दशकों तक यहां खनन किया जा सकता है। दंतेवाड़ा में ही बचेली-किरंदुल में एनएमडीसी के पास कुल 11 डिपॉजिट हैं, जिनमें कुल 1343.53 मिलियन टन आयरन और डिपॉजिट है। एनएमडीसी देश की सबसे बड़ी और दुनिया की छठवीं आयरन ओर उत्पादक कंपनी है। बैलाडिला देश ही नहीं, विश्व के सबसे बड़े लौह अयस्क भंडार क्षेत्रों की टॉप दस स्थानों की सूची में शामिल है। यहां छत्तीसगढ़ का 70 फीसदी लौह अयस्क जमा है। प्रदेश के दूसरे बड़े भंडार क्षेत्र रावघाट को भी मिला लिया जाए तो यह आंकड़ा 80 फीसदी से अधिक पहुंच जाता है।

रावघाट क्षेत्र भी बस्तर में ही है। बस्तर संभाग के चार जिलों दंतेवाड़ा, कोंडागांव, कांकेर और नारायणपुर में कुल मिलाकर 2151 मिलियन टन लौह अयस्क मौजूद है। उत्तर बस्तर के भानुप्रतापपुर क्षेत्र में हाहालद्दी, आरीडोंगरी में भी लौह अयस्क भंडार हैं। रावघाट में सेल को 2028 हेक्टेयर क्षेत्र में माइनिंग लीज मिली है। वहां से भिलाई स्टील प्लांट के लिए अयस्क की आपूर्ति की जाएगी। बैलाडिला में अभी अकेले एनएमडीसी खनन कर रहा है। लेकिन अब निजी कंपनियों के भी बस्तर में खनन के द्वार खुल रहे हैं। इससे बस्तर देश के विकास में हिस्सेदारी रखने वाला एक प्रमुख क्षेत्र बन जाएगा।

● **रायपुर से टीपी सिंह**

बनेगा एआई पार्क

छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में इसी वर्ष मई में देश के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डेटा सेंटर पार्क की नींव रखी गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गत 3 मई को नवा रायपुर के सेक्टर-22 में इसकी आधारशिला रखी। इस डेटा सेंटर पार्क को 13.5 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है, जिसमें 2.7 हेक्टेयर हिस्सा विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसआजेड) के रूप में विकसित होगा। इस परियोजना के जरिए लगभग 500 प्रत्यक्ष और 1500 अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर तैयार होंगे। रैक बैंक डेटा सेंटर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित यह परियोजना पूरी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) सेवाओं को समर्पित होगी। पहले चरण में 5 मेगावाट क्षमता से शुरू होकर इसे 150 मेगावाट तक विस्तारित किया जाएगा। भविष्य में इस परियोजना में लगभग 2000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश संभावित है। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए इस डेटा सेंटर को हरित और ऊर्जा दक्ष तकनीक के अनुरूप डिजाइन किया गया है।

देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस वर्तमान में जितनी कमजोर है, उतनी पहले कभी नहीं हुई। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कांग्रेस की अपनी कोई नीति नहीं है। आलम यह है कि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाने में भी विफल साबित हो रही है। इससे पार्टी निरंतर कमजोर होती जा रही है।

विपक्ष की भूमिका में विफल कांग्रेस

सिकुड़ते जनाधार के बाद भी गांधी परिवार मजबूत

सोनिया गांधी के सक्रिय राजनीति में आने के औपचारिक फैसले के बाद तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी की 1998 में पद और कांग्रेस मुख्यालय से अपमानजनक विदाई इतिहास का हिस्सा है। 2004-14 के बीच यूपीए सरकार के डॉ. मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रित्व के दोनों कार्यकालों में इस परिवार के वर्चस्व की चर्चा होती रही। बेशक इस बीच कांग्रेस का जनाधार लगातार सिकुड़ा है लेकिन पार्टी पर नेहरू-गांधी परिवार की पकड़ बदस्तूर कायम है। फिलहाल पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हैं लेकिन पार्टी के छोटे से बड़े नेता-कार्यकर्ता को गांधी परिवार का ही नेतृत्व स्वीकार्य है। फिलहाल केवल तीन राज्यों कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में पार्टी की अपने बूते सरकार है। झारखंड और बिहार जैसे राज्यों में जूनियर पार्टनर के तौर पर वह सत्ता से जुड़ी है। देश के सबसे बड़े राज्य उप्र जहां से नेहरू-गांधी परिवार के तीन सदस्य जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, वहां की 80 लोकसभा सीटों में उसकी एक और 403 सदस्यीय विधानसभा में सिर्फ दो सीटों की हिस्सेदारी है।

भारतीय लोकतंत्र को कमजोर करने में उसी कांग्रेस का हाथ नजर आ रहा है जो कभी कांग्रेस का हाथ, आम आदमी के साथ का नारा देती थी और आम आदमी ने तो अपनी नई पार्टी ही बना डाली। किसी लोकतंत्र में जनता के लिए उन्हीं की चुनी सरकार चलाने के बड़े मायने हैं। कभी बहुमत तो कभी जोड़-तोड़ वाले गठबंधन से, जिसे भी जनादेश मिलता है, सच्चे लोकतंत्र में वही सत्ता का अधिकारी होता है। लेकिन इन सबमें भी एक सच्चे और तगड़े विपक्ष की भूमिका गौण नहीं हो जाती। जिस तरह हर इंसान को निंदक नियरे राखिये की तर्ज पर अपनी कमियां बताने की हिम्मत रखने वाले को सुनने का धैर्य होना चाहिए। वैसे ही एक आदर्श लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ताधारी पक्ष को भी विपक्ष को सुनने और उसके साथ संवाद का रास्ता खुला रखना चाहिए।

वर्तमान में कांग्रेस संतुलित एवं सामान्य राजनीतिक गतिविधियों वाली पार्टी नहीं दिख रही। राहुल गांधी और उनके सलाहकार-रणनीतिकार, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आदि के वक्तव्य-क्रियाकलाप देखकर ऐसा ही लगता है। कई कांग्रेस नेताओं की भी ऐसी ही धारणा है कि उनकी पार्टी की दशा-दिशा और रीति-नीति वह है ही नहीं, जो कांग्रेस की होनी चाहिए। पिछले दिनों मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि आज की कांग्रेस न पं. नेहरू की कांग्रेस है, न इंदिरा गांधी की और यह राजीव गांधी की भी कांग्रेस नहीं है। यह सच है कि कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है। इस कारण सरकार के फैसलों की निर्मम समीक्षा और विभिन्न मुद्दों पर आक्रामक होकर उसे घेरना कांग्रेस का कर्तव्य है, लेकिन जब बात देश हित की आए तो पार्टी से उम्मीद की जाती है कि वह सामान्य परिपक्वता दिखाएगी, परंतु कांग्रेस इसके ठीक उलट विरोध के नाम पर अतिवादी आचरण करती दिख रही है। यह स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी देश के अंदर युद्ध लड़ रहे हैं और भारत में राजनीतिक बदलाव के लिए विदेश से समर्थन पाने की कोशिश में लगे हैं। वे विदेश में भारत की ऐसी डरावनी तस्वीर प्रस्तुत करते हैं जैसे देश में धर्म, अभिव्यक्ति, राजनीतिक गतिविधियों और अन्य वैयक्तिक स्वतंत्रताओं को सत्ता के दुरुपयोग से नष्ट कर दिया गया है।

सोनिया गांधी ने हाल में एक अंग्रेजी दैनिक में लिखे आलेख में ईरान-इजराइल युद्ध में सरकार की नीति की आलोचना करते हुए मांग की कि केंद्र सरकार को इस पर मुंह खोलना चाहिए। उनके कहने का आशय था कि भारत को ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। इजराइल-हमास संघर्ष के दौरान भी कांग्रेस फलस्तीन के बहाने हमास और उसकी समर्थक इस्लामिक शक्तियों के साथ खड़ी दिखी, किंतु उसने हमास द्वारा निरपराध इजराइलियों की हत्या पर एक शब्द नहीं बोला। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया में पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भारत सरकार ने 7 सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल विभिन्न देशों में भेजे। इसमें कांग्रेस के भी सदस्य थे। हैरानी की बात है कि कांग्रेस के रणनीतिकारों ने अपने ही सदस्यों शशि थरूर, सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी के चरित्र हनन का प्रयास किया। अपने ही नेताओं के वक्तव्यों और भूमिका पर लगातार कटाक्ष से बड़ा अतिवाद क्या हो सकता है?

थरूर के विरूद्ध तो पार्टी के अंदर ऐसा अभियान चल रहा है जैसे उन्होंने कांग्रेस से गंभीर विश्वासघात कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के अंदर भी एक बड़ा दुष्प्रचार अभियान चला, जो आज तक जारी है। राहुल गांधी यहां तक कहने लगे कि ट्रंप ने फोन किया और प्रधानमंत्री ने युद्ध विराम कर दिया। उन्होंने इसकी कोई चिंता नहीं की कि इससे भारत की कमजोर देश की छवि बनती है, जो अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान जैसे आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देशों के विरूद्ध भी कार्रवाई से पीछे हट सकता है। राहुल गांधी चुनाव आयोग जैसी संस्था को भी भाजपा का आदेशपालक साबित करने के लिए हर सीमा लांघ चुके हैं। महाराष्ट्र चुनाव परिणाम के किसी तथ्यात्मक

नेता विपक्ष की हैसियत भी न मिली

आजादी के बाद पहला लोकसभा चुनाव 1952 में हुआ। बीच की अवधि में संविधान सभा का कार्य पूर्ण हो जाने के बाद उसे अस्थायी संसद के तौर पर बदल दिया गया था। आजादी के संघर्ष की अगुवाई कांग्रेस ने की थी। स्वाभाविक रूप से संविधान सभा के बहुसंख्य सदस्य भी उसी से जुड़े हुए थे। 313 सदस्यीय अस्थाई सदन में औपचारिक तौर पर कोई विपक्ष नहीं था। जो कांग्रेस में नहीं थे उन्हें असम्बद्ध सदस्य माना जाता था। शुरुआत में उनकी संख्या 22 थी। 1951 में यह संख्या 28 हो गई। पहली बार 1969 में कांग्रेस के विभाजन के बाद कांग्रेस (ओ) के नेता डॉक्टर राम सुभग सिंह को विपक्ष के नेता का अधिकृत दर्जा प्राप्त हुआ था। लेकिन आजाद भारत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली पार्टी पिछले दो लोकसभा चुनावों में नेता विपक्ष के लिए जरूरी लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की 10 प्रतिशत सीटें हासिल नहीं कर सकी है। 2014 में उसे 44 और 2019 में 52 सीटें हासिल हुई थी।

आंकड़े और उत्तर से उनका लेना-देना नहीं है। ईवीएम के विरूद्ध दुनियाभर में अभियान और भारत की चुनाव प्रणाली को बदनाम करना इन दिनों कांग्रेस के एजेंडे में सबसे ऊपर दिख रहा है। जबकि सुप्रीम कोर्ट भी इस पर सुनवाई कर चुका है। बावजूद इसके कांग्रेस के रवैये में बदलाव नहीं आ रहा है। क्या कांग्रेस यह सब अनजाने में कर रही है या इसके पीछे उसकी कोई सोची-समझी दूरगामी नीति और योजना है? मुस्लिम वोट पाने और उसे बनाए रखने की उसकी रणनीति तो साफ है, पर लगता है यह यहीं तक सीमित नहीं है। एक समय दुनियाभर में हिंसक क्रांति से सत्ता परिवर्तन करने या सत्ता पर कब्जा करने की राजनीति करने वाली वामपंथी पार्टियां इसी तरह दुष्प्रचार से छवि बनाती थीं कि संपूर्ण सत्ता कुछ लोगों, पूंजीपतियों की गिरफ्त में है।

न्यायपालिका, कार्यपालिका सब एक होकर उसका साथ दे रही हैं। आमजन शोषण-दमन के शिकार हो रहे हैं, उनके अधिकार कुचले जा रहे हैं। संविधान और कानून के कोई मायने नहीं रह गए हैं। लोगों में असंतोष पैदा कर विद्रोह के लिए उकसाना और फिर खूनी क्रांति एवं सरकारों को सत्ता से बेदखल करने तक अभियान चलता रहता था। ऐसा प्रतीत होता है कि जाति जनगणना, संपत्ति सर्वे, समान बंटवारा की बात कर राहुल गांधी इसी तरह लोगों में असंतोष पैदा करना चाहते हैं। पिछले कुछ वर्षों में दुनियाभर में नए प्रकार का लेफ्टिज्म उभरा है। पूर्व कम्युनिस्टों से विपरीत इसमें विश्वभर के बड़े-बड़े पूंजीपति, वैश्विक संस्थाएं, थिंक टैंक, देशों की सत्तारूढ़ या विपक्ष की पार्टियां हैं। एक बड़ी इस्लामी लाबी भी इसमें है। इसकी धार्मिक, अभिव्यक्ति, वैयक्तिक स्वतंत्रता से लेकर शासन, समाज, पर्यावरण, सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, उपभोग आदि को लेकर अपनी योजनाएं हैं।

देशों में और वैश्विक स्तर पर भी ये वर्तमान सत्ता की जगह अपने मनमाफिक व्यवस्था कायम करना चाहते हैं। लगता है कि राहुल गांधी को किसी ने यह समझा दिया है कि भाजपा, नरेंद्र मोदी, संघ, हिंदुत्व और उससे संबद्ध भारतीय राष्ट्र के सोच के विरूद्ध लगातार हमलावर रुख से उनका समर्थन बढ़ेगा और सत्ता में वापसी होगी। भारत की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी का, जिसने लंबे समय तक केंद्र से लेकर राज्यों तक शासन किया हो, उसका सत्ता हासिल करने का यह तौर-तरीका चिंतित करने वाला है। बेशक कांग्रेस 140 साल पुरानी पार्टी है लेकिन आजादी के पहले और आजादी के बाद की कांग्रेस में बहुत बड़ा फर्क रहा है। आजादी के संघर्ष की कांग्रेस में पार्टी संगठन निर्णायक स्थिति में था। आजादी के बाद की कांग्रेस पार्टी नेहरू-गांधी की पर्याय रही है। इस अवधि में पार्टी सत्ता में रही हो अथवा विपक्ष में, दोनों ही दशा में नेहरू-गांधी परिवार के फैसले अंतिम रहे हैं। आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी के 18 अध्यक्ष बने हैं। आजादी के बाद इन 76 सालों में से 38 साल नेहरू-गांधी परिवार के सदस्य ही पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। शेष अवधि के 20 अध्यक्ष या तो परिवार के आगे दंडवत रहे अथवा उन्हें पद छोड़ना पड़ा। असलियत में परिवार के दबदबे की शुरुआत आजादी के ठीक पहले पार्टी अध्यक्ष के 1946 के चुनाव में पड़ गई, जब गांधीजी के दबाव में किसी भी राज्य की कमेटी से प्रस्ताव न होने के बाद भी पंडित जवाहर लाल नेहरू अध्यक्ष चुन लिए गए। इस चुनाव में 15 में 12 राज्य कमेटियां सरदार पटेल और दो आचार्य कृपलानी के पक्ष में थीं। एक कमेटी तटस्थ थी।

कांग्रेस के इतिहास में 1950 का अध्यक्ष पद का चुनाव याद किया जाता है जब सरदार पटेल गुट के उम्मीदवार पुरुषोत्तम दास टंडन ने नेहरू समर्थित आचार्य कृपलानी को पराजित कर दिया था। सरदार पटेल की 15 दिसंबर 1950 को मृत्यु के बाद टंडन को नेहरू के दबाव में इस्तीफा देना पड़ा था। उसके बाद पार्टी अध्यक्ष पर या तो नेहरू-गांधी परिवार अथवा उसके वफादार ही टिके रह सके। 1969 में कांग्रेस के ऐतिहासिक विभाजन का कारण नेहरू-गांधी परिवार को पार्टी के भीतर से मिल रही चुनौती थी। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष एस निंजलिगप्पा की अगुवाई में पार्टी द्वारा राष्ट्रपति पद के लिए चयनित उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी को इंदिरा गांधी ने स्वीकार नहीं किया। निर्दलीय वीवी गिरि को उन्होंने समर्थन और जीत दिलाई। पार्टी दो हिस्सों में बंट गई लेकिन 1971 के लोकसभा चुनाव में जबरदस्त जीत के जरिए इंदिरा गांधी ने सिद्ध किया कि जहां वो और उनका परिवार है, वही असली कांग्रेस है। 1977 की जबरदस्त पराजय के बाद 1978 में कांग्रेस एक बार फिर बंटी। लेकिन 1980 में सत्ता में वापसी के जरिए पार्टी पर परिवार का नियंत्रण कायम रहा। देश की सबसे पुरानी पार्टी नेहरू-गांधी परिवार पर कितना आश्रित हो चुकी है इसकी बानगी राजीव गांधी के 1991 में निधन के बाद देखी जा सकती है। जाहिर तौर पर अगले 6 वर्षों तक परिवार का कोई सदस्य सक्रिय राजनीति में नहीं था लेकिन 1991 में नरसिम्हा राव की प्रधानमंत्री पद पर ताजपोशी सोनिया गांधी की सहमति से ही संभव हुई। प्रधानमंत्री के तौर पर सोनिया गांधी को खुश रखने की राव हर मुमकिन कोशिश करते रहे। बात दीगर है कि वे इसमें कामयाब नहीं रहे।

● **विपिन कंधारी**

बिहार में इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग विपक्षी पार्टियों के निशाने पर है। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। इस बीच, चुनाव आयोग ने सियासी दलों को जवाब दिया और साथ ही एक अपील भी की है। आयोग ने पार्टियों से कहा है कि बेबुनियाद आरोपों से कुछ हासिल नहीं होगा। समय व्यर्थ की जगह सभी दल हर मतदान केंद्र पर अपने बीएलए नियुक्त करें।

नफा और नुकसान का सियासी गणित

जैसे-जैसे बिहार चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे-वैसे राजनीतिक दलों की रणनीतियां भी सामने आ रही हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मी के बीच कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कथित मैच फिक्सिंग का आरोप लगाकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र में मतदाता सूची में हेरफेर और मतदान प्रतिशत में असामान्य वृद्धि हुई और यह चुनावी धांधली का ब्लूप्रिंट अब बिहार में लागू हो सकता है। इस बयान पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की ओर से तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है, जबकि महागठबंधन ने इसे जनता के हित में उठाया गया मुद्दा करार दिया है। यह विवाद बिहार की सियासत में नया मोड़ ला सकता है, क्योंकि एनडीए के नेता अब यह कहने लगे हैं कि बिहार चुनाव से पहले ही राहुल गांधी ने महागठबंधन की हार मान ली है। आखिर इसके राजनीतिक संदेश क्या हैं, क्या राहुल गांधी ने वाकई में एक तरह से सेल्फ गोल कर लिया है या फिर चुनाव आयोग पर सवाल उठाकर बड़ा दांव चला है?

राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर दावा किया कि महाराष्ट्र में 2019 से 2024 तक मतदाता संख्या में 31 लाख की बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन मई 2024 से नवंबर 2024 तक केवल पांच महीनों में ही 41 लाख मतदाताओं की संख्या में असामान्य वृद्धि दर्ज की गई। उन्होंने इसे फर्जी मतदाता करार दिया और आशंका जताते हुए कहा कि बिहार में भी ऐसा हो सकता है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए पूछा कि अगर कुछ छिपाने की बात नहीं है तो उनके सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है।

राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर सवाल उठाने को लेकर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पलटवार करते हुए कहा कि, राहुल गांधी का सोशल मीडिया पोस्ट फर्जी विमर्श गढ़ने का एक ब्लूप्रिंट है, क्योंकि वह लगातार चुनाव हारने से दुखी और हताश हैं। वह चरण दर चरण इस प्रकार करते हैं। पहले चरण में कांग्रेस पार्टी अपनी हरकतों के कारण चुनाव दर चुनाव हारती है। दूसरे चरण में आत्मनिरीक्षण करने के बजाय, वह (राहुल गांधी) विचित्र षड्यंत्र रचते हैं और धांधली का रोना रोते हैं। तीसरे चरण में सभी तथ्यों और आंकड़ों की अनदेखी करते हैं और चौथे चरण में बिना सबूत के साथ संस्थाओं को बदनाम करते हैं। जेपी नड्डा ने आगे लिखा, तथ्यों की अपेक्षा सुर्खियों की उम्मीद करना और बार-बार पोल खुलने के बावजूद वह (राहुल गांधी) बेशर्मी से झूठ फैलाते रहते हैं। वह ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार में उनकी हार निश्चित है। जेपी नड्डा ने कहा कि लोकतंत्र को

नाम कटने से बिगड़ेगा सियासी गणित

वोटर वेरिफिकेशन अभियान से लाखों नाम कटने और कई विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी गणित बिखरने की आशंका भाजपा और जेडीयू के नेताओं को भी है। कई नेता अंदरूनी तौर पर जताते नजर आ रहे हैं, लेकिन सार्वजनिक तौर पर वो अपने बीएलए पर भरोसा जताते हुए कहते हैं कि एनडीए में कोई फूट नहीं होगी और सबकुछ ठीक कर लिया जाएगा। चुनाव आयोग के राज्यव्यापी वोटर्स वेरिफिकेशन अभियान को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि इस प्रक्रिया से राज्य से बाहर रहने वाले लगभग 3 करोड़ प्रवासी बिहारी मतदाता में से अधिकतर मतदाता सूची से बाहर हो सकते हैं, जबकि भाजपा पिछले कुछ महीनों से इस वर्ग को लेकर राष्ट्रवाद और विकास आधारित प्रचार अभियान चलाती रही है। यदि वोटर वेरिफिकेशन अभियान में इनकी उपस्थिति दर्ज नहीं हो पाई तो यह न सिर्फ मतदाता सूची से नाम कटने का कारण बनेगा, बल्कि राजनीतिक असंतोष को भी बढ़ा सकता है। इसका सीधा नुकसान भाजपा और एनडीए को हो सकता है।

नाटक की नहीं, बल्कि सच्चाई की जरूरत है। बता दें कि इससे पहले चुनाव आयोग की ओर से भी बयान आया था कि चुनाव के फैसले पक्ष में नहीं आने के बाद ऐसे आरोप लगाना बेतुके हैं। 24 दिसंबर 2024 को ही कांग्रेस को भेजे अपने जवाब में ये सभी तथ्य सामने रखे थे, जो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। ऐसा लगता है कि बार-बार ऐसे मुद्दे उठाते हुए इन सभी तथ्यों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है।

वहीं, एनडीए ने कांग्रेस नेता के इस बयान को राहुल गांधी की हताशा और बिहार में हार की आशंका का डर बताया। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने भी तंज कसते हुए कहा, हार मानने वाले लोग ऐसी बातें करते हैं। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने राहुल पर निशाना साधते हुए कहा कि वे ईवीएम पर सवाल उठाकर पहले से ही हार का बहाना बना रहे हैं। जबकि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल के आरोपों को पहले ही हास्यास्पद साजिश करार दिया और कहा कि इसमें कोई तथ्य नहीं है। जबकि आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों वाले महागठबंधन ने राहुल गांधी के बयान का बचाव किया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि राहुल ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक जायज सवाल उठाया है। उन्होंने कहा, जो लोग वोटरों के जनादेश को हेरफेर से हासिल करना चाहते हैं वे इन सवालों से अब बौखला गए हैं। कांग्रेस के बिहार प्रभारी राजेश कुमार ने कहा कि राहुल का बयान बिहार की जनता को सतर्क करने की कोशिश है, ताकि वे अपने मताधिकार की रक्षा करें।

बहरहाल, राहुल गांधी का यह बयान राजनीतिक जानकारों की नजर में महागठबंधन की रणनीति में एक दोधारी तलवार है। राजनीतिक जानकार अशोक कुमार शर्मा कहते हैं कि एक ओर यह मतदाताओं में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाकर एनडीए के खिलाफ माहौल बना सकता है। खासकर युवाओं और अल्पसंख्यक समुदायों में। लेकिन, दूसरी ओर यह बयान महागठबंधन को डिफेंसिव भी कर गया है क्योंकि एनडीए इसे महागठबंधन की हार की स्वीकारोक्ति के रूप में प्रचारित कर रहा है। बता दें कि यह हार का डर तब और प्रासंगिक लगने लगता है जब 2024 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के बिहार में 11 सीटें जीतने और एनडीए के 29 सीटों के साथ बेहतर प्रदर्शन की बात होती है।

बता दें कि बिहार में अक्टूबर-नवंबर 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में एकजुट होकर मैदान में है। 2024 के उपचुनाव में एनडीए ने चार में से चार सीटें जीतकर अपनी ताकत दिखाई थी, जबकि महागठबंधन को बेलागंज जैसे गढ़ में हार का सामना करना पड़ा। एक तरफ चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) का उभार और उनकी नव संकल्प रैली एनडीए को दलित और ओबीसी वोटरों में मजबूती दे रही है। वहीं, राहुल गांधी का बयान महागठबंधन के लिए जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि यह मतदाताओं में अविश्वास पैदा कर सकता है। हालांकि, राजनीतिक जानकार राहुल गांधी के आरोपों में कुछ सकारात्मक संभावनाएं भी देखते हैं।

अशोक कुमार शर्मा कहते हैं कि राहुल गांधी के बयान को अगर सही तरीके से पब्लिक के बीच ले जाया जाए तो यह एनडीए की कथित चुनावी गड़बड़ियां कराने की बात को महागठबंधन मुद्दा बना सकता है। कांग्रेस की न्याय संवाद और पलायन रोको, नौकरी दो जैसे कार्यक्रम के जरिये बिहार में अपनी पैठ बनाने में लगी है। ऐसे में राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर सवाल उठाना एक रणनीतिक कदम हो सकता है, जो महागठबंधन को बिहार में एंटी-इनकंबेंसी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों के साथ जोड़कर एनडीए को घेरने की कोशिश है। हालांकि, एनडीए की तीखी प्रतिक्रिया और राहुल गांधी के बयान को हार की स्वीकारोक्ति के रूप में पेश करना महागठबंधन के लिए नुकसानदायक हो सकता है।

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग के मतदाता सूची को लेकर विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान पर इंडिया गठबंधन के घटक दल कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट पार्टियों ने आपत्ति जताई है और चुनाव आयोग पर जमकर हमला बोला है, लेकिन अब विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर एनडीए के सहयोगी दलों में भी असंतोष के स्वर उठने लगे हैं। भाजपा समेत एनडीए नेताओं को प्रवासी बिहारी मतदाताओं के नाम सूची से कटने का डर भी सता रहा है। एनडीए नेता उपेंद्र कुशवाहा ने सार्वजनिक तौर पर असंतोष जाहिर करते हुए चुनाव आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए दिए गए समय को कम बताया है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टी के लोगों के मन में बहुत सारी आशंकाएं हैं। चुनाव आयोग को उन सभी आशंकाओं को दूर करना चाहिए। इससे पहले भी कुशवाहा ने ये मांग की थी कि चुनाव आयोग को बिहार के प्रवासी मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में बनाए रखने का ख्याल रखना चाहिए। दरअसल भाजपा और एनडीए के नेताओं को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में प्रदेश से बाहर रह रहे प्रवासी वोटरों के नाम सूची से गायब ना हो इसकी चिंता सता रही है।

● **इन्द्र कुमार**

गहन संशोधन की जरूरत क्यों?

चुनाव आयोग ने गहन पुनरीक्षण के पीछे कई कारण गिनाए हैं। इनमें शहरीकरण की तेज गति, आंतरिक पलायन, मृतकों के नाम सूची से हटाने में देरी, नए योग्य युवाओं का पंजीकरण और कथित रूप से अवैध विदेशी नागरिकों के नामों का शामिल होना शामिल है। आयोग का कहना है कि इन सभी कारणों से मतदाता सूची की शुद्धता प्रभावित होती है और इसे ठीक करने के लिए यह विशेष अभ्यास आवश्यक हैं। इस गहन पुनरीक्षण के दौरान बूथ लेवल ऑफिसर घर-घर जाकर प्रत्येक मतदाता से व्यक्तिगत जानकारी लेंगे। इसके लिए हर मतदाता को एक व्यक्तिगत गणना फॉर्म भरना होगा। 2003 के बाद मतदाता सूची में नाम जुड़वाने वालों को अपने नागरिक होने का प्रमाण भी देना होगा। इसमें पासपोर्ट, जन्म प्रमाणपत्र, माता-पिता के मतदाता पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश, भूमि रिकॉर्ड, स्थानीय निकाय द्वारा जारी निवास प्रमाणपत्र आदि दस्तावेज ही मान्य होंगे। इससे पहले, बीएलए घरों में जाकर गणना पैड भरवाते थे जो परिवार के मुखिया द्वारा भर दिया जाता था, लेकिन इस बार हर व्यक्ति को अलग-अलग दस्तावेज और फॉर्म भरने होंगे। साथ ही, नए मतदाता पंजीकरण के लिए फॉर्म-6 में अब एक अतिरिक्त घोषणापत्र जोड़ा गया है, जिसमें नागरिकता का स्पष्ट प्रमाण देना अनिवार्य होगा।

उद्धव-राज साथ-साथ!

महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के एक साथ आने से न केवल सत्तारूढ़ महायुति के लिए चुनौती बढ़ी है, बल्कि विपक्षी पार्टियों के गठबंधन महाविकास अघाड़ी के लिए राज-उद्धव का साथ गले की फांस बन सकती है। महाविकास अघाड़ी की सहयोगी पार्टी कांग्रेस और एनसीपी (शरद पवार) के लिए राज ठाकरे की सियासत से तालमेल बैठा पाना बहुत सरल नहीं है। ठाकरे बंधुओं के साथ ने महाविकास अघाड़ी के अस्तित्व को लेकर सवाल खड़ा कर दिया है।

मुंबई में आयोजित विजय रैली में उद्धव ठाकरे की सहयोगी पार्टी कांग्रेस की अनुपस्थिति इस ओर इशारा कर रही है। इस साझा मंच ने जहां मराठी अस्मिता और हिंदुत्व की विचारधारा को एक नई ऊर्जा देने का प्रयास किया है, वहीं यह कदम महाविकास अघाड़ी, जिसमें कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी-शरद पवार गुट) और उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) शामिल हैं, के भीतर सियासी तनाव को उजागर किया है। खासकर कांग्रेस और एनसीपी (एसपी गुट) के लिए यह एक सियासी चुनौती बनकर उभरा है। लेकिन महाराष्ट्र में विपक्षी पार्टियों के बीच पहले से ही गठबंधन है। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़े थे। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि राज और उद्धव ठाकरे का साथ महाविकास अघाड़ी के लिए नई चुनौती लेकर आएगा। आइए जानते हैं कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का साथ महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस और एनसीपी के लिए कैसे चुनौती है?

विजय रैली का आयोजन मुंबई में हिंदी को अनिवार्य करने के सरकारी फैसले को वापस लिए जाने की जीत के रूप में किया गया था। इस फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने मोर्चा खोला था और शिवसेना (यूबीटी) ने भी उसका समर्थन किया था। इस मुद्दे पर दोनों नेताओं के बीच संवाद और सहमति बनी, जिसका परिणाम विजय रैली के रूप में सामने आया। इस रैली में मंच पर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ नजर आए, जो 2006 में शिवसेना से टूट के बाद पहली बार हुआ। मंच पर एकजुटता दिखाकर दोनों नेताओं ने संकेत दिया कि मराठी अस्मिता के मुद्दे पर उनका गठबंधन संभव है और यह गठजोड़ आगे भी कायम रह सकता है। राज ठाकरे, बालासाहेब ठाकरे की विचारधारा के करीब माने जाते रहे हैं। उनके भाषणों में हिंदुत्व की झलक स्पष्ट दिखती है, जबकि कांग्रेस और एनसीपी जैसे धर्मनिरपेक्ष विचारधारा की पार्टियों के लिए यह वैचारिक टकराव पैदा करता है। कांग्रेस और एनसीपी पहले ही शिवसेना (यूबीटी) के साथ गठबंधन को लेकर कई बार असहजता जता चुकी हैं। अब यदि शिवसेना, मनसे के साथ भी निकटता बढ़ाती है तो यह गठबंधन और भी जटिल हो जाएगा। मनसे ने अतीत में कई बार हिंदीभाषियों, उत्तर भारतीयों और मुसलमानों को लेकर विवादास्पद बयान दिए हैं, जिससे कांग्रेस व एनसीपी के कोर वोटबैंक को नुकसान हो सकता है।

कांग्रेस और एनसीपी की राजनीति समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय पर टिकी है, जबकि मनसे की राजनीति मराठी मानुष, हिंदुत्व और प्रादेशिक अस्मिता पर आधारित रही है। ऐसे में राज-उद्धव समीकरण यदि मजबूत होता है, तो कांग्रेस और एनसीपी को अपने कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के बीच इसका स्पष्टीकरण देना मुश्किल हो सकता है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के मेल को यदि आगामी चुनावों में महाविकास अघाड़ी के हिस्से के रूप में देखा जाता है, तो कांग्रेस और एनसीपी की भूमिका और नेतृत्व पर सवाल उठेंगे कि क्या वे सिर्फ समर्थन देने वाली पार्टियां बनकर रह जाएंगी? राज ठाकरे के साथ मंच साझा करना उद्धव ठाकरे के लिए एक रणनीतिक कदम था, जो उन्हें मराठी अस्मिता और कट्टर हिंदुत्व की ओर फिर से वापस लाने में मदद कर सकता है। एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना के विभाजन के बाद उद्धव ठाकरे लगातार सेकुलर गठबंधन की राजनीति कर रहे थे। इससे उनका पारंपरिक वोटबैंक नाराज था, जो अब राज ठाकरे के समर्थन से फिर से जुड़ सकता है।

हालांकि, यह कांग्रेस और एनसीपी के लिए असहज स्थिति उत्पन्न करेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उद्धव ठाकरे अगर राज ठाकरे के साथ गठबंधन को मजबूत करते हैं तो महाविकास अघाड़ी का स्वरूप बदल सकता है या टूट सकता है। फिलहाल कांग्रेस और एनसीपी ने इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन राजनीतिक दूरी बनाए रखना उनकी प्राथमिकता लग रही है। विजय रैली में कांग्रेस का शामिल न होना भी इस बात का संकेत है कि वे राज ठाकरे को अपने गठबंधन में शामिल नहीं करना चाहती है। रैली में एनसीपी (एसपी) की ओर से केवल सुप्रिया सुले ही शामिल हुई थीं। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि राज और उद्धव का गठबंधन मजबूत होता है तो कांग्रेस और एनसीपी के पास दो विकल्प होंगे। पहला गठबंधन में रहते हुए न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर सहमति बनाना और दूसरा आगामी चुनावों में स्वतंत्र रणनीति अपनाना और सीमित सीटों पर प्रतिस्पर्धा करना।

● बिन्दु माथुर

निकाय चुनाव पर दिखेगा असर

मुंबई महानगरपालिका चुनाव को लेकर यह गठजोड़ महत्वपूर्ण है क्योंकि एमएनएस और शिवसेना दोनों का वहां मराठी मतदाताओं पर प्रभाव है। यदि दोनों एकसाथ आते हैं, तो भाजपा-शिंदे गुट को कड़ी टक्कर मिल सकती है। वहीं, कांग्रेस और एनसीपी का प्रभाव महानगरपालिका में सीमित रहा है, लेकिन राज्य स्तर पर यदि यह गठबंधन आगे बढ़ता है, तो महागठबंधन का पुनर्गठन अपरिहार्य होगा। उधर, महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री ने उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने ठाकरे के मराठी प्रेम को दिखावटी करार देते हुए कहा कि उनका असली एजेंडा मराठी नहीं, बल्कि मुंबई महानगरपालिका पर कब्जा करना है। ये सब केवल चुनावी ड्रामा है जो चुनाव जीतने के लिए किया जा रहा है। बावनकुले ने उद्धव ठाकरे के हालिया भाषण पर तंज कसते हुए कहा कि वर्ली में ठाकरे ने मराठी के नाम पर सत्ता खोने का शोकगीत गाया है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब उद्धव ठाकरे 2019 से 2022 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, तब 2022 में पहली कक्षा से हिंदी को अनिवार्य करने की सिफारिश को क्यों स्वीकार किया गया?

फिर गरमाया संजीवनी घोटाला

राजस्थान की राजनीति में बहुचर्चित संजीवनी क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी घोटाला एक बार फिर सुर्खियों में है। इस घोटाले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। विवाद की ताजा कड़ी जुड़ी है शेखावत की दिवंगत मां का नाम सार्वजनिक तौर पर लेने और मानहानि केस को लेकर हुई तकरार से। राजस्थान की संजीवनी क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी पर सैकड़ों निवेशकों से करोड़ों की ठगी का आरोप लगा है। आरोप है कि सोसायटी ने निवेश का झांसा देकर बड़ी संख्या में लोगों की रकम डुबोई। जांच में कई राजनीतिक नाम सामने आए, जिनमें गजेंद्र सिंह शेखावत और उनके परिजनों का भी जिक्र हुआ।

मार्च 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया था कि इस घोटाले में शेखावत के परिवार के सदस्य, जिनमें मां, पत्नी और पिता शामिल हैं, की भूमिका रही है। उन्होंने दावा किया था कि एसओजी की जांच में शेखावत की संलिप्तता प्रमाणित हुई है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने हाईकोर्ट में बताया था कि 12 अप्रैल 2023 की एसओजी रिपोर्ट में गजेंद्र सिंह शेखावत, उनकी पत्नी, माता-पिता समेत 68 लोगों को आरोपी माना गया है। रिपोर्ट के अनुसार, निवेशकों से ठगी करने वाली कंपनियों से शेखावत का सीधा संबंध होने की जांच चल रही है। रिपोर्ट का पेज 7 खासतौर पर इस संबंध में उल्लेखनीय है। अशोक गहलोत ने हाल ही में शेखावत से उनके खिलाफ दर्ज मानहानि का केस वापस लेने की अपील की थी। लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे सिरे से खारिज करते हुए कहा कि गहलोत ने सार्वजनिक मंच पर उनकी दिवंगत मां का नाम घसीटकर उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है। शेखावत ने स्पष्ट कर दिया है कि वे यह केस वापस नहीं लेंगे। इस पूरे प्रकरण को लेकर दिल्ली की अदालत में शेखावत द्वारा गहलोत के खिलाफ दर्ज मानहानि केस अभी लंबित है। अक्टूबर 2023 में दिल्ली सेशन कोर्ट ने इस पर अंतिम आदेश नहीं दिया, जबकि दिसंबर 2023 में हाईकोर्ट ने गहलोत से जवाब मांगा और जनवरी 2024 में सुनवाई की तारीख तय की गई थी। अब तक इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं आया है। संजीवनी घोटाला अब केवल आर्थिक घोटाले तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह एक सियासी और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है। दोनों नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी का दौर जारी है, जिससे यह मामला 2025 की राजस्थान राजनीति का एक बड़ा मुद्दा बनकर उभर रहा है। गौरतलब है कि तकरीबन 9 महीने पहले सितंबर 2024 में संजीवनी क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी घोटाले में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को राजस्थान हाईकोर्ट ने क्लीन चिट दे दी थी। अतिरिक्त महाधिवक्ता की ओर से दी रिपोर्ट में भी कहा गया कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। दरअसल, शेखावत की ओर से दायर याचिका में एफआईआर के साथ-साथ जांच को भी रद्द करने को लेकर मांग की गई थी। 17 सितंबर 2024 को जस्टिस अरुण मोंगा की बेंच ने मामले में अंतिम आदेश पारित करते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता को इस सवाल का जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया कि क्या एसओजी गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने का इरादा रखती है। मामले में अतिरिक्त महाधिवक्ता की ओर से एक विस्तृत रिपोर्ट दायर की गई। जिसमें कहा गया कि गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है और कंपनियों में निदेशक के रूप में उनके इस्तीफे के बाद किए गए अपराधों के लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

ऐसे में कोर्ट ने आदेश पारित करते हुए निर्देश दिया कि अतिरिक्त महाधिवक्ता की ओर से पेश रिपोर्ट के आधार पर याचिकाकर्ता गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा था कि मैंने पहले भी कहा था कि सत्य को बादलों के आवरण से ढकने और कालिख पोतने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन, अंत में सत्य सामने आता है। झूठ खड़ा करने का षड्यंत्र, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति और बेटे की हार से उत्पन्न खीझ की मानसिकता के चलते मुझे घसीटने की कोशिश की गई थी। आज न्यायालय ने उस पर अपना फैसला सुनाते हुए एसओजी की जांच को रद्द कर दिया है। वहीं, यह भी कहा है कि आगे न्यायालय की अनुमति के बिना जांच नहीं की जाएगी। घोटाले में गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम इसलिए आया था कि संजीवनी घोटाले के मुख्य आरोपी विक्रम सिंह गजेंद्र सिंह शेखावत के नजदीकी बताए जा रहे थे। इथोपिया में शेखावत और विक्रम सिंह की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर हैं। गजेंद्र सिंह और विक्रम सिंह बिजनेस पार्टनर रह चुके हैं। विक्रम सिंह के खातों से शेखावत और उनके परिजन के बैंक खातों में लाखों रुपए का लेनदेन भी सामने आया था। सांसद बनने से पहले गजेंद्र सिंह ने विक्रम सिंह के साथ अपनी पार्टनरशिप को समाप्त कर लिया था। इधर, पीड़ितों का कहना था कि कंपनी में निवेश के समय शेखावत का नाम प्रमुखता से लिया गया था। विक्रम सिंह ने शेखावत और उनके साथ की फोटो और उनका शेयर में होल्ड आदि दिखाकर निवेश करवाया था।

● **जयपुर से आर.के. बिन्नानी**

निवेशकों के पैसों को गलत तरीके से लोन पर दिया

संजीवनी क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी को राजस्थान सोसायटी एक्ट के तहत 2008 में रजिस्टर्ड कराया गया था। इसके बाद 2010 में यह सोसायटी मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव सोसायटी के रूप में बदल गई। इसका लाइसेंस केंद्र से सोसायटी को मिला और फिर इसमें निवेश करने वालों को अच्छे रिटर्न के साथ विदेश की यात्रा, गोल्ड और सिल्वर कॉइन आदि गिफ्ट का लालच दिया गया। जो निवेश करते, उन्हें ही एजेंट बनाकर उनके अंडर में जो निवेश करते उनका कमीशन उन्हें दिया गया। इससे लालच में आकर लोगों ने मोटी रकम इसमें निवेश की। इसके बाद इस सोसायटी ने निवेशकों के पैसों को गलत तरीके से लोन पर दिया और ब्याज नहीं लिया। देखते ही देखते अन्य राज्यों में ब्रांच खोलकर फर्जी कंपनियों को लोन बांटे गए। इस सोसायटी के पहले मैनेजिंग डायरेक्टर विक्रम सिंह थे, जो पूरे घोटाले के मास्टरमाइंड भी हैं। संजीवनी घोटाले में अगस्त, 2020 में एफआईआर दर्ज की गई थी। एसओजी ने सोसायटी के सीएमडी विक्रम सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। पूरे मामले की जांच में पता लगा था कि सोसायटी ने 2007 में बाड़मेर से शुरुआत की थी।

सनातन पर सियासत

जाकी रही भावना जैसी

बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया है। धीरेंद्र ने जाकी रही भावना जैसी कहते हुए कहा कि हमारे ऊपर टिप्पणी करने वालों की रोटी पच रही है, भगवान करें उनकी रोटी पचती रहे। दरअसल अखिलेश ने कहा था कि कई कथावाचक 50 लाख रुपए तक लेते हैं। पता करवा लीजिए कि धीरेंद्र शास्त्री अंडरटेबल नहीं लेते हैं क्या? धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि देश में अभी बहुत विचित्र स्थिति है। देश को खत्म करने के लिए, दूसरा पाकिस्तान जन्म देने के लिए यदि कोई बीमारी है तो वह है जातिवाद। देश की उन्नति रोकना है, देश का उत्थान रोकना है तो वह है जातिवाद। इस देश में लगातार दंगे कराकर नेताओं को लाभ लेना है तो वह है जातिवाद। हिंदुओं को एकजुट नहीं होने देना है तो उसका उपाय है जातिवाद। जो जातिवाद में फंसा है उससे देश में स्थिति ठीक नहीं होगी। ये घोर निंदनीय है। शिखा, चोटी काटना ये भी निंदनीय है। उससे बड़ी निंदा की बात ये है कि जो उस घटना में घी डाल रहे हैं, संवाद की बजाए विवाद बढ़ा रहे हैं, यदि दो भाई आपस में लड़ रहे हैं तो उसे सुलझाने का काम करना चाहिए। अखिलेश यादव के बयान पर धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि भईया हम राजनीति पर कोई बयान नहीं देते हैं। कोई हम पर कुछ बोलता है तो भगवान की इच्छा मान लेते हैं।

उप्र के इटावा जिले में कथाकार की जाति पूछकर किए गए अमानवीय कृत्य से पूरा देश शर्मसार है। जहां पर जाति न पूछिए साधु की पूछ लीजिए ज्ञान की बात कही जाती हो उस देश में इस प्रकार की घटना हिंदू समाज के माथे पर कलंक है। विचार के आधार पर यदि आचरण नहीं है तो हमारी तत्व निष्ठा व्यर्थ है। अगर सभी संतानें ईश्वर की हैं तो ऊंच-नीचता की भावना नहीं होनी चाहिए। उधर, इटावा के कथावाचक कांड को राजनीतिक रंग देकर उसमें स्वयं फंसते नजर आ रहे सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बाबा बागेश्वर धाम आचार्य धीरेंद्र शास्त्री पर ही हमला बोल दिया और उन पर कथा करने के लिए अंडर द टेबल 50 लाख रुपए लेने का आरोप लगाकर नया विवाद उत्पन्न करने का असफल प्रयास किया है। सपा मुखिया जब इटावा की घटना पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने में सफल नहीं हुए तब उन्होंने हिंदू राष्ट्र का नारा देने वाले धीरेंद्र शास्त्री पर बयान देकर सनसनी मचाने का प्रयास किया। वास्तव में अखिलेश यादव धीरेंद्र शास्त्री की आड़ में अपनी पीडीए राजनीति को हवा देने का प्रयास कर रहे हैं।

सपा मुखिया अखिलेश यादव यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि वर्तमान समय में बाबा बागेश्वर धाम की लोकप्रियता चरम सीमा पर है। बाबा बागेश्वर के लाखों भक्त तथा प्रशंसक हैं, वे जहां भी कथा सुनाने जाते हैं वहां लाखों लोगों की भीड़ उमड़ती है। उनके ऊपर सपा मुखिया ने सुनियोजित षड्यंत्र के अंतर्गत आरोप लगाए हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव घोर जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं और टीवी चैनलों पर अपने प्रवक्ताओं से बहस करवा रहे हैं कि क्या कथा कहना केवल एक जाति का ही अधिकार है? जब वह इस बहस में पिछड़ गए और फंसने लगे तब बाबा बागेश्वर पर हमलावर हो गए। बाबा बागेश्वर ने अखिलेश के आरोपों का उत्तर देते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि अगर दक्षिणा नहीं लेंगे तो कैंसर अस्पताल कैसे बनेगा? उसमें गरीबों का निशुल्क उपचार कैसे होगा? बाबा बागेश्वर धाम गरीब कन्याओं का विवाह कैसे संपन्न करवाएगा? बाबा बागेश्वर यदि हनुमानजी का आशीर्वाद लेकर लोगों की समस्या का समाधान करते हैं तो इससे लोगों को परेशानी क्यों हो रही है ?

ज्ञातव्य है कि बाबा बागेश्वर सोशल मीडिया पर भी एक सेलेब्रिटी की तरह हैं। उनके फेसबुक पर साढ़े 8 करोड़ सोशल मीडिया एक्स पर दो लाख तथा इंस्टाग्राम पर भी दो लाख से अधिक फालोअर्स हैं जबकि करोड़ों लोग उनके यूट्यूब चैनल को नियमित रूप से देखते हैं। अपनी कथा व उपदेशों के माध्यम से वह जनमानस को हिंदू एकता और राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाते हैं। यही कारण है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव सहित अन्य स्वार्थी नेता उन पर सामूहिक हमले करते हैं। विगत वर्ष जब बाबा बागेश्वर कथा करने के लिए बिहार गए थे तब वहां के विरोधी दलों के नेताओं ने उनको जेल में डालने की बात तक कही थी।

बाबा बागेश्वर से उन सभी राजनीतिक दलों व नेताओं को समस्या उत्पन्न हो रही है जो जातिवाद व मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाह रहे हैं। बाबा बागेश्वर धाम जातिवाद को कैंसर के समकक्ष बताते हैं और हिंदू समाज को एक बनाए रखने के लिए काम करते हैं। हिंदू एकता के लिए की गई उनकी पहली पदयात्रा बहुत सफल व लोकप्रिय रही थी, अब वह एक बार फिर नई दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा पर निकलने वाले हैं। सच्चाई यह है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव का बाबा पर यह ताजा हमला उनकी हिंदू संत समाज व सनातन विरोधी मानसिकता को ही दर्शाता है। जो लोग अयोध्या, मथुरा व काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के प्रबल विरोधी रहे हों, जिन लोगों ने अयोध्या में निहत्थे कारसेवकों का नरसंहार किया हो, जिन्होंने कुंभ का उपहास किया हो, वो एक हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले युवा संत का विरोध ही करेंगे। जब महाराष्ट्र के पालघर में संतों को मुस्लिम भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला था तब सपा मुखिया मौन हो गए थे।

सपा मुखिया ने केवल बाबा पर हमला नहीं किया है, अपितु सभी कथावाचकों और संतों सहित सनातन धर्म व उसकी एकता पर किया है। सपा मुखिया को स्पष्ट रूप से रामायण, महाभारत, भागवत कथा, आरती, मंदिर, गौशालाओं, गीता आदि सभी से नफरत है। सपा मुखिया को हर उस अच्छी चीज से नफरत है जिससे हिंदू समाज का गौरव बढ़ता है। सपा के लोग प्राय: रामचरितमानस आदि ग्रंथों का अपमान करने से नहीं चूकते, कभी फाड़ते हैं, कभी जलाते हैं। सपा मुखिया गौशालाओं से बदबू आती है जैसी बातें कहकर भगवान श्रीकृष्ण व समस्त यदुवंशी समाज का अपमान कर चुके हैं। सपा मुखिया ने पहले कथावाचक घटना को राजनीतिक रंग देकर फिर बाबा बागेश्वर पर हमला करके एक बहुत ही निम्न राजनीतिक चाल चली है। उप्र और बिहार ही नहीं वरन पूरे देश को यह समझना होगा कि जातिवाद की राजनीति से ऊपर उठकर स्वार्थी राजनेताओं को पूरी तरह से धूल चटाने का समय आ गया है।

● लखनऊ से मधु आलोक निगम

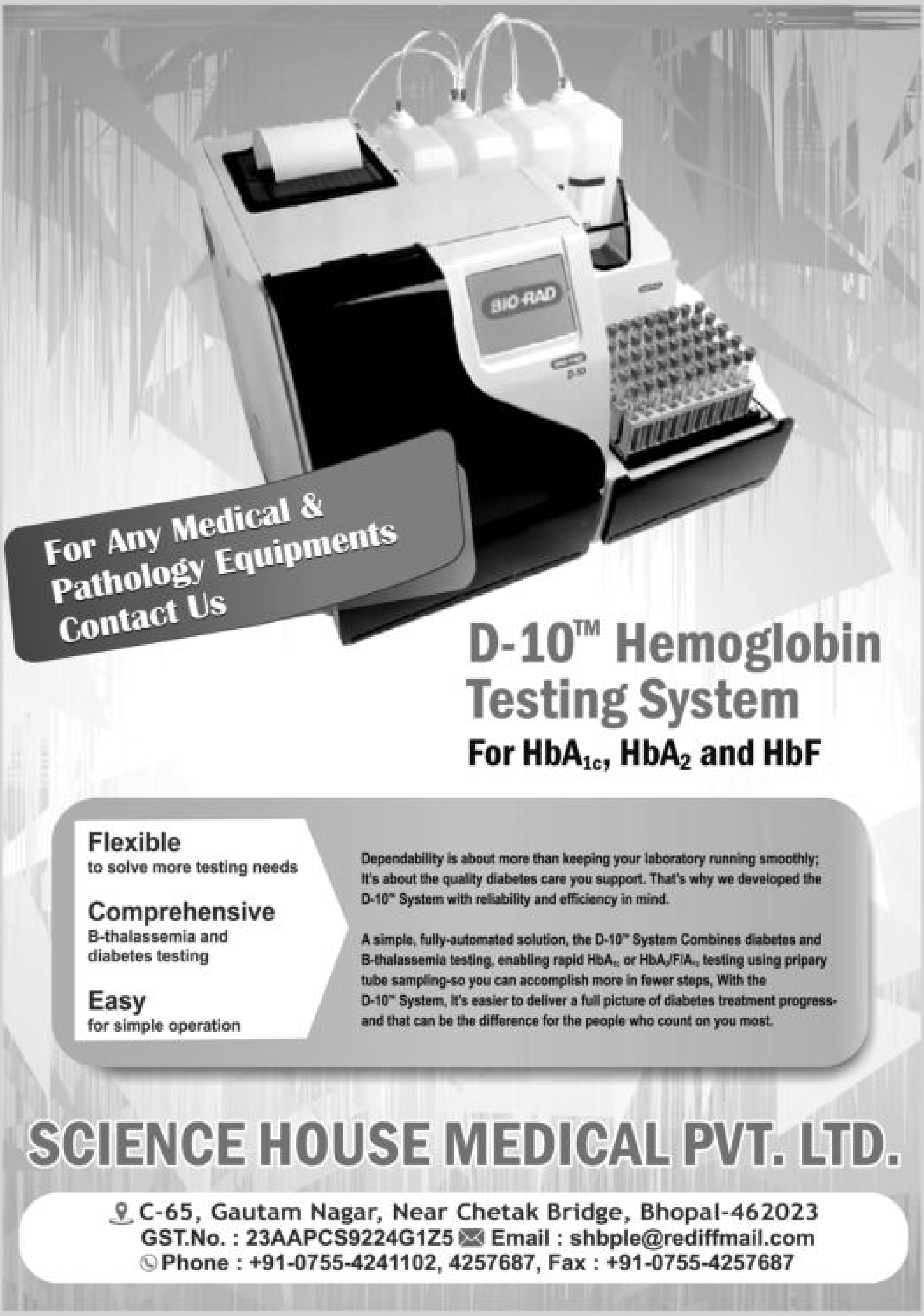

BIO-RAD
For Any Medical &
Pathology Equipments
Contact Us
D-10™ Hemoglobin
Testing System
For HbA_{1c}, HbA_2 and HbF
Flexible
to solve more testing needs
Comprehensive
B-thalassemia and
diabetes testing
Easy
for simple operation
Dependability is about more than keeping your laboratory running smoothly; It's about the quality diabetes care you support. That's why we developed the D-10™ System with reliability and efficiency in mind.
A simple, fully-automated solution, the D-10™ System Combines diabetes and B-thalassemia testing, enabling rapid HbA_{1c} or HbA_2/F/A_{1c} testing using pripary tube sampling-so you can accomplish more in fewer steps, With the D-10™ System, It's easier to deliver a full picture of diabetes treatment progress-and that can be the difference for the people who count on you most.
SCIENCE HOUSE MEDICAL PVT. LTD.
C-65, Gautam Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
GST.No. : 23AAPCS9224G1Z5 Email : shbple@rediffmail.com
Phone : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687

बिहार में 20-20 खेल रहे तेजस्वी

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी तापमान अब पूरी तरह से चढ़ चुका है। भाजपा-जदयू की दोस्ती सत्ता पर अपना वर्चस्व बनाए रखने की कोशिश में है तो राजद-कांग्रेस और वामपंथी दल मिलकर किस्मत आजमा रहे हैं। इंडिया गठबंधन की अगुवाई कर रहे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बिहार की सियासी रणभूमि में नीतीश कुमार को मात देने के लिए वन-डे नहीं बल्कि 20-20 का सियासी मैच खेल रहे हैं। नीतीश कुमार के 20 सालों के शासन के जवाब में तेजस्वी ने 20 महीने में 20 वादों का दांव चला है।

तेजस्वी यादव बिहार की जनता से 5 साल का समय नहीं बल्कि 20 महीने का वक्त मांग कर रहे हैं और 20 महीने में 20 वादे पूरे करने का भी वचन दे रहे हैं। आरजेडी ने बिहार चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया है, लेकिन तेजस्वी यादव ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। तेजस्वी ने जनता के सामने अपना 20 सूत्रीय एजेंडा रखा है, जिसको 20 महीने में पूरा करने का भी वादा किया है। ऐसे में सवाल उठता है कि नीतीश के खिलाफ तेजस्वी का 20-20 का फॉर्मूला कितना कारगर रहेगा?

इंडिया गठबंधन ने भले ही तेजस्वी यादव को बिहार मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित न किया हो, लेकिन 2025 का चुनाव उनकी ही अगुवाई में लड़ने का फैसला किया है। ऐसे में तेजस्वी क्रिकेट की तरह बिहार की सियासत में फ्रंटफुट पर उतरकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं। प्रदेश की जनता के सामने तेजस्वी ने 20 महीने में 20 वादे पूरे करने का एजेंडा रखा है। तेजस्वी ने बिहार के लोगों से डोमिसाइल नीति लागू करने का वादा किया है। इसके बाद 65 फीसदी आरक्षण लागू करने, नौकरी-रोजगार दिलाने, युवा आयोग बनाने, मुफ्त में परीक्षा फॉर्म भरवाने, पेपर लीक पर पूर्ण लगाम लगाने, माई-बहिनों के खाते में हर महीने 2500 रुपए देने, सामाजिक पेंशन 1500 रुपए देने का वादा किया है। इसके अलावा 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने, 200 यूनिट मुफ्त बिजली मुफ्त, ताड़ी को शराबबंदी से बाहर करने, बेटी योजना लागू करने, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित, शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने, स्वास्थ्य की सुविधा सुगम और बेहतर करने, बिहार में नए निवेश लाने, उद्योग-धंधे लगाने, पलायन पर लगाम लगाने और 20वां वादा पर्यटन उद्योग बढ़ाने का किया है।

नीतीश कुमार ने 2005 में आरजेडी के 15 साल के शासन को खत्म कर सत्ता की बागडोर संभाली थी। इसके बाद 20 सालों से बिहार की सियासत नीतीश कुमार के इर्द-गिर्द ही सिमटी हुई है और वे सत्ता की बागडोर अपने हाथों में रखे हुए हैं। इस तरह से नीतीश के 20 साल के शासन के जवाब में तेजस्वी यादव 20 महीने का एजेंडा सेट कर रहे हैं। बिहार की जनता से तेजस्वी 5 साल का समय नहीं मांग रहे हैं बल्कि 20 महीने का वक्त मांग रहे हैं। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करते हुए जदयू के 20 सालों के शासन के जवाब में 20 महीने में 20 वादों को पूरा करने का वचन दे रहे हैं। तेजस्वी यादव 2020 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में वापसी करने से चूक गए थे, लेकिन इस बार कोई मौका नहीं गंवाना चाहते हैं। इसीलिए 2025 के विधानसभा चुनाव में युवाओं को रोजगार देने से लेकर सामाजिक न्याय का एजेंडा सेट करने में जुटे हैं। नीतीश के 20 साल के शासन के जवाब में सिर्फ 20 महीने का ही समय मांग रहे हैं। 20 महीने में 20 वादों को पूरा करने का भी वचन दे रहे हैं। इसके लिए तेजस्वी अगस्त 2020 से जनवरी 2024 तक यानी 17 महीने सत्ता में रहने के दौरान रोजगार से लेकर जातिगत सर्वे और आरक्षण बढ़ाने के काम को रख रहे हैं।

अगस्त 2022 में नीतीश कुमार ने भाजपा से गठबंधन तोड़ लिया था और जनवरी 2024 तक आरजेडी के साथ मिलकर सरकार चलाई थी। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव थे। इन 17 महीनों में नीतीश के अगुवाई वाली महागठबंधन सरकार ने बिहार में जाति सर्वे कराने से लेकर आरक्षण और सरकारी नौकरियों की जबरदस्त भर्ती निकाली थी। इस काम का क्रेडिट तेजस्वी अपने नाम लेना चाहते हैं और अब 20 महीने में 20 वादों को पूरा करने का भी दांव चल रहे हैं, लेकिन 20-20 वाले फॉर्मूले से क्या वे एनडीए से पार पाएंगे?

मुख्यमंत्री नीतीश और प्रधानमंत्री मोदी की सियासी जोड़ी लगातार मजबूत गठबंधन ही नहीं बल्कि एक बेहतर जातीय समीकरण के सहारे उतरी है। पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान में किए गए ऑपरेशन सिंदूर से एनडीए के पक्ष में सकारात्मक माहौल बना हुआ है और मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का फैसला करके विपक्ष के हाथों से बड़ा मुद्दा छीन लिया है। बिहार चुनाव में भाजपा ने इन्हीं मुद्दों के सहारे उतरने की रणनीति बनाई है, जिसे पूरी तरह भेदे बिना सत्ता के सियासी वनवास को खत्म करना इंडिया गठबंधन के लिए काफी मुश्किल है।

● **विनोद बक्सरी**

नीतीश कुमार के खिलाफ सफल होंगे तेजस्वी?

बिहार का विधानसभा चुनाव में नीतीश के अगुवाई वाले एनडीए और तेजस्वी के अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है। नीतीश कुमार की जदयू के साथ भाजपा, चिराग पासवान की एलजेपी, जीतन राम मांझी की एचएएम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। वहीं, तेजस्वी यादव की आरजेडी के साथ कांग्रेस, सीपीआई माले, सीपीआई-सीपीएम और मुकेश सहनी की वीआईपी है। इसके अलावा पशुपति पारस की पार्टी एलजेपी के साथ रहने की संभावना है। इस तरह से दोनों ही गठबंधनों ने प्रदेश के सियासी समीकरण के लिहाज से अपने-अपने गठबंधन बना रखे हैं। एनडीए मुख्यमंत्री नीतीश और प्रधानमंत्री मोदी के नाम और काम पर सियासी माहौल बनाने में जुटी है तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद सियासी फिजा पूरी तरह से उसके पक्ष में दिख रही है। इस तरह से एनडीए बिहार में कास्ट समीकरण से लेकर राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के एजेंडे का ताना-बाना बुन रही है। इस तरह से एनडीए के सियासी चक्रव्यूह को भेदना तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जोड़ी के लिए आसान नहीं है।

विश्व शांति के लिए भी खतरा है पाक

पाकिस्तान के आतंकी ढांचे को खत्म करना जरूरी

पाकिस्तान के आतंकी चरित्र ने न केवल दक्षिण एशिया की शांति में खलल डाला है, बल्कि वैश्विक सुरक्षा के लिए भी वह नासूर बन गया है। उससे निपटने की आधी-अधूरी कार्रवाई से बात नहीं बनने वाली। उसके साथ कूटनीतिक सक्रियता का समय भी अब निकल गया। पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी ढांचे को ध्वस्त किए बिना दक्षिण एशिया में शांति संभव नहीं। समय आ गया है कि पाकिस्तान को केवल पहलगाम के लिए ही नहीं, बल्कि दशकों से चले आ रहे छद्म युद्ध में गंवाई हर एक जान के लिए जिम्मेदार और जवाबदेह बनाकर न्याय के कठघरे में खड़ा किया जाए।

पहलगाम के आतंकी हमले ने द्विपक्षीय समीकरण ही नहीं, बल्कि समूचे दक्षिण एशिया में संबंधों के तानेबाने को प्रभावित किया है। इस हमले ने आतंक की नीति को जारी रखने वाली पाकिस्तानी मंशा को प्रकट किया था। पर्यटकों से उनकी मजहबी पहचान पूछकर की गई हत्याओं को लश्कर के पिट्ठू संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ ने अंजाम दिया। इसे केवल एक नरसंहार के रूप में न देखा जाए। यह भू-राजनीतिक उकसावे की एक सुनियोजित कार्रवाई थी। इसने जहां आतंक को पालने-पोसने वाले पाकिस्तान के कलंकित इतिहास को दोहराया, वहीं इसके पीछे की एक मंशा जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा ढांचे को अस्थिर करने की भी थी।

वैश्विक निगरानी और अंतरराष्ट्रीय दबाव के बावजूद पाकिस्तान ने अपनी जमीन पर संचालित आतंकी ढांचे को समाप्त नहीं किया है। पहलगाम हमला भी उसी पुराने ढर्रे पर किया गया, जहां सेना-आईएसआई की आतंकी करतूत से इस्लामाबाद ने आदतन किनारा कर लिया। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व की हरी झंडी के बिना ऐसे किसी हमले को अंजाम दिया गया होगा। पहलगाम हमले के बाद भारत ने आर्थिक, कूटनीतिक और सामरिक मोर्चों पर बहुत कारगर कदम उठाए और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। दूसरी ओर, पाकिस्तान लकीर पीटने वाले ढर्रे पर चलते हुए बस शेखी बघारता रहा। भारत ने जहां सिंधु जल समझौते को ठंडे बस्ते में डालकर पाकिस्तान और उसकी आर्थिकी की कमर तोड़ने वाला दांव चला, वहीं पाकिस्तान शिमला समझौते से पीछे हटने का निरर्थक राग अलापता रहा।

कश्मीर में दशकों की अस्थिरता से उबरते हुए पटरी पर आ रही पर्यटन गतिविधियां आतंकी हमले के बाद फिर से अनिश्चितता के भंवर में फंस गई हैं। हालांकि इसका आर्थिक खामियाजा जम्मू-कश्मीर से परे समूचे दक्षिण एशिया को भुगतना पड़ रहा है। इस पृष्ठभूमि में भारत-पाकिस्तान, दोनों ने व्यापार, निवेश और वीजा आदि के मोर्चे पर जो कदम उठाए हैं, उससे क्षेत्रीय सहयोग के साथ ही आर्थिक-व्यापारिक गतिविधियों पर भी ग्रहण लगा है। इस तरह एक देश की आतंक समर्थक नीतियों की कीमत पूरे क्षेत्र को अपनी शांति एवं समृद्धि गंवाने के रूप में चुकानी पड़ रही है। यहां तक कि पाकिस्तान के इस रवैये का दंश वहां की जनता को भी भुगतना पड़ रहा है। उसे फर्जी राष्ट्रवाद की घुट्टी पिलाई जा रही है। भले ही पाकिस्तान खुद को आतंक से पीड़ित दिखाने का प्रयास करता रहे, लेकिन उसकी पहचान आतंक से निपटने में शिथिलता दिखाने वाले देश की ही है। करीब ढाई माह पुराने पहलगाम हमले ने आतंकी गतिविधियों के मामले में पाकिस्तान को लेकर अंतरराष्ट्रीय चिंताओं को नए सिरे से उभारने का काम किया है। पूर्व में पाकिस्तान को ग्रे-लिस्ट में रखने वाली एफएटीएफ जैसी संस्था के समक्ष भी पाकिस्तान पर अंकुश लगाने का दबाव बढ़ेगा। इससे पाकिस्तान की छवि और खराब होगी। आर्थिक निवेश और विकास को लेकर उसकी उम्मीदों को पलीता लगेगा।

पहलगाम हमला पाकिस्तान के आतंकी चरित्र में एक खतरनाक बदलाव का भी परिचायक है। 2001 की शुरुआत से पाकिस्तान पोषित आतंकियों ने मुख्य रूप से जम्मू क्षेत्र को निशाना बनाते हुए सैन्य बलों पर ही हमले किए। अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद पहलगाम हमला कश्मीर में हुई पहली बड़ी आतंकी वारदात रही। हिंदुओं को निशाना बनाने के पीछे भी कुत्सित सोच एकदम स्पष्ट रही कि देश में सामाजिक वैमनस्य बढ़े और कश्मीर में सरकार का विकास एजेंडा पटरी से उतरे। भारत ने इसे बखूबी समझा। इसका असर हमले के बाद की प्रतिक्रिया में भी झलका।

भारत ने बहुस्तरीय रणनीति अपनाते हुए खुफिया मोर्चे को और चाकचौबंद किया, जमीनी स्तर पर सुरक्षाकर्मियों की तैनाती बढ़ाई और किसी भी संभावित आतंकी हमले को निस्तेज करने के लिए अभियान तेज किए, विशेष तौर पर अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर। चूंकि जम्मू-कश्मीर में अभी भी सैकड़ों पाकिस्तान समर्थक आतंकी सक्रिय हैं, इसलिए सुरक्षा बलों की चुनौती काफी कड़ी होने वाली है। इस समय भले ही दोनों देशों के बीच युद्धविराम जैसी स्थिति हो, लेकिन पाकिस्तान अपने आतंकी पिट्ठुओं को एक रणनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता रहेगा। भारत ने जिस तरह सिंधु जल समझौते को स्थगित रखने की दृढ़ता दिखाई है, उसके चलते इसकी भरी-पूरी आशंका है कि आतंकी जम्मू-कश्मीर में किसी अहम इन्फ्रास्ट्रक्चर ढांचे को निशाना बनाएं ताकि भारत सरकार कुछ दबाव में आए और कश्मीर का मुद्दा अंतरराष्ट्रीय पटल पर छाए। भारत ने इरादे एकदम स्पष्ट कर दिए हैं कि भविष्य में कोई आतंकी हमला युद्ध के लिए उकसाने वाले कृत्य के रूप में देखा जाएगा। किसी हमले की सूरत में दोनों देश फिर से आमने-सामने आ सकते हैं। इससे अंतरराष्ट्रीय दबाव और संभावित मध्यस्थता प्रयासों के लिए गुंजाइश बनेगी। यह भी एक पहलू है जो पाकिस्तान की नापाक कश्मीर नीति से जुड़ा है। भारत के दृष्टिकोण से पहलगाम हमला केवल एक त्रासदी भर नहीं, बल्कि एक निर्णायक मोड़ रहा। ऐसा मोड़, जिसने भविष्य में किसी भी पाकिस्तानी आतंकी कृत्य से निपटने की उसकी दिशा को निर्धारित किया है।

● **ऋतेन्द्र माथुर**

PRISM® CEMENT

प्रिज़्म® चैम्पियन प्लस

ज़िम्मेदारी मज़बूत और टिकाऊ निर्माण की.

- ज्यादा मज़बूती
- ज्यादा महीन कण
- ज्यादा वर्कबिलिटी
- बेहतरीन निर्माण कार्य
- इको–फ्रेन्डली
- कन्सिसटेंट क्वालिटी
- ज्यादा प्रारम्भिक ताक़त
- ज्यादा बचत

PRISM® प्लस चैम्पियन सीमेंट

दूर की सोच®

Toll free: 1800-572-1444 Email: cement.customerservice@prismjohnson.in

चीन में सत्ता परिवर्तन के संकेत

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को वहां का आजीवन नेता माना जाता रहा है। लेकिन, वहां कुछ ऐसा हो रहा है, जिससे अटकलें लगाई जा रही है कि शी अपने रिटायरमेंट की जमीन तैयार कर रहे हैं। दरअसल, शी जिनपिंग अपनी शक्तियां पार्टी के विभिन्न निकायों के साथ साझा कर रहे हैं। अब उन्होंने सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख निकायों को कुछ अधिकार सौंपने शुरू कर दिए हैं। ऐसा उनके 12 साल से अधिक के शासन में पहली बार हो रहा। शी के इन फैसलों से अटकलें लगाई जा रही हैं कि वे व्यवस्थित रूस से अपनी ताकत यानी सत्ता का हस्तांतरण कर रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि वह अपनी संभावित सेवानिवृत्ति को लेकर अपनी जिम्मेदारियां कम कर रहे हैं। हाल ही में सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने बताया कि सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के शक्तिशाली 24-सदस्यीय राजनीतिक ब्यूरो ने 30 जून को अपनी बैठक में पार्टी के काम करने के लिए लाए गए नए नियमों की समीक्षा की। इसके बाद से शी की सत्ता हस्तांतरण को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। वहीं ये सब तब हो रहा है जब 2027 में अगले 5 साल के लिए सीपीसी का कांग्रेस होने वाला है। इसी समय शी का तीसरा कार्यकाल भी खत्म होगा।

शी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि ये नियम सीपीसी केंद्रीय समिति की निर्णय लेने वाली, विचार-विमर्श करने वाली और को-ऑर्डिनेटिंग संस्थाओं की स्थापना, जिम्मेदारियों और संचालन को और अधिक मानकीकृत करेंगे। शिन्हुआ की रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसी निकायों को प्रमुख कार्यों पर अधिक प्रभावी नेतृत्व और को-ऑर्डिनेशन के साथ काम करना चाहिए तथा प्रमुख कार्यों की योजना बनाने, चर्चा करने और देखरेख करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वहीं, हाल के महीनों में विदेशों में रहने वाले चीन के असंतुष्ट समुदाय में ऐसी चर्चा थी कि कड़े नियंत्रण वाली सीपीसी के भीतर गुप्त रूप से सत्ता संघर्ष चल रहा है। चीन स्थित एक राजनीतिक विश्लेषक ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि इन पार्टी निकायों पर नियम शी की सेवानिवृत्ति की तैयारियों का संकेत दे सकते हैं।

हांगकांग स्थित साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने एक विश्लेषक के हवाले से कहा कि शासन के विभिन्न निकायों को रेगुलेट करने के लिए नियम बनाए जा सकते हैं। क्योंकि यह सत्ता परिवर्तन का महत्वपूर्ण समय है। हालांकि, अन्य विशेषज्ञों ने कहा कि सीपीसी के संस्थापक माओत्से तुंग के बाद सबसे शक्तिशाली नेता माने जाने वाले शी बड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कुछ शक्तियां पार्टी के महत्वपूर्ण प्रभागों को सौंप सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो में चीनी एलिट पॉलिटिक्स और फाइनेंस के विशेषज्ञ विक्टर शिह ने पोस्ट को बताया कि ऐसा लगता है कि शी शायद दिन-प्रतिदिन के विवरणों पर कम ध्यान देते हैं। इसके लिए एक पुलिस तंत्र की आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनकी नीतिगत प्राथमिकताओं को अभी भी निचले स्तर के अधिकारियों द्वारा लागू किया जा रहा है। शी ने रियो डी जेनेरियो में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी भाग नहीं लिया। राष्ट्रपति बनने के बाद यह पहला मौका है जब वे उभरती अर्थव्यवस्थाओं के शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे। चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग शिखर सम्मेलन में चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं।

शी द्वारा पावर ट्रांजिशन का ये कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के टैरिफ युद्ध के बीच आया है। इससे अमेरिका को चीन के 440 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात में बाधा उत्पन्न हुई है। इसके अलावा चीनी अर्थव्यवस्था के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। इसमें निरंतर मंदी के कारण विकास में गिरावट और आर्थिक विकास का मुख्य आधार आवास बाजार का पतन शामिल है।

कॉरपोरेट क्षेत्र पर लगाम लगाने के सरकार के प्रयासों और महामारी के चरम पर चीनी शहरों को बंद करने की असफल शून्य कोविड नीति के कारण संकट और बढ़ गया। इसके परिणामस्वरूप उद्योग और व्यापार पूरी तरह ठप्प हो गए। शी पहले उपराष्ट्रपति थे। 2012 में सीपीसी के महासचिव बनने के बाद से उन्होंने प्रमुख शक्ति केंद्रों-पार्टी, राष्ट्रपति पद और केंद्रीय सैन्य आयोग (सीएमसी) के अध्यक्ष, जो चीनी सशस्त्र बलों का सबसे बड़ा हाईकमान होता है, के रूप में शक्तिशाली सेना में अपनी पकड़ को तेजी से मजबूत की। जैसे ही उन्होंने सत्ता संरचनाओं पर अपनी पकड़ मजबूत की, चीन के सबसे बड़े भ्रष्टाचार विरोधी अभियान को अंजाम दिया। इसमें 10 लाख से अधिक अधिकारियों को दंडित किया गया और दर्जनों शीर्ष जनरलों को हटा दिया गया। शी को पार्टी का कोर लीडर घोषित किया गया। यह पदनाम केवल पार्टी के संस्थापक जेडॉन्ग को दिया गया था। बाद में, राष्ट्रपति के 5 साल के दो कार्यकाल के प्रमुख नियम को विधायिका द्वारा संशोधित किया गया।

● सुश्री नित्या

शी जिनपिंग की जगह लेने 5 नाम रेस में

शी की गैरमौजूदगी और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की चुप्पी ने यह अटकलें तेज कर दी हैं कि अगर शी जिनपिंग की सत्ता वाकई कमजोर हो रही है, तो अगला नेता कौन होगा? इसके लिए ली क्यांग पहले नंबर पर हैं। ली क्यांग को 2023 में चीन का प्रधानमंत्री बनाया गया था। वे लंबे समय से शी जिनपिंग के करीबी माने जाते हैं और शंघाई में कोविड लॉकडाउन के दौरान उनके सख्त प्रशासनिक रवैये ने उन्हें नेतृत्व की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। हाल ही में उन्होंने जी20 जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर चीन का प्रतिनिधित्व भी किया, जिससे यह संकेत मिला कि पार्टी उन्हें अंतरराष्ट्रीय चेहरा बनाने को तैयार है। दूसरे हैं जनरल झांग यूशिया। झांग यूशिया इस वक्त सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के पहले उपाध्यक्ष हैं, यानी जिनपिंग के बाद सबसे ताकतवर शख्स। तीसरे हैं झाओ लेजी। झाओ लेजी, पोलितब्यूरो स्थायी समिति के वरिष्ठ सदस्य हैं और पहले चीन के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के प्रमुख रह चुके हैं। चौथे हैं वांग हुनिंग। वांग हुनिंग को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का थिंक टैंक माना जाता है। पांचवें हैं डिंग श्वेइशियांग। डिंग, जो शी जिनपिंग के चीफ ऑफ स्टाफ रह चुके हैं, उनका राजनीतिक कद सिर्फ जिनपिंग के भरोसे पर खड़ा है।

इश्क कर रहा पतियों को लहूलुहान

इश्क और जंग में सब जायज है, वैसे तो यह एक कहावत है, जिसका अर्थ है कि प्यार और युद्ध में लोग अक्सर अपने लक्ष्यों को पाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। भले ही उसके लिए उन्हें समाज या परिवार के गुस्से का सामना तक क्यों न करना पड़े। कोई भी व्यक्ति अपने प्यार को पाने के लिए झूठ बोल सकता है, छल कर सकता है या किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुंचा सकता है। पिछले कुछ सालों से यही देखने को मिल रहा है और इसका शिकार वो दूल्हे (पति) हो रहे हैं, जो बड़े अरमानों से अपनी दुल्हन (पत्नियों) को उसके घर से विदा कर अपने घर लाते हैं। फिर कुछ समय बाद वो अपने ही घर में नीले ड्रम में पैक मिलते हैं या फिर हनीमून ट्रिप पर पहाड़ों पर मार दिए जाते हैं।

मेरठ की मुस्कान हो या इंदौर की सोनम हो, सभी का अपने पतियों की हत्या करने के पीछे का सिर्फ एक कारण, वो था लव। किसी का शादी से पहले अफेयर चल रहा था तो किसी का शादी के बाद अफेयर शुरू हो गया। इनके इश्क का खामियाजा उन बेगुनाह पतियों को उठाना पड़ा, जो इनके पुराने इश्क से अंजान थे। हाल ही में इंदौर का राजा रघुवंशी मर्डर केस काफी सुर्खियों में रहा। राजा की पत्नी सोनम उसे हनीमून ट्रिप पर ले गई और वहां राजा की हत्या करवा दी। सोनम के मंसूबे को उसके आशिक राज ने अंजाम तक पहुंचाया। कुछ इसी तरह की कहानी मेरठ के सौरभ राजपूत की थी। सौरभ को उसकी पत्नी मुस्कान और उसके आशिक साहिल ने पहले बेरहमी से मारा, फिर नीले ड्रम में सीमेंट से पैक कर दिया। ये तो केवल दो ही मामले हैं, जो काफी सुर्खियों में रहे। ऐसे अनगिनत मामले हैं, जहां पत्नियों के लव के चक्कर में पति अपनी जान गंवा बैठे। क्राइम डेटा और रिपोर्ट्स के अनुसार, पिछले 5 वर्षों में देश के 5 राज्यों में कुल 785 पतियों की हत्या के मामले सामने आए हैं। इन राज्यों में मप्र, उप्र, बिहार, राजस्थान और महाराष्ट्र शामिल हैं। इस आंकड़े ने कई सवाल उठाए हैं। खासकर यह कि आखिर क्यों महिलाएं अपने पतियों की हत्या करने के कदम तक पहुंच रही हैं। इन मामलों में से कुछ बेहद जघन्य घटनाएं रही हैं, जिनमें पत्नियों ने अपने पतियों की हत्या की योजना बनाई और उसे अंजाम तक पहुंचाया भी।

वहीं एक मामला तेलंगाना के कुरनूल का सामने आया है। जहां रिश्तों के नाम पर इतना बड़ा धोखा हुआ, जिसे सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए। ये कहानी एक नवविवाहिता, उसकी मां और एक बैंक कर्मचारी के खौफनाक रिश्तों और षड्यंत्र की है। इस केस में एक बेकसूर युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई, वो भी उसकी शादी के एक महीने के अंदर। और इस खूनी साजिश को रचने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी नई नवेली पत्नी और सास थीं। इस खूनी वारदात के पीछे सिर्फ एक ही मकसद था- लालच, हवस और धोखे से भरा रिश्ता, जिसके लिए एक मासूम नौजवान की जान ले ली गई। इस कहानी में जो सबसे चौंकाने वाली बात है, वो ये कि मां-बेटी दोनों के एक ही शख्स से अवैध संबंध थे। और वो शख्स अब फरार है।

> *इंदौर की सोनम हो या मेरठ की मुस्कान... दोनों ने प्यार के चलते अपने पति की हत्या की। मीडिया में दोनों का मामला भी सुर्खियों में रहा, लेकिन क्या आपको पता है कि पिछले 5 सालों में 785 पतियों को इसी तरह मौत के घाट उतार दिया गया। इनकी हत्या या तो इनकी पत्नी ने खुद की या फिर अपने प्रेमी से करवाई।*

5 राज्यों के आंकड़े

उप्र- उप्र एक ऐसा राज्य है, जहां शादी के बाद अफेयर के चलते सबसे ज्यादा पत्नियों ने अपने पति की हत्या करवाई है या फिर खुद की है। अगर 5 साल के आंकड़ों पर गौर करें तो उप्र में 275 पतियों की हत्या हुई है।

बिहार- दूसरे नंबर पर बिहार है, जहां पतियों की हत्या पत्नियों द्वारा की गई है। बिहार की बीवियां भी अब खूंखार बन गई हैं। 5 साल में बिहार में 186 पतियों की हत्या हुई है।

राजस्थान- राजस्थान में भी पत्नियों के बेवफाई में खेले गए खूनी खेल के मामले कम नहीं हैं। यहां की पत्नियों ने बीते 5 सालों में 138 पतियों की हत्या करवाई है। यहां के ग्रामीण इलाकों में ये घटनाएं सबसे ज्यादा रहीं हैं।

महाराष्ट्र- चौथे नंबर पर महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में बीते 5 साल के दौरान ऐसे 100 मामले सामने आए हैं, जब पत्नियों ने अपने पतियों की हत्या करवाई है या खुद कर दी है।

मप्र- इस लिस्ट में 5वें नंबर पर मप्र का नंबर है। इंदौर का राजा रघुवंशी मर्डर केस काफी सुर्खियों में रहा। मप्र में बीते 5 सालों ऐसे 87 मामले सामने आए हैं, जहां पत्नियों ने अपने पतियों की हत्या करवा दी।

● **ज्योत्सना अनूप यादव**

देश में हर साल 275 पतियों की हत्या

2022 में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट के अनुसार, भारत में होने वाली हत्याओं में प्रेम-संबंध तीसरा सबसे बड़ा कारण है। एक रिसर्च में पता चला है कि भारत में हर साल लगभग 275 पति अपनी पत्नियों द्वारा मारे जाते हैं। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल द लैंसेट में छपी एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में महिलाओं से जुड़ी 60 प्रतिशत हत्याएं उनके वर्तमान या पूर्व साथी द्वारा की जाती हैं और इसका शिकार उनके पति होते हैं। देश में 10 में से एक हत्या प्रेमी, पति या पत्नी द्वारा की जाती है। 2010 से 2014 तक प्रेम संबंधों और रिश्तों से जुड़ी हत्याओं का अनुपात 7 प्रतिशत और 8 प्रतिशत के बीच था। इसके विपरीत 2015 से 2022 तक यह प्रतिशत बढ़कर 10 प्रतिशत और 11 प्रतिशत के बीच हो गया। मतलब ये आंकड़ा एक प्रकार से बढ़ता ही गया, घटा नहीं।

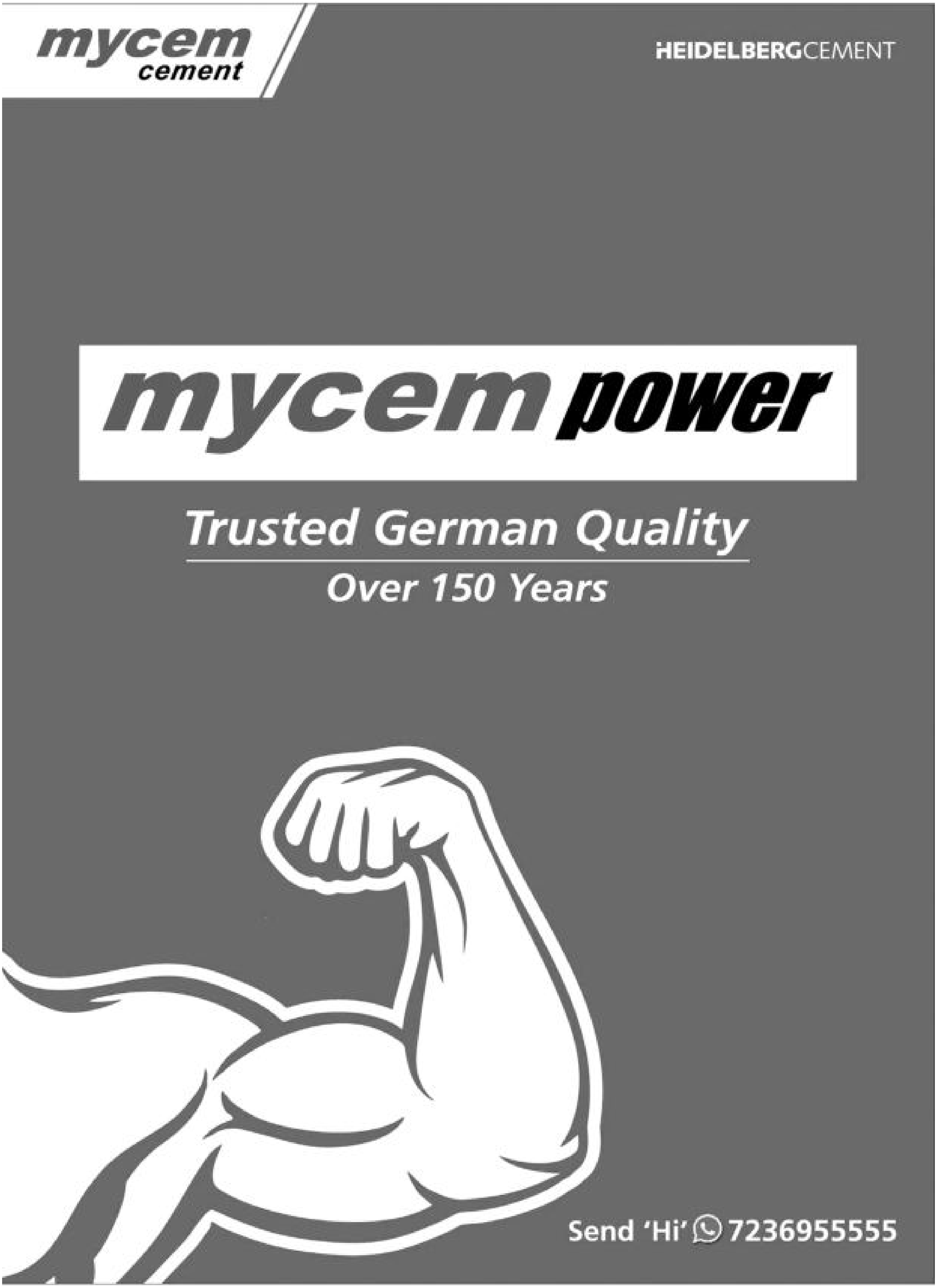
mycem
cement
HEIDELBERGCEMENT
mycem power
Trusted German Quality
Over 150 Years
Send 'Hi' 7236955555

अधर में भारत-बांग्लादेश सीरीज!

यह सर्वविदित है कि भारत और पाकिस्तान के राजनीतिक संबंधों का इतिहास क्षेत्रीय विवादों और कूटनीतिक प्रयासों का एक जटिल मिश्रण रहा है। वर्ष 1947 में ब्रिटिश भारत के विभाजन के बाद से ही दोनों देशों ने संघर्ष और सीमित सहयोग के दौर का अनुभव किया है। मौजूदा समय में तनाव काफी गहरा गया है। वहीं अब दूसरे पड़ोसी बांग्लादेश से भी भारत के संबंध निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। इनका असर खेलों में पड़ने लगा है। असल में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम वर्तमान में इंग्लैंड के दौरे पर पांच टेस्ट मैचों की सीरीज खेली रही है। इस दौरे के बाद उसे सीमित ओवरों की सीरीज के लिए बांग्लादेश के दौरे पर जाना है। जहां दोनों के बीच अगस्त में आईसीसी फ्यूचर टूर प्रोग्राम के तहत तीन वनडे और तीन टी-20 मैचों की सीरीज खेली जानी है। यह सीरीज 17 अगस्त को शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम में शुरू होनी थी। लेकिन पिछले साल अगस्त में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद दोनों देशों के रिश्तों में खटास आने से बीसीसीआई को अभी तक भारत सरकार से इस दौरे के लिए अनुमति नहीं मिल सकी है। ऐसे में सरकार टीम इंडिया को बांग्लादेश जाने की मंजूरी नहीं देती है तो यह सीरीज अधर में लटक सकती है।

गौरतलब है कि भारत को बांग्लादेश दौरे पर 17 अगस्त से तीन वनडे और तीन टी-20 मैच खेलने हैं, लेकिन पिछले साल हुए हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से ही बांग्लादेश में उथल-पुथल की स्थिति बनी हुई है। हिंदू अल्पसंख्यकों पर हुए अत्याचार के कारण लगातार भारत में भी बांग्लादेश के खिलाफ माहौल बना हुआ है। हालांकि इसके बावजूद पिछले साल बांग्लादेश की टीम भारत दौरे पर आई थी, जबकि इस साल फरवरी में चैम्पियंस ट्रॉफी में भी दोनों टीमों की टक्कर हुई थी। मगर कुछ ही दिनों पहले बांग्लादेश सरकार के करीबी एक पूर्व सैन्य अधिकारी ने भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों पर कब्जा करने का बयान देकर तनाव को बढ़ा दिया था जिस पर भारत सरकार ने भी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की थी। मौजूदा राजनीतिक स्थिति को देखते हुए इस दौरे की संभावना कम ही लग रही है। इस बीच बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की ओर से इस दौरे को लेकर बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीसीसीआई के साथ हमारी सकारात्मक चर्चा चल रही है। यह अगस्त या सितंबर में जैसा नहीं है हम इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि हम सीरीज कैसे आयोजित कर सकते हैं और अगर हम अभी इसकी मेजबानी नहीं कर सकते हैं तो हम इसे किसी अन्य संभावित समय पर आयोजित करेंगे। अमीनुल ने कहा कि हालांकि भारत ने औपचारिक रूप से स्थगन का अनुरोध नहीं किया है, लेकिन यह दौरा सरकार की हरी झंडी पर निर्भर करता है।

बांग्लादेश के लिए यह कहना दिलचस्प है कि वे एक नई विंडो की योजना बना रहे हैं। जबकि टीम इंडिया का जनवरी 2026 तक का कार्यक्रम काफी व्यस्त है। उसके ठीक बाद टी-20 विश्वकप 2026 और फिर आईपीएल 2026 है। इसलिए यदि भारत का बांग्लादेश दौरा अगले महीने नहीं होता है तो बीसीबी को आईपीएल 2026 तक इंतजार करना पड़ सकता है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि बांग्लादेश दौरा टीम इंडिया के कैलेंडर का हिस्सा जरूर है लेकिन इस पर अभी तक अंतिम फैसला नहीं हुआ है तो ऐसे में ये संभावना काफी प्रबल है कि मौजूदा हालातों को देखते हुए टीम इंडिया इस दौरे के लिए बांग्लादेश जाए ही नहीं। भारत ने बांग्लादेश में कभी भी टी-20 सीरीज नहीं खेली है। ये ऐसी पहली टी-20 सीरीज होती जब बांग्लादेश घरेलू मैदान पर भारत की द्विपक्षीय श्रृंखला की मेजबानी करता। दोनों टीमों के बीच टी-20 सीरीज 2024 में हुई थी लेकिन तब बांग्लादेश ने भारत का दौरा किया था और मेजबान टीम ने 3-0 से आसान जीत हासिल की थी। टीम इंडिया बांग्लादेश में 2014 के बाद से कोई भी वनडे सीरीज नहीं खेली है। अब विराट कोहली और रोहित शर्मा की वापसी से भारत के पास जीत दर्ज करने और 11 साल के सूखे को खत्म करने का मौका था लेकिन अभी सीरीज पर सस्पेंस बना हुआ है। पिछली बार जब भारत ने बांग्लादेश में तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली थी तो रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम को 1-2 से सीरीज में हार का सामना करना पड़ा था। भारत ने 2014 के बाद से बांग्लादेश में एक दिवसीय सीरीज नहीं जीती है। रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों टी-20 और टेस्ट से संन्यास लेने के बाद एक दिवसीय में वापसी करने के लिए तैयार हैं। तीन मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला 17 अगस्त को मीरपुर में शुरू होनी है लेकिन इस पर अभी दोनों देशों में सहमति नहीं बन पाई है।

● **आशीष नेमा**

भारी पड़ेगा भारत का बहिष्कार

भारतीय क्रिकेट टीम ने आखिरी बार 2008 में एशिया कप के लिए पाकिस्तान का दौरा किया था। उसके बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच कोई द्विपक्षीय क्रिकेट श्रृंखला नहीं खेली गई है। दोनों टीमें केवल आईसीसी और एशिया कप जैसे बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में ही एक-दूसरे के खिलाफ खेली हैं। 2008 के मुंबई हमलों के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया था। तब से दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंध तनावपूर्ण रहे हैं, जिसके कारण द्विपक्षीय क्रिकेट श्रृंखलाएं नहीं हो पाई हैं। वर्तमान में बीसीसीआई ने पहलगाम हमले के बाद आईसीसी से मांग की है कि उन्हें आईसीसी टूर्नामेंट में भी पाकिस्तान के साथ एक ग्रुप में ना रखा जाए। इससे दोनों के बीच क्रिकेट मैच और कम होने की संभावना बढ़ गई है। ऐसे में खेल समीक्षकों का कहना है कि भारत अगर पूरी तरह पाकिस्तान और बांग्लादेश का बहिष्कार कर दे तो ये झटका दोनों क्रिकेट बोर्ड बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट को इससे 220 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो सकता है।

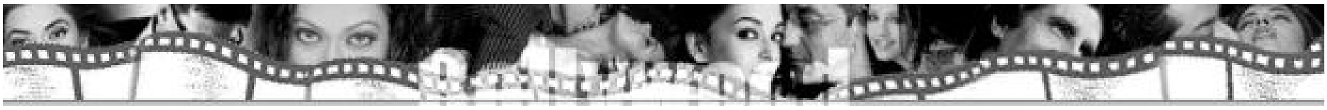

राजेश खन्ना जैसा कोई नहीं...

अभिनेत्री जीनत अमान ने जब खोली सुपरस्टार की पोल

अमृता सिंह के हीरो की सादगी पर हुई थीं फिदा

जीनत अमान ने राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन दोनों के साथ काम किया है। लेकिन दोनों को लेकर उनकी सोच बहुत अलग है। जहां अमिताभ की सादगी और प्रोफेशनल बिहेवियर पर वह फिदा थीं, वहीं राजेश खन्ना की लेट आने की आदत और मनमाने ढंग से वह चिढ़ जाती थी।

जीनत अमान ने अपने दौर में एक से बढ़कर एक हिट और सुपरहिट फिल्मों में काम किया था। अपनी फिल्मों में वह ऐसे रोल निभाती थी कि फिल्में हिट हो जाती थीं। खासतौर पर राज कपूर की ब्लॉकबस्टर में तो वह तहलका ही मचा देती थीं। अपने बेबाक अंदाज के लिए पहचानी जाने वाली जीनत ने अपने एक इंटरव्यू में कुछ ऐसा कह दिया था कि सभी हैरान हो गए थे। उन्होंने अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना को लेकर अपना नजरिया शेयर किया था। 70 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस जीनत अमान ने अपने पुराने को-स्टार्स को लेकर कुछ दिलचस्प बातें शेयर कीं। उन्होंने बताया कि कैसे राजेश खन्ना सेट पर हमेशा देर से आते थे और पूरी शूटिंग उनके टाइम के मुताबिक चलती थी। वहीं दूसरी तरफ, अमिताभ बच्चन को उन्होंने बेहद प्रोफेशनल बताया। सालों पहले दिए एक इंटरव्यू में जीनत अमान ने बताया, राजेश खन्ना पूरी तरह कंट्रोल में रहते थे। सब लोग उन्हें ही फॉलो करते थे। मैं आशिक हूं बहारों का की शूटिंग कर रही थी। शूटिंग काफी लेट शुरू होती थी। वो तय करते थे कि कब आएंगे, कब शूट करेंगे और कब जाएंगे। सेट पर सब कुछ उन्हीं के हिसाब से होता था।

डायरेक्टर-प्रोड्यूसर के एक्टर हैं अमिताभ... *जीनत अमान ने बताया कि उन्होंने राजेश खन्ना से ज्यादा फिल्में अमिताभ बच्चन के साथ की हैं। डॉन फिल्म के दौरान की बात करते हुए उन्होंने कहा, अमिताभ बच्चन बेहद प्रोफेशनल हैं। वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के एक्टर हैं। अमिताभ बच्चन की प्रोफेशनलिज्म की एक मिसाल हाल ही में कल्कि 2898 एडी के डायरेक्टर नाग अश्विन ने दी थी। उन्होंने बताया कि शूटिंग के दौरान बिग बी ने उनसे पूछा, क्या मैं वॉशरूम जा सकता हूं? डायरेक्टर खुद हैरान रह गए और बोले, सर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, आप जो चाहें कर सकते हैं।*

सनी देओल-संजय दत्त पर भारी था इस सुपरस्टार का स्टारडम, घमंड ने डूबो दिया पूरा करियर

मशहूर अभिनेता राजेंद्र कुमार के बेटे कुमार गौरव ने साल 1981 में फिल्म लव स्टोरी से बॉलीवुड में धमाकेदार शुरुआत की और तुरंत ही लोकप्रियता हासिल की थी। उनके पिता राजेंद्र कुमार भी मशहूर अभिनेता और निर्माता थे, जिन्होंने कुमार गौरव के करियर को प्रभावित किया। लव स्टोरी के बाद कुमार गौरव ने तेरी कसम, लवर्स, फूल और नाम जैसी फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें नाम को खास सराहना मिली।

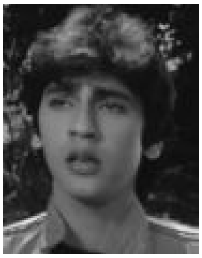

कुमार गौरव ने साल 1981 में लव स्टोरी से बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री करने के बाद भी घमंड में चूर होने के बाद उनका करियर डूब गया। जब कुमार का करियर बुलंदियां छू रहा था, उस वक्त वह उनका स्टारडम उनके सिर चढ़कर बोलने लगा था। वो नई एक्ट्रेसेस के साथ तो काम करना पसंद ही नहीं करते थे। उन्होंने कई फिल्में भी सिर्फ इसलिए रिजेक्ट की थी। क्योंकि उनमें नई एक्ट्रेस को कास्ट किया गया था। बता दें कि इडंस्ट्री के फेमस प्रोड्यूसर दिनेश बंसल ने फिल्म शीरीं-फरहाद के लिए भी कुमार को कास्ट किया था। लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनके साथ इस फिल्म में नई नवेली एक्ट्रेस मंदाकिनी को कास्ट किया जा रहा है तो उन्होंने ये कहकर फिल्म छोड़ दी थी कि मैं मंदाकिनी संग काम नहीं करूंगा। बाद में यही मंदाकिनी फिल्म राम तेरी गंगा मैली के बाद स्टार बन गई और धीरे-धीरे इसी तरह गौरव का करियर बर्बाद हो गया।

अमिताभ की वो शर्त, जिसे अब तक निभा रही हैं जया बच्चन, इसी 1 वजह पर टिकी है शादी

अमिताभ बच्चन और जया बच्चन ने शादी से पहले भी कई हिट फिल्मों में काम किया है। 52 साल बाद भी आज तक दोनों के बीच किसी तकरार की बात सामने नहीं आई है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये शादी आज तक एक शर्त पर टिकी है। इस बात का खुलासा खुद जया ने ही किया था। अभी भी जया अपने परिवार को बहुत तरीके से संभाले हुए हैं और बिग बी भी उनकी बातों की बहुत इज्जत करते हैं।

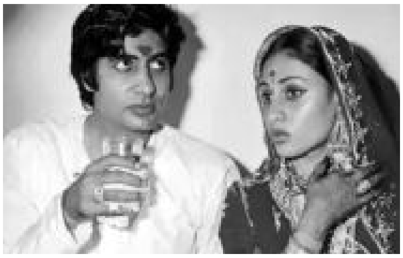

जया बच्चन, अमिताभ बच्चन के स्टार बनने से पहले ही सुपरस्टार बन चुकी थीं। लेकिन फिर भी उन्होंने अमिताभ के साथ काम किया था। करियर चमकाने वाली फिल्म भी जया की वजह से ही मिली थी। साल 1973 में रिलीज हुई फिल्म जंजीर, अमिताभ के करियर में टर्निंग प्वाइंट साबित हुई थी। इस फिल्म में कोई उनके साथ काम नहीं करना चाहता था, जब सिर्फ जया ने उनके साथ काम किया और किस्मत चमका दी थी। अमिताभ और जया की जब शादी हुई थी, उस वक्त बिग बी ने जया के सामने शर्त रखी थी कि वह शादी के बाद कम काम करेंगी। चुनिंदा प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगी और अच्छे लोगों के साथ करेंगी। जया ने भी अमिताभ की बात का मान रखा और इस शर्त को माना। जहां शादी के बाद अमिताभ हिट फिल्मों में काम करते रहे, वहीं जया परिवार और बच्चों को संभालने लगी थी। लेकिन आज दोनों फिल्मों में काम कर रहे हैं।

काश मैं सामग्री विभाग का प्रमुख होता

जब हम छोटे थे तो समझते थे कि सबसे ताकतवर लोग पुलिसवाले होते हैं, फिर बड़े हुए तो लगा कि मंत्री सबसे ताकतवर होते हैं। लेकिन जैसे ही किसी सरकारी या कॉरपोरेट दफ्तर में कदम रखा, सच्चाई की बिजली गिरी- सबसे ताकतवर तो सामग्री विभाग का प्रमुख होता है! यह कोई विभाग नहीं, एक परा-सत्ता है। यहां स्टील, सीमेंट और फर्नीचर नहीं, सत्ता, सुविधा और सब्सिडी का कॉकटेल बनता है। और उसका प्रधान पुजारी होता है-सामग्री प्रमुख। उसकी मंजूरी के बिना एक पेन भी नहीं खरीदा जा सकता, एक कुर्सी नहीं बदली जा सकती और एक फाइल भी नहीं चल सकती-फिजिकली भी और मेंटली भी।

दफ्तर की असली ई-टेंडरिंग तो यही है: कागजों पर लिखी गई ई-टेंडर प्रक्रिया से बड़ा झूठ शायद ही कोई हो। असली टेंडर तो सामग्री प्रमुख की मुस्कान में फिक्स होता है। नियमों की किताबें सिर्फ टेबल की शोभा बढ़ाती हैं, असली नियम तो उस नोटशीट के पीछे छुपे होते हैं जिस पर ठेकेदार का नाम नहीं, नाता लिखा होता है। यदि कोई नया ठेकेदार पूछ बैठे कि सर, प्रक्रिया क्या है?, तो उत्तर आता है-हमारे विभाग में प्रक्रिया नहीं, परंपरा है। इस परंपरा में जो सामग्री प्रमुख का प्रिय हो, वही सप्लाई करता है-ईवन अगर वह रजिस्टर की जगह रसोई का रजिस्टर ले आए।

हर वस्तु में मूल्य नहीं, मार्जिन देखा जाता है: जो लोग समझते हैं कि सामग्री प्रमुख सिर्फ खरीद-फरोख्त करता है, वे परदे के बाहर हैं। असली खेल तो उन वस्तुओं के पीछे छुपे मूल्य-वर्धित प्रस्तावों में होता है। पिछली बार ऑफिस के लिए टेबल खरीदी गई थी, लेकिन साथ में आया पारिवारिक डिनर और दुबई टूर पैकेज। कौन कहेगा कि ये टेबल के साथ फ्री नहीं था?

और फिर सामग्री प्रमुख के सटीक शब्द-हमने केवल कंपनी की गुणवत्ता देखी है, बाकी बातें इत्तेफाक होंगी। काश मुझे भी कोई सामग्री प्रमुख बना देता, तो मैं भी मार्जिन के नाम पर वह सबकुछ ले लेता जो एमआरपी में नहीं लिखा होता।

स्टॉक में सामान नहीं, संबंध जमा होते हैं: जहां बाकी विभागों में स्टॉक रजिस्टर में फाइलें गुम होती हैं, वहीं सामग्री विभाग में फाइलें नहीं, संबंधों का हिसाब-किताब रखा जाता है। कौन ठेकेदार कितने वर्षों से विश्वासपात्र है, किसकी मिठाई सबसे पहले आती है, किसके बिस्कुट में नोट की चॉकलेट भरी होती है-यह सब जानकारी वहां के कम्प्यूटर से नहीं, चाय पिलाने वाले अर्दली से मिलती है। अगर कोई नया ठेकेदार घूस नहीं दे, तो फाइल में टिप्पणी होती है-क्वालिटी अनसर्टिफाइड, अप्रूवल रिक्वायर्ड। लेकिन जो समय से तोहफा पहुंचा दे, उसकी फाइल डायरेक्ट अप्रूव्ड हो जाती है, जैसे कोई अर्जुन बिना युद्ध के ही विजय प्राप्त कर गया हो।

सोचता हूं, काश मैं भी सामग्री प्रमुख होता-तो हर वस्तु की क्वालिटी मैं आंख से नहीं, जेब से तय करता।

ऑफिस की चाय भी उन्हीं की कमीशन वाली होती है: आजकल दफ्तरों में जो टी-बैग से बनी अद्भुत चाय आती है, उसमें स्वाद कम, डील का रस ज्यादा होता है। क्योंकि जिस दिन सामग्री विभाग ने नई चाय सप्लाई कंपनी से गठबंधन किया था, उस दिन से चाय के कप में चीनी कम, चापलूसी ज्यादा घुलने लगी। और जब कोई कहे-सर, ये चाय बड़ी बेस्वाद है, तो सामग्री प्रमुख उत्तर देता है-अरे! तुम तो क्लासिक टेस्ट को समझ ही नहीं सकते।

क्लासिक टेस्ट का मतलब है-जिस कंपनी ने डील के साथ डिनर दिया हो। काश मैं भी ऐसी चाय का अनुबंध करता, जिसमें स्वाद से ज्यादा सुविधा मिलती। फिर मैं भी कहता-एक कप ऑफिस टी, बिना दूध, लेकिन डबल बिल के साथ।

साल दर साल वही कंपनी क्यों जीतती है-ये सवाल मत पूछो: अब ये कोई मामूली संयोग नहीं कि हर बार वही कंपनी टेंडर जीतती है जिसकी मिठाई की डिब्बी सबसे भारी होती है। जब सारे दस्तावेज बराबर हों, तब निर्णय का आधार क्या होता है? उत्तर सीधा है-इमोशनल इंटेलिजेंस। यानी कौन टेंडर फॉर्म के साथ भावनाओं की गठरी लेकर आया। जब कोई ईमानदार कर्मचारी पूछता है-सर, बाकी कंपनियां बेहतर रेट दे रही हैं, तो सामग्री प्रमुख उत्तर देता है-हमें सिर्फ रेट नहीं, रिलेशन देखना होता है। अगर मुझे भी यह निर्णय शक्ति मिल जाती, तो मैं भी हर साल वही कंपनी चुनता जिससे मुझे रिटायरमेंट गिफ्ट समय से पहले मिल जाए।

कुर्सियों से ज्यादा बिछौने बदलते हैं इस विभाग में: जब बाकी लोग पुरानी कुर्सियों पर झख मारते हैं, तब सामग्री प्रमुख के कक्ष में हर छह महीने में नया इंटीरियर होता है। पिछली बार जब नया पंखा आया, तो पर्सनल केबिन में एयर प्यूरिफायर भी गलती से आ गया। और पूछा जाए तो उत्तर होता है-यह कर्मचारियों की सुविधा हेतु टेस्टिंग यूनिट है। टेस्टिंग ऐसी कि घर में भी चलती रहे। काश! मुझे भी ऐसी टेस्टिंग यूनिट मिलती, तो मैं भी कहता-यह लैपटॉप अभी ऑफिस के लिए ट्रायल पर है, तब तक घर ले जाता हूं।

एकमात्र विभाग जहां रद्दी भी राजस्व बन जाती है: पुराने कम्प्यूटर हों, जर्जर कुर्सियां हों या टूटी मेज-बाकी विभागों में ये कबाड़ होती हैं, लेकिन सामग्री विभाग में यह कमाई की संभावनाएं होती हैं। हर स्क्रैप में भी स्कीम होती है। जो सामान 500 रुपए में कबाड़ी को जाए, वह टेंडर के नाम पर सामाजिक संस्थान को दान घोषित कर दिया जाता है-और वहां से चुपचाप उधार चुकता होता है। सोचता हूं, काश मैं भी सामग्री प्रमुख होता, तो कबाड़ के जरिए गोल्डन कबाड़ी युग शुरू कर देता।

निष्कर्ष-सामग्री प्रमुख होना केवल एक पद नहीं, एक जीवनदर्शन है: जब आप सामग्री प्रमुख होते हैं, तो आपको भगवान से प्रार्थना नहीं करनी पड़ती-हे ईश्वर, सब कुछ दे देना। क्योंकि आपके पास पहले से ही वह विभाग होता है जो सब कुछ खरीद सकता है। आपके पास टेंडर की तलवार होती है, आपूर्ति की ढाल होती है और आदेश की गदा होती है। आपका निर्णय ही बजट होता है और आपकी मुस्कान ही अनुबंध। इसलिए जब मैं ऑफिस की टूटी कुर्सी पर बैठा सिस्टम हैंग होने की प्रतीक्षा करता हूं, तो दिल से एक ही आवाज आती है-काश मैं भी सामग्री विभाग का प्रमुख होता।

● **डॉ. शैलेश शुक्ला**

ANU SALES CORPORATION

We Deal in Pathology & Medical Equipment

Address : M-179, Gautam Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023

9329556524, 9329556530 Email : ascbhopal@gmail.com

मौसमी बीमारियों से बचें

आसपास सफाई रखें...

- पानी जमा न होने दें, क्योंकि यह मच्छरों के प्रजनन के लिए एक आदर्श स्थान है।
- कूड़ा-कचरा नियमित रूप से हटाएँ।
- नालियों और गटरों को साफ रखें।

पानी उबालकर पिएं...

- दूषित पानी पीने से हैजा, टाइफाइड और आंत्रशोथ जैसी बीमारियाँ हो सकती हैं।
- सुनिश्चित करें कि आप जो भी पानी पीते हैं, वह शुद्ध या उबला हुआ हो।

स्वस्थ भोजन खाएं...

- मौसमी फल और सब्जियां खाएं।
- बाहर का खाना खाने से बचें।
- साफ-सुथरे हाथों से खाना खाएं।

पर्याप्त आराम करें...

- पर्याप्त नींद लें और तनाव से बचें।
- बीमार होने पर, डॉक्टर से सलाह लें।
- इन उपायों का पालन करके, आप सावन के महीने में मौसमी बीमारियों से बच सकते हैं।

मच्छरों से बचाव करें...

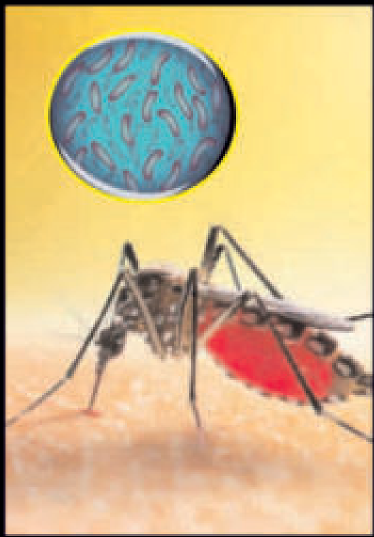

- फुल बाजू के कपड़े पहनें।
- मच्छर भगाने वाली क्रीम या लोशन का उपयोग करें।
- मच्छरदानी का उपयोग करें।
- अपने घर के आसपास पानी जमा न होने दें।

जनहित में जारी

फारूकी ब्रदर्स, इंदौर (मध्यप्रदेश)